



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2015/फाल्गुन 18, 1936

No. 58]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2015/PHALGUNA 18, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2015

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और मलेशिया से 304 सीरीज की स्टेनलेस स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

फा. सं. 14/30/2013-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसके सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

1. यतः, मैसर्स जिन्दल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, नई दिल्ली (जिसे एतदपश्चात आवेदक कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और मलेशिया (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसटीएम ग्रेड 304 की स्टेनलेस स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के सभी रूपभेदों (वैरिएण्ट्स) अधोलिखित विवरण के अनुसार, (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के तथाकथित पाटन का आरोप लगाते हुए एक आवेदन पत्र, अधिनियम और नियमावली के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष दायर किया है और संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के लिए जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया है।

2. और यतः, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर कथित पाटन की मौजूदगी उसकी मात्रा और उसके प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की एक ऐसी राशि की सिफारिश करने, जो यदि उद्बुद्ध की गई तो, घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 11 मार्च, 2014 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की ।

क. प्रक्रिया

3. प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त जांच की शुरुआत की सार्वजनिक सूचना की अधिसूचना जारी करने के पश्चात इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है।

- (i) इस पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के अनुरोध सहित घरेलू उद्योग से प्राप्त आवेदन पत्र के बारे में प्राधिकारी ने नियम 5 के उप-नियम 5 के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के राजदूतावासों की इसकी अधिसूचना प्रेषित की। इस आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में कोरिया की सरकार को भी कोरिया गणराज्य और भारत के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) के अनुच्छेद 2.14 के प्रावधानों के अनुसार इसके राजदूतावास के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई।
- (ii) इस जांच की शुरुआत के बारे में संबद्ध देशों के नई दिल्ली स्थित राजदूतावासों को भी नियम 6(2) के अनुसार सूचित किया गया।
- (iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 11 मार्च, 2014 की जांच शुरुआत अधिसूचना की प्रतियां, उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत में संबद्ध देशों के राजदूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग के प्रेषित की। इस जांच के पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे प्रश्नावली प्रत्युत्तर भेजें और विहित समय सीमा के अंतर्गत अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराएं। निर्यातकों को प्रेषित किए गए पत्र, याचिका और प्रश्नावलियों की प्रतियां संबद्ध देशों के राजदूतावासों को भी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गई कि वे संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दे कि वे प्रश्नावली का प्रत्युत्तर निश्चित समय-सीमा के अंदर दें।
- (iv) घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका के अगोपनीय पाठ की प्रति प्रमुख नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और राजदूतावासों को प्रेषित की गई।
- (v) संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना प्रदान करने के लिए निर्यातक प्रश्नावलियां प्रेषित की गई।
 1. मैसर्स ताइयुआन आयरन एंड स्टील (ग्रुप) कंपनी, लिमिटेड, चीन
 2. मैसर्स लिआनझांग स्टेनलेस कारपोरेशन, चीन
 3. मैसर्स बाओस्टील टावर, चीन
 4. मैसर्स जिउ कुआन आयरन एंड स्टील (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड, चीन
 5. झान्जियांगंग पोहांग स्टेनलेस स्टील कंपनी, लिमिटेड, चीन
 6. पोस्को, कोरिया
 7. बाहस स्टेनलेस, मलेशिया
- (vi) चीन जनवादी गणराज्य, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश होने के कारण, प्राधिकारी ने चीन जनगण के ज्ञात निर्यातकों को नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में यथा-उल्लिखित आवश्यक सूचना/साक्ष्य प्रस्तुत करने की सूचना दी जिससे प्राधिकारी यह विचार करने में सक्षम हो सके कि क्या ऐसे सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जा सकता है जो यह प्रदर्शित कर सके कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के अंतर्गत कार्य करते हैं।
- (vii) संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का निर्यात करने वाले निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया :
 - (i) मैसर्स लिआनझांग स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन, चीन
 - (ii) मैसर्स बाहरन स्टेनलेस, मलेशिया
 - (iii) मैसर्स सेंचुरी स्टील, पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

- (viii) मैसर्स पोस्को, कोरिया; मैसर्स हुंडई, कोरिया और मैसर्स हयोउसंग, कोरिया ने घरेलू उद्योग के दावों का विभिन्न आधार पर विरोध करते हुए संयुक्त क्षति प्रस्तुतिकरण दायर किया है।
- (ix) भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और उपभोक्ताओं को, नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना प्रेषित करने के लिए प्रश्नावलियां भेजीं :

1. रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, गांधीधाम
2. संगीता मेटल (इंडिया), मुंबई
3. भंडारी फ्वाइलस एंड ट्यूब्स लिमिटेड, देवास (मध्य प्रदेश)
4. रमानी स्टील हाउस, मुंबई
5. प्रकाश स्टीलएज लिमिटेड, नवी मुंबई, महाराष्ट्र
6. निशांत इनफिन्न प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई
7. राजेन्द्रा मैकेनिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ईस्ट मुंबई
8. एसी स्टील ग्रुप, मुंबई
9. फीनिक्स फ्वाइलस प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात
10. क्वालिटी फ्वाइलस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा
11. डामेट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र
12. रेमी इडेल्स्टाहल ट्यूबुलर्स लिमिटेड, मुंबई
13. प्रोसेस प्लांट एंड मशीनरी एसोसिएशन आफ इंडिया, मुंबई
14. स्टेनलेस स्टील एक्सपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, दिल्ली
15. आल इंडिया स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आफ इंडिया, मुंबई
16. दि तमिलनाडु स्टेनलेस स्टील मर्चेन्ट्स एंड मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, चेन्नई

- (x) संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने अपना प्रत्युत्तर दायर किया :

1. रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड
2. भंडारी फ्वाइलस एंड ट्यूब्स लिमिटेड
3. हिन्दुस्तान इनाक्स लिमिटेड
4. जेएनबी स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
5. कन्सारा पोपटलाल तिभुवनदास मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
6. संतोष स्टील इंडस्ट्रीज
7. शाल्को इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
8. शुभलक्ष्मी मेटल्स एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
9. एसएनबी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
10. सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
11. सनराइज स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड

12. वरुण फवाइल्स लिमिटेड
 13. सनसिटी शीट्स प्राइवेट लिमिटेड
 14. नवगढ़ फासेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
- (xi) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से अनुरोध किया गया कि वह विगत तीन वर्षों और जांच की अवधि के दौरान हुए संबद्ध वस्तु के आयातों का विवरण प्रदान कराए। याचिकाकर्ता ने भी आईबीआईएस से प्राप्त आयात आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। आंकड़ों के दोनों स्रोतों की जांच की गई और उनका उपयुक्त पाई गई सीमा तक प्रयोग किया गया है।
 - (xii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण करने के लिए एक खुली सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया।
 - (xiii) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की इष्टतम उत्पादन और उसे बनाने तथा उसकी बिक्री करने की लागत का निर्धारण सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर किया गया जिससे यह सुनिश्चयन किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
 - (xiv) विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के संबंध में गोपनीयता के दावों की जांच की गई है। वह सूचना, जो स्वभावतः गोपनीय है या जिसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराया गया है तथा साथ में उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत किया गया है, उसे गोपनीय रूप में माना गया। इस अंतिम जांच परिणाम में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और प्राधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत उसे वैसा ही माना गया है।
 - (xv) यह जांच अप्रैल, 2012 – जून, 2013 (जांच की अवधि) के लिए की गई। तथापि, जांच में वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा जांच की अवधि के दौरान हुई क्षति को भी शामिल किया गया है।
 - (xvi) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के विचार मौखिक रूप से सुनने के लिए दिनांक 09.12.2014 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया जिसमें हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हितबद्ध पक्षकारों से कहा गया कि वे लिखित प्रस्तुतिकरण और प्रत्युक्तियां दायर करें। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतिकरणों और प्रत्युक्तियों पर इस जांच परिणाम में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
 - (xvii) घरेलू उद्योग तथा निर्यातकों के आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक स्थल सत्यापन किया गया।
 - (xviii) पूर्वोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इस जांच परिणाम के लिए आवश्यक समझे गए तथ्यों/आधारों का हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 25 फरवरी, 2015 को प्रकटन किया गया और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर इन अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
 - (xix) प्राधिकारी ने जांच की अवधि (अप्रैल 2012- जून, 2013 तक की) के दौरान के लिए भारित औसत विनिमय दर 54.69 रुपए प्रति अमरीकी डालर के रूप में मानी है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरूआत अधिसूचना में अधिसूचित विचाराधीन उत्पाद "हाट रोल आस्टीनिटिक स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स; चाहे वे आयताकार आकृति के प्लेट्स, शीट्स या क्वाइल्स (हाट रोलड एनील्ड और पिकल्ड या ब्लैक), 304 या 304एच या 304एल या 304एन या 304एलएन या ईएन1.4311, ईएन 1.4301, ईएन 1.4307 या एक्स 5सीआरएनआई 1810 या एक्स 04सीआर 19एनआई9, के ग्रेड के या उसके समकक्ष यूएनएस, डीआईएन, जेआईएस, बीआईएस, ईएन आदि किसी अन्य मानक ग्रेड के हों या न हों, चाहे वह नम्बर वन या ब्लैक फिनिश के हो या न हों; चाहे वह क्वालिटी प्राइम या नान प्राइम के हों या न हों; चाहे उनकी एज (धार) स्थिति मिल एंज या ट्रिम एंज की हो या न हो, जिनकी मोटाई क्वाइल्स में 1.2 एमएम से 10.5 एमएम की रेंज की हो और प्लेट्स या शीट्स की मोटाई 3 एमएम से 105 एमएम की हो; 1650 एमएम तक की सभी चौड़ाई वाले, क्वाइल्स में 10000 मीटर तक की सभी लंबाई और प्लेट्स में 10 मीटर तक की लंबाई वाले उत्पाद" हैं।

5. संबद्ध वस्तु का प्रयोग प्रासेस उपकरणों, रि-रोलिंग, रिएक्टर वेसेल्स, सामग्री प्रहस्तन उपकरणों, रेलवेज, पाइप्स और ट्यूब, आटोमेटिक संघटकों, रोलड एवं फार्म्ड सेक्सनों, आर्किटेक्चर, भवन एवं विनिर्माण, औद्योगिक फेब्रिकेशनों और पावर सेक्टर आदि के लिए किया जाता है।

6. इस उत्पाद को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अध्याय 72 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची के सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या 7219 और 7210 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। उत्पाद विवरण सभी परिस्थितियों में अभिभावी रहेगा।

7. आवेदक ने दावा किया है उनके द्वारा विनिर्मित उत्पाद तथा संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ऐसा भारी अंतर नहीं है जिसका कीमत, उपयोग, गुणवत्ता आदि पर कोई प्रभाव हो। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि याचिकाकर्ता और संबद्ध देश के निर्यातकों के बीच उत्पादन प्रक्रिया में भी कोई वास्तविक अंतर नहीं है। इसलिए, आयातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु दोनों नियमावली के निबंधनों के आशय से अंतर्गत "समान वस्तुएं" हैं।

ख.1 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. मैसर्स पोस्को, कोरिया गणराज्य; मैसर्स ह्युन्दई कारपोरेशन, कोरिया आरपी; मैसर्स ह्योसंग कारपोरेशन कोरिया आरपी, मैसर्स एक्रिनाक्स, बाहुरू स्टेनलेस मलेशिया; मैसर्स सेंचुरी स्टील सिंगापुर, मैसर्स लिस्को, चीन और भारत में आयातकों को शामिल करते हुए हितबद्ध पक्षकारों ने इस विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध वस्तु के दायरे के संबंध में किए गए अपने प्रस्तुतिकरणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित तर्क दिए हैं :

- यह कि इस जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद या तो सर्वसम होना चाहिए या तुलनात्मक के लिए सभी तरह से कम से कम समान होना चाहिए। इस संबंध में, जहां कोई उत्पाद सर्वसम या समान घरेलू उत्पाद नहीं है, वहां जांच में संगत उत्पाद लाइन का अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए और इसके दायरे को भी संकीर्ण बना दिया जाना चाहिए।
- यह कि याचिकाकर्ता के अभिनव सूचीपत्र में दर्शाए गए उत्पाद आयामों के अनुसार वे हिसार में "न्यूनतम 2.8 एमएम की मोटाई की हाट रोलड क्वाइल और एचआरएपी/क्वाइल का तथा ओडिशा संयंत्र में न्यूनतम 2 एमएम की मोटाई के हाट रोलड क्वाइल्स तथा न्यूनतम 1.4 एमएम की मोटाई के एचआरएपी क्वाइल" का उत्पादन करते हैं। ओडिशा संयंत्र अभी भी रैम्प-अप की स्थिति में है और इतनी कम मोटाई का उत्पादन करने में अक्षम है। इसलिए 2.0 एमएम से कम की मोटाई के एसटीएस एचआर 304 को इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- 2.0 एमएम से कम की मोटाई के और भारतीय ग्राहकों द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता मानकों एवं विनिर्देशनों के लिए अर्ह एसटीएस एचआर 304 का विनिर्माण करने की घरेलू उत्पादकों की अक्षमता के कारण अनुप्रवाही उपभोक्ता उद्योगों के लिए इसका आयात करना अनिवार्य हो जाता है।
- यह कि एनीलिंग और पिकलिंग नामक प्रक्रियाएं कोल्ड रोलड प्रासेस में शामिल प्रक्रियाएं हैं जिनमें हाटरोलिंग कार्य में एनीलिंग और पिकलिंग प्रक्रिया शामिल नहीं है। हाट रोलिंग और कोल्डरोलिंग दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में एनीलड और पिकलड उत्पादों को शामिल करने से दो अलग-अलग प्रक्रियाओं और उत्पादों का अतिच्छादन होगा। इसलिए प्राधिकारी को चाहिए कि वे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से एनीलड और पिकलड उत्पादों को अपवर्जित कर दें जिससे कि विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में स्पष्ट गंभीर अशक्तता दूर हो सके।
- यह कि चूंकि इस विचाराधीन उत्पाद में प्राइम और नॉन-प्राइम दोनों ही उत्पादों को शामिल किया गया है इसलिए पाटन एवं क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए उचित तुलना करने हेतु समुचित समायोजन किया जाना चाहिए।
- यह कि याचिकाकर्ता यह दावा करता है कि उन्होंने हिसार संयंत्र से 1270 एमएम तक की चौड़ाई के उत्पाद का उत्पादन और उसकी आपूर्ति की है और ओडिशा संयंत्र से 1650 एमएम तक की सुविधाएं भी विकसित की है, तथापि, अपने ओडिशा संयंत्र में केवल 1625 एमएम तक के उत्पादों का ही उत्पादन किया है। अतः, चौड़ाई को इस उत्पाद की परिभाषा करते समय याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित स्तर तक ही रखा जाना चाहिए जो किसी भी हाल में 1625 एमएम से अधिक नहीं है।
- यह कि याचिकाकर्ता सामान्यतः मिल एंज में 1000 एमएम, 1250 एमएम और 1500 एमएम तक की चौड़ाई के क्वाइल्स बना रहा है और यदि किसी ग्राहक को 400 एमएम, 405 एमएम, 425 एमएम, 485 एमएम, 550 एमएम, 585 एमएम, 600 एमएम, 620 एमएम, 650 एमएम, 720 एमएम, 750 एमएम, 780 एमएम आदि

(सामान्यतः 1000 एमएम से कम एमएम के) क्वाइल्स चाहिए तो याचिकाकर्ता उसे स्लिट एज देता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता 1000 एमएम से कम की चौड़ाई के मिल एज की संबद्ध वस्तु की आपूर्ति नहीं करता है। इसके विपरीत, संबद्ध देशों के उत्पादकगण मिल एज में भी सभी तरह की चौड़ाई जैसे 400 एमएम, 405 एमएम, 425 एमएम, 485 एमएम, 550 एमएम, 585 एमएम, 600 एमएम, 620 एमएम, 650 एमएम, 720 एमएम, 750 एमएम, 780 एमएम के क्वाइल्स प्रदान करा रहे हैं। अतः, कम चौड़ाई के उत्पाद बनाने की याचिकाकर्ता की उत्पादउन प्रक्रिया चीन के हुआदी, डिंगाजिन, रूइशियान, जिस्को, बाओशान, जुआनझिंग आदि विनिर्माताओं की विनिर्माण प्रक्रिया से पूर्णतया भिन्न हैं और विचाराधीन उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद में 1000 एमएम के कम के मिल एज को शामिल करने के लिए परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा उसका उत्पादन नहीं किया जा रहा है।

- यह कि याचिकाकर्ता ने 10000 मीटर तक की अधिकतम लंबाई के कॉइल का दावा किया है और विचाराधीन उत्पाद में 10,000 मीटर तक की लंबाई के कॉइल को शामिल किया है। यह तर्कसंगत नहीं है। 1650 एमएम की चौड़ाई और 2 एमएम की मोटाई तथा 10000 मीटर लंबे कॉइल का वजन लगभग 262 टन होना चाहिए। तथापि, विश्व में कोई भी कंपनी 40 टन से अधिक के वजन की कॉइल का उत्पादन नहीं कर सकती है। बाजार सूचना के अनुसार, संबद्ध देशों में से किसी भी देश से 1000 मीटर से अधिक की कोई सामग्री भारत नहीं आई है। अतः, 10,000 मीटर तक की कॉइल को शामिल करना संदेहास्पद प्रतीत होता है और उसका निर्धारण बाजार की वास्तविकता एवं प्रथाओं के अनुरूप किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा के वास्तविक पहलू को सुनिश्चित किया जा सके।

9. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु के दायरे के संबंध में इन सामान्य तर्कों के अलावा मैसर्स पोस्को कोरिया ने अपने प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित तर्क भी दिए हैं :

- यह कि कोरिया से निर्यातित एचआर स्टेनलेस स्टील कॉइल्स और शीट्स याचिकाकर्ता के उत्पादों के समान उत्पाद के दायरे से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में पास्को ने समान वस्तु का निर्धारण करने के मुद्दे के संबंध में ईसी-एस्वेस्टास में अपीलीय निकाय के प्रेक्षकों को उद्धृत किया है जो निम्नवत है :

"बार्डर टैक्स एडजस्टमेंट पर वर्किंग पार्टी की रिपोर्ट में एक सेमी 'समानता' का विश्लेषण करने का अधिगम बताया गया है जो अनुकरण की गई है और जिसका कई पैनेलों और अपीलीय निकाय द्वारा विकास किया गया है। इस प्रक्रिया, मुख्यतः, में 'समानता' का विश्लेषण करने के लिए चार मापदंडों को शामिल किया गया है; (i) उत्पाद के गुणधर्म, प्रकृति और उसकी गुणवत्ता; (ii) उत्पाद के अंतिम प्रयोग; (iii) उत्पाद के संबंध में उपभोक्ताओं की रुचि और स्वभाव – अधिक व्यापक रूप से पारिभाषिक उपभोक्ताओं के अवबोधन और व्यवहार – और (iv) उत्पादों का प्रशुल्क वर्गीकरण।

- यह कि अपीलीय निकाय द्वारा ऊपर यथानिर्धारित चार सामान्य मानदंडों पर विचार करते हुए प्राधिकारी को न केवल प्रशुल्क वर्गीकरण में उल्लिखित निर्वधनों के अनुसार समान उत्पाद की जांच करनी चाहिए बल्कि इसकी गुणवत्ता, अंतिम प्रयोग और उपभोक्ताओं की अधिमान्यता पर भी विचार करना चाहिए जो अधिक महत्वपूर्ण है। यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु तथा कोरिया से आयातित वस्तु के बीच उत्पाद की गुणवत्ता, इसके अंतिम प्रयोग और एसटीएस एचआर 304 की उपभोक्ताओं की अधिमान्यता के संबंध में भारी अंतर है। यद्यपि संबंधित उत्पाद को समान मानदंडों में वर्गीकृत किया जाता है परंतु अंतिम प्रयोग के लिए गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के हितों एवं बाजार लक्ष्य के आधार पर इसमें अंतर है। विशिष्टीकृत ग्राहक समूहों और बाजार के साथ, पास्को और याचिकाकर्ता के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके बीच कोई प्रतिस्पर्धा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि गैर-प्रतिस्पर्धी संबंधों की भी व्याख्या नहीं की जा सकती है क्योंकि उनमें से एक गैर-प्रतिस्थानीय प्रकृति का है। प्रतिस्पर्धात्मक और स्थानापन्नता के अभाव में प्राधिकारी को कोरिया मूल के एसटीएस एचआर 304 का इस जांच से अपवर्जन कर देना चाहिए।
- यह कि याचिकाकर्ता के प्रकथन के विपरीत, पास्को के उत्पाद तथा याचिकाकर्ता के उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया के बीच भारी अंतर है। जैसाकि विश्व स्टेनलेस स्टील बाजार में यह सुज्ञात है कि पास्को 2.0 एमएम से कम की मोटाई के कुछ विशेष उत्पादों का उत्पादन करने के लिए अपनी उत्पादन प्रक्रिया में 'स्ट्रिप कास्टिंग' विधि जिसे 'पोस्ट्रिप' नाम से जाना जाता है, का प्रयोग करता है, यह प्रक्रिया पास्को को अधिक पतले कॉइल्स एवं प्लेटों के रूप में भिन्न विनिर्देशनों वाले कॉइल्स एवं प्लेटों का विनिर्माण करने के योग्य बनाती है। यह अंतर इस तथ्य के मद्देनजर और भी अधिक स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता 2.0 एमएम से कम की मोटाई के उत्पादों को विनिर्माण नहीं करता है।

- यह कि पास्को की "स्ट्रिप कास्टिंग" समग्र उत्पादन प्रक्रिया को कम कर देती है और इसमें कई परम्परागत उत्पादन प्रक्रिया जिसे याचिकाकर्ता द्वारा अपनाया जाता है, में पहले 'स्लैब्स' का उत्पादन किया जाता है और फिर उनकी हाट रोलिंग की जाती है, परंतु स्ट्रिप कास्टिंग मैथड में 'स्लैब्स' के उत्पादन के छोड़ दिया जाता है और कास्टिंग से लेकर हाटरोलिंग तक की सभी प्रक्रियाएं लगातार एक साथ की जाती हैं।
- यह कि इस प्रक्रिया में कमी का आशय यह नहीं है कि उत्पादन की प्रक्रिया में केवल कमी ही हुई है। स्ट्रिप कास्टिंग की शुरुआत करने से पास्को "पोस्ट्रिप" का विनिर्माण करने में सफल रहा है, जो ग्राहकों की अधिक आधुनिक जरूरतों को संतुष्ट करता है और इससे इसके उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है जिसे विश्व स्टेनलेस स्टील बाजार में एक भिन्न उत्पाद के रूप में माना जाता है।
- यह कि इस जांच में यह विचार किया जाना चाहिए कि पोस्को की उत्पादन प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है जिसे विश्व भर के इस्पात उद्योग में "स्ट्रिप कास्टिंग प्रक्रिया" के रूप में माना जाता है, जिससे यह एसटीएस एचआर 304 के उत्पाद का उत्पादन करने में सक्षम होता है जो उपभोक्ताओं की अत्याधुनिक जरूरतों तथा बेहतर गुणवत्ता की पूर्ति करता है।

ख.2 घरेलू उद्योग के विचार

10. घरेलू उद्योग ने अपने विभिन्न प्रस्तुतिकरणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित तर्क दिया है :

- यह कि इससे पहले रक्षोपाय महानिदेशक ने अधिसूचना संख्या जीएसआरडी 22011/06/2012 के तहत इस उत्पाद के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की है, जिसमें महानिदेशक (रक्षोपाय) ने एक विस्तृत जांच के उपरांत इस विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित दायरे पर विचार किया था।

स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद (1625 एमएम की अधिकतम चौड़ाई तक), जिनमें उन सभी आस्टीनिटिक ग्रेड के 6 प्रतिशत न्यूनतम निकेल (एनआई) तत्व शामिल हो, और जिनमें मालिब्डेनम टाइटेनियम आदि जैसे अन्य अलायिंग तत्वों की मौजूदगी युक्त या उसके बिना क्रोमियम अनिवार्यतः मौजूद हो।"

- यह कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूरोपियन यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान और यूएसए से आयातित इस उत्पाद पर अधिसूचना सं. 14/12/2010-डीजीएडी के तहत पाटनरोधी शुल्क की इससे पूर्व भी संस्तुति की है, जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विस्तृत जांच के उपरांत विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर निम्नवत विचार किया है :

"एसटीएस ग्रेड 304 के सभी रूपांतरों युक्त 1250 एमएम तक की चौड़ाई (मिल एंज के लिए + 20 एमएम की चौड़ाई सहिष्णुता और ट्रिम्ड एंज के लिए + 5 एमएम की चौड़ाई सहिष्णुता) के स्टेनलेस स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद जिनमें अन्य मापदंडों जैसे यूएनएस, आईएस, चाइनीज डीआईएन, जेआईएस, बीआईएस, ईएन आदि समकक्ष विनिर्देशनों के उत्पाद शामिल हैं।"

- यह कि संपूर्ण विश्व में अधिकांशतः समन्वित उत्पादक एचआर उत्पादों की रोलिंग करके एचआर उत्पादों और सीआर उत्पादों का उत्पादन करते हैं। संपूर्ण विश्व में उत्पादकगण एक ही संयंत्र/विनिर्माण सुविधा पर विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं और अंतर्निमेय रूप से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादकगण पहले "अधिक चौड़ाई" के कॉइल्स का उत्पादन करते हैं और फिर उन्हें "अंतिम उपभोक्ता" द्वारा अपेक्षित आकार की "कम चौड़ाई" में (उनके द्वारा या स्लिटर्स या रि-रोलर्स द्वारा) ट्रिम/स्लिट किया जा सकता है। कॉइल्स के विपरीत, उत्पादकगण अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित आकार की प्लेटों का उत्पादन करते हैं।
- यह कि ग्राहकों की तीन श्रेणियां होती हैं जिनको एचआर स्टील के उत्पादक अपने उत्पाद की बिक्री करते हैं :
 - (i) अंतिम उपभोक्ता : एचआर प्लेटों, एचआर कॉइल्स, सीआर प्लेटों, शीट्स, स्ट्रिप्स के उपभोक्ता यह इस विचाराधीन उत्पाद के संभावित उपभोक्ता होते हैं। इन अंतिम उपभोक्ताओं को अपने अंतिम अनुप्रयोगों के लिए विशिष्ट उत्पाद प्रकार की जरूरत होती है और वे सामान्यतः वांछित आयामों के उत्पादों की खरीद करते हैं।
 - (ii) रि-रोलर्स और स्लिटर्स (सेवा केंद्रों सहित) : वे घरेलू अथवा विदेशी उत्पादकों से एचआर कॉइल्स की खरीद करते हैं और फिर उनकी कॉइलों की वांछित चौड़ाई (कमतर) और मोटाई में प्रशीतित स्थिति के अंतर्गत रि-रोलिंग करते हैं। उनका अंतिम उत्पाद संकीर्णतर चौड़ाई और तनुतर मोटाई के कोल्ड रोल्ड कॉइल्स होते हैं। कुछ सेवा केंद्र हैं जो इन एचआर उत्पादों की स्लिटिंग करते हैं। वे एचआर और सीआर दोनों ही कॉइल्स की वांछित चौड़ाई में स्लिटिंग करने में सक्षम होते हैं।

- (iii) व्यापारी : यह इस विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता नहीं होते हैं। वे इस विचाराधीन उत्पाद की खरीद करते हैं और उनकी बिक्री करते हैं। उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना और धनोपार्जन करना होता है।
- यह कि स्लिट्स और रि-रोलर्स अधिक चौड़ाई के चौड़े उत्पादों की खरीद करते हैं, स्लिट करते हैं और फिर उसे अंतिम उपभोक्ताओं या रि-रोलरों को बेच देते हैं।
 - यह कि इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे में कॉइल्स शीट्स और प्लेट्स शामिल हैं। शीट्स/प्लेट्स तथा कॉइल्स इस विचाराधीन उत्पाद के दो भिन्न प्ररूप होते हैं। शीट्स और प्लेट्स में केवल मोटाई का अंतर होता है। यदि मोटाई 5 एमएम से कम होती है तो उसे सामान्यतः शीट के नाम से जाना जाता है। यदि मोटाई उससे अधिक होती है तो उसे प्लेट के नाम से जाना जाता है। शीट्स/प्लेट्स और कॉइल्स का आयात संबद्ध देशों से किया गया है और घरेलू उत्पादकों द्वारा उसकी आपूर्ति की गई है।
 - यह कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस उत्पाद के संबंध में इससे पूर्व की जांच की है, जिसमें विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत कॉइल्स और प्लेटों/शीटों दोनों को शामिल किया गया है (इस पाटनरोधी जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा 1250 एमएम तक की चौड़ाई (मिल एंज के लिए + 20 एमएम की चौड़ाई सहिष्णुता और ट्रिम्ड एंन के लिए + 5 एमएम की चौड़ाई सहिष्णुता) के स्टेनलेस स्टील के हाट रोलड फ्लैट उत्पाद जिनमें अन्य मापदंडों जैसे यूएनएस, आईएस, चाइनीज डीआईएन, जेआईएस, बीआईएस, ईएन आदि समकक्ष विनिर्देशनों के उत्पाद) था। किसी भी उत्पाद की खपत कॉइल रूप में नहीं की जाती है। प्रत्येक कॉइल को पहले काटा जाता है और फिर उसकी खपत की जाती है।
 - यह कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही उत्पादों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों प्रकाशों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण वितरण और विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण जैसे पैरामीटरों के रूप में तुलनीय अभिलक्षण होते हैं। घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के संबंध में उत्पाद की आवश्यक विशेषताओं की तुलना यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और आयातित वस्तु उत्पाद की अनिवार्य विशेषताओं के रूप में समान है। कई ऐसे मानदंड हैं – जिनका संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तथा अन्य सभी उत्पादक इन मानदंडों की संपुष्टि करते हैं। अतः, उपभोक्ताओं यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु और विदेशी उत्पादकों द्वारा आपूरित उत्पाद, यदि वे दोनों इन मानदंडों की पूर्ति करते हैं तो समान है।
 - विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया और याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है। तथापि, प्रत्येक विनिर्माता अपनी उत्पादन प्रक्रिया को जरूरतों एवं उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप बनाता है।
 - यह कि उत्पाद विवरण वह है जिसका प्रस्ताव प्रारंभिक याचिका दायर करने के पश्चात निदेशालय द्वारा किया गया। ऐसा होते हुए भी, यद्यपि, उत्पाद विवरण लंबा या व्यापक हो सकता है तथापि, उत्पाद का दायरा व्यापक नहीं है और यह वही रहता है जिस पर विगत पाटनरोधी जांच में और रक्षोपाय जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।
 - यह कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी द्वारा उत्पादित उत्पाद का लक्ष्य समान अनुप्रयोग/ अंतिम प्रयोग होता है और उपभोक्तागण इन वस्तुओं का उपयोग अदल-बदल कर रहे हैं, अतः इन उत्पादों को समान उत्पाद के रूप में माना जा सकता है। समान वस्तु का निर्धारण करते समय प्राधिकारी को उन सभी उत्पादों पर विचार करना अपेक्षित होता है जो ऐसे उत्पाद विवरण के अंतर्गत आते हैं जहां तक वे तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय होते हैं। पास्को ने कोल्ड रोलड फ्लैट उत्पादों के आयातों से संबंधित जांच के मामले में समान मुद्दा उठाया है। प्राधिकारी ने इन तर्कों को नामंजूर कर दिया है।
 - यह है निर्दिष्ट प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद को निम्नवत पुनर्गठित करने पर विचार कर सकते हैं, जिसका आशय विचाराधीन उत्पाद के दायरे में परिवर्तन करना नहीं होता है और यह के विवरण को प्रतिबंधित करता है और इसका बेहतर ढंग से स्पष्टीकरण करता है :

"सभी प्राकारान्तरों और ईएन, डीआईएन, जेआईएस, बीआईएस आदि जैसे अन्य मानदंडों में समकक्ष ग्रेडों सहित, जिनकी चौड़ाई 1650 एमएम से अधिक न हो, और जिनमें न्यूनतम निकिल तत्व 6 प्रतिशत हो, जिनमें क्रोमियम अनिवार्यतः मौजूद हो, और जो 1.2 एमएम की न्यूनतम मोटाई युक्त टाइटेनियम, तांबा आदि जैसे अन्य तत्वों के

संवर्धन के बिना या सहित हो, को शामिल करते हुए, एएसटीएम के अनुरूप 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद।"

- यह कि याचिकाकर्ता को उपर्युक्त के अनुरूप विचाराधीन उत्पाद का विवरण करने पर कोई आपत्ति नहीं है। हर हाल में, याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि विगत मामले में और वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद का दायरा समान है।
- यह कि ओडिशा में स्थापित नई उत्पादन सुविधा का विकास 1650 एमएम तक की सुविधा के लिए किया गया है और याचिकाकर्ता ने कोल्ड रोलिंग में 1690 एमएम तक की चौड़ाई की सामग्री की आपूर्ति पहले ही की हुई है। 1690 एमएम की चौड़ाई के उत्पाद (सीआर उत्पाद) की बिक्री को दर्शाने वाला संगत साक्ष्य प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
- यह कि पास्को के तर्क के विपरीत याचिकाकर्ता 2 एमएम की मोटाई से कम की वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, जिसका उत्पादन और निर्यात इसके द्वारा किया जाता है, याचिकाकर्ता ने न्यूनतर मोटाई के उत्पादों का उत्पादन और उसकी आपूर्ति की है। प्राधिकारी ने संगत साक्ष्य प्रस्तुत किया है।
- यह कि प्राइम और नॉन-प्राइम इस विचाराधीन उत्पाद के दो भिन्न उत्पाद प्रकार हैं। इस विचाराधीन उत्पाद के लिए की गई पाटनरोधी और रक्षोपाय जांच में इस उत्पाद में प्राइम और गैर-प्राइम के रूप में कोई अंतर नहीं किया गया है। प्राइम और गैर-प्राइम उत्पाद की उत्पादन लागत में कोई अंतर नहीं है।
- यह कि एनीलिंग और पिकलिंग प्रक्रियाएं हाट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों दोनों में की जाती हैं। एएसटीएम और ईएन मानदंड स्पष्ट एनीलड और पिकलड (डि-स्केल्ड) हाट रोल्ड उत्पादों का स्पष्टतः उल्लेख करते हैं।
- यह कि ओडिशा में इस उत्पाद का उत्पादन बंद करना एक अस्थायी बंदी है। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया गया कोई संयंत्र स्थायी रूप से बंद किए जाने को समझदारीपूर्ण व्यवसाय नहीं कहा जाएगा। हाट रोल्ड उत्पादों का उत्पादन ओडिशा संयंत्र में अभी भी किया जा रहा है। कोल्ड रोल्ड श्रेणी में उत्पादन अभी बंद है।

ख. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों की सावधानीपूर्वक जांच की है। याचिकाकर्ता की उत्पादन सुविधाओं का दौरा करने के दौरान उत्पादन प्रक्रिया तथा उत्पाद की स्वयं यथासंभव सीमा तक जांच की गई है।

12. याचिकाकर्ता भारत में हाट रोल्ड तथा कोल्ड रोल्ड उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है। भारत में इसके दो संयंत्र हैं – एक हिसार में और दूसरा ओडिशा में नव निर्मित संयंत्र, जिनकी संयुक्त संस्थापित क्षमता 15.80 लाख टन प्रति वर्ष है। दोनों ही संयंत्र पहले वांछित मोटाई और चौड़ाई की हाट रोल्ड ब्लैक प्लेट्स/काँइल्स का उत्पादन करते हैं और फिर उनको इस उत्पाद में आवश्यक मृदुता और सरफेस फिनिशिंग प्रदान करने के लिए एनील और पिकलड किया जाता है। हाट रोल्ड उत्पादों की बिक्री या तो ब्लैक प्लेट्स/काँइल्स के रूप में की जाती है जिनको क्रेता द्वारा अपनी ओर से पुनः संसाधित अर्थात् एनीलड और पिकलड किया जाता है या नम्बर 1 उत्पाद के रूप में एनीलड और पिकलड किया जाता है। इन संयंत्रों में उत्पादित हाट रोल्ड प्लेट्स/काँइल्ड उत्पादों के एक भाग को पुनः कोल्ड रोल्ड, एनीलड और पिकलड तथा स्किन पास्ड किया जाता है और तत्पश्चात उनकी बिक्री कोल्ड रोल्ड उत्पादों के रूप में की जाती है जिनका अलग-अलग अंतिम प्रयोग होता है। दोनों ही संयंत्रों में हाट और कोल्ड रोलिंग के लिए अपनी अलग-अलग सुविधाएं हैं। इसलिए, यह देखा गया है कि हाट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड दोनों ही उत्पादों के लिए एनीलिंग और पिकलिंग एक घनिष्ट हिस्सा है। अतः, कुछ हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत एनीलड पिकलड उत्पादों को गलत इरादे से शामिल किया है, जो कोल्ड रोलिंग प्रक्रिया का एक भाग है, त्रुटिपूर्ण है।

13. सत्यापन दौरे के दौरान यह पाया गया कि जेएसएल के ओडिशा संयंत्र में हाट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग दोनों तरह के प्रचालन कार्यरत थे। जांच करने पर यह पाया गया कि कोल्ड रोलिंग यूनिट को राज्य सरकार के कतिपय प्रदूषण नियंत्रण मुद्दों के कारण 16 नवम्बर से 20 दिसम्बर, 2014 के दौरान बंद रखा गया। कंपनी द्वारा संगत प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की गई सीडीआर रिपोर्ट के अनुसार इस संयंत्र को अपनी रैंप-अप प्रक्रिया को 90 प्रतिशत क्षमता उपयोग सहित सितम्बर, 2013 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए था। तथापि, यह प्रस्तुत किया गया कि विभिन्न देशों से पाटन के कारण कम आदेश मिलने की वजह से क्षमता उपयोग प्राप्त नहीं किया जा सका जबकि यह संयंत्र पूर्ण उत्पादन के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर हाल में, यह संयंत्र हाट रोल्ड उत्पादों का उत्पादन कर रहा था, इसलिए हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क सही नहीं पाया गया कि घरेलू उद्योग ओडिशा संयंत्र बंद होने के कारण माल की आपूर्ति करने में अक्षम है।

14. याचिकाकर्ता की क्षमताओं और उत्पादन की जांच यह व्यक्त करती है कि ओडिशा संयंत्र के तकनीकी साहित्य के अनुसार इस संयंत्र की क्षमता 1650 एमएम चौड़ाई तक की प्लेटों और स्ट्रिप का उत्पादन करने की है। आईएसओ मानकों के अनुसार मिल एंज उत्पादन में + 20 एमएम की सहनशीलता होती है। इस संयंत्र ने जांच की अवधि के दौरान 1625 एमएम तक की चौड़ाई के और 1.2 एमएम तक की मोटाई के एचआर कॉइल्स की बिक्री की है। इसी संयंत्र ने उसी अवधि के दौरान 1690 एमएम तक के सीआर कॉइल्स का उत्पादन और उसकी बिक्री की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उसी संयंत्र में उत्पादित एचआर कॉइल्स को ग्राही रूप से अंतरण सीआर कॉइल्स में कोल्ड रोलिंग करने के लिए किया जाता है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि यद्यपि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान 1625 एमएम से अधिक की चौड़ाई के एचआर कॉइल्स की बिक्री नहीं की है, तथापि यह तथ्य कि याचिकाकर्ता द्वारा 1690 एमएम तक की चौड़ाई वाले सीआर कॉइल्स का उत्पादन और उसकी बिक्री की गई है, दर्शाता है कि उन्होंने समान चौड़ाई के एचआर का उत्पादन किया और उन्हें कोल्ड रोलिंग के लिए ग्राही रूप से अंतरित किया। सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता की टेक्निकल टीम द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यद्यपि यह संयंत्र 1650 एमएम तक की चौड़ाई और 1.2 एमएम की मोटाई (+ साहिष्णुता सीमा) का उत्पादन कर सकता है तथापि, उनका उत्पादन शिड्यूल और वास्तविक उत्पादन क्रेताओं द्वारा मांगी गई मोटाई और आकार पर निर्भर करता है। इसलिए, यदि कोई आर्डर मिला है तो वे इन आयामों तक के एचआर कॉइल्स का सदैव उत्पादन कर सकते हैं।

15. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता 1000 एमएम से कम की चौड़ाई के मिल एंल की संबद्ध वस्तु की आपूर्ति नहीं कर रहा है, यह स्पष्ट किया गया कि अधिक चौड़ी प्लेटों/कॉइल्स का उत्पादन करना और तदुपरांत ग्राहक की जरूरत के उन्हें उससे कम चौड़ाई में स्लिट करना उत्पादन की तुलना में अधिक लागत प्रभावी है। हर हाल में उपभोक्ता को मिल एंज प्लेटों/कॉइल्स का प्रयोग करने से पहले उसे ट्रिम करना होता है। उसी रूप से अधिक संकरी प्लेटों/कॉइलों में रोलिंग करने से उत्पादन सुविधा की काफी कुछ क्षति होती है और ऊर्जा का नुकसान होता है। यह पाया गया कि याचिकाकर्ता अपने क्रेताओं को स्लिटिंग के पश्चात विभिन्न चौड़ाई के हाट रोलड कॉइल्स की आपूर्ति करता है। चूंकि मिल एंज प्लेटों को अंततः अपेक्षित आयामों के लिए ट्रिम और स्लिट किया जाता है इसलिए हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क में कोई आधार नहीं है कि इस विचाराधीन उत्पाद में 1000 एमएम से कम के मिल एंज उत्पादों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

16. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि गैर-प्राइम सामग्री को विचाराधीन उत्पाद से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में प्राइम और गैर-प्राइम दोनों वस्तुओं का उत्पादन सार्वभौमिक रूप से किया जाता है और उसकी बिक्री उसी रूप में की जाती है। उपभोक्ताओं द्वारा उनका उपयोग के कई क्षेत्रों में प्रतिस्थापनीय उत्पादों के रूप में उपयोग किया जाता है। प्राइम और गैर-प्राइम वस्तु की बिक्री भिन्न कीमत पर की जाती है। रक्षोपाय जांच सहित विगत में की गई सभी जांचों में उत्पाद का विभेदन प्राइम और नॉन-प्राइम आधार प्रकृति के उत्पादों की प्रकृति के आधार पर नहीं किया गया है। इसलिए इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क में प्राधिकारी को कोई ठोस आधार नहीं लगता है।

17. जहां तक कॉइल्स की लंबाई 10000 मीटर तक होने का संबंध है, इस मामले की जांच की गई और हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को तर्कसंगत पाया गया। स्पष्टतः इस विवरण में कोई न कोई भूल हुई है और इसलिए प्राधिकारी ने इस मापदंड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से हटा लिया है।

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पास्को ने अपने प्रस्तुतिकरण ने यह तर्क दिया है कि उनकी उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादित स्टील के ग्रेड भिन्न हैं और इसलिए वे याचिकाकर्ता द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु नहीं हैं। पास्को ने यह तर्क दिया है कि कतिपय डब्ल्यूटीओ पैनलों द्वारा विकसित किए गए न्याय निर्णय "समानता" का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित चार सामान्य मापदंडों को अपनाने का संकेत देते हैं; (i) उत्पाद की विशेषताएं, प्रकृति और गुणवत्ता; (ii) उत्पादों का अंतिम प्रयोग; (iii) उत्पाद के संबंध में उपभोक्ताओं की अनुभूति और स्वभाव जिसे अधिक व्यापक रूप से उपभोक्ताओं का अवबोधन और उनका बर्ताव कहा जाता है; और (iv) उत्पाद का प्रशुल्क वर्गीकरण।" इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियम 2 (घ) में समान वस्तु को ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है भारत में पाटित की जा रही जांचाधीन वस्तु के समरूप या समान हों अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य वस्तु, समान वस्तु मानी जाएगी जो यद्यपि सभी तरह से समान न भी हो, परंतु उसमें ऐसी विशेषताएं हो तो जांचाधीन वस्तु की विशेषताओं के निकट से सादृश्य हों। किसी वस्तु की समानता का निर्धारण करते समय प्राधिकारी उसमें प्रयोग किए गए कच्चे माल, उत्पादन प्रक्रिया, अंतिम प्रयोग और तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीयता आदि पर विचार करते हैं।

19. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पास्को ने यह सिद्ध करने के लिए रिकार्ड में इस तथ्य के अलावा कि पास्को संकीर्णतर और तनुतर कॉइलों का उत्पादन करने के लिए स्ट्रिप कास्टिंग प्रणाली का प्रयोग करता है कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि उनका उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद से भिन्न है। पास्को यह दावा करता है कि यह प्रक्रिया कई परम्परागत

प्रक्रियाओं को स्क्रिप करके उत्पादन की समग्र प्रक्रियाओं में कमी लाता है और बेहतर गुणवत्ता का उत्पाद उत्पादित करता है। यद्यपि, पास्को ने अपने इस दावे के प्रमाण में कोई उत्पादन और लागत आंकड़े तथा प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पास्को ने कोल्ड रोल्ड कॉइल्स के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में उत्पादन प्रक्रिया और गुणवत्ता में भिन्नता के आधार पर अपने उत्पादों का अपवर्जन करने के लिए इसी तरह के तर्क दिए थे और प्राधिकारी ने यह प्रतिपादित किया था कि ".....प्राधिकारी यह सराहना करते हैं कि बीएएफ इसे अभिव्यक्ततः गुणवत्ता और तकनीक रूप से भिन्न अंतिम उत्पाद मानने के बजाय गुणवत्तापूर्ण अंतिम उत्पाद प्राप्त करने की कारगर प्रक्रिया मानते हैं। अतः, प्राधिकारी ने बीएएफ प्रक्रिया द्वारा उत्पादित 409 और 409एल ग्रेडों को बीएएफ का प्रयोग न करके घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के वाणिज्यिक रूप से और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय माना है। वर्तमान मामले में भी पास्को ने अपने दावे का यह कहकर साक्ष्यांकन किया है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एक ऐसे उत्पाद का उत्पादन होता है जो घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद के तकनीकी रूप से एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है। इसलिए, पास्को के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जाता है।

20. घरेलू उद्योग तथा हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न तर्कों की उपर्युक्त जांच और आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्पाद एवं आयात के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित 304 श्रृंखला की स्टेनलेस स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पादों और संबद्ध देशों से आयातित उत्पादों के बीच कोई अंतर नहीं है। विनिर्माण प्रक्रिया में समानता और तकनीकी रूप से एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीयता के कारण प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि संबद्ध वस्तु को इस मामले में "विचाराधीन" उत्पाद का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ एक उत्पाद और समान वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए।

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसके समरूप एक जांच परिणाम में रक्षोपाय प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा वास्तविक उत्पादन और आपूर्ति के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के दायरे को 1625 एमएम की चौड़ाई तक प्रतिबंधित कर दिया था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने 1625 एमएम से परे और 1.2 एमएम तक की मोटाई के स्टेनलेस स्टील कॉइल्स का उत्पादन करने और उसकी बिक्री करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। वास्तव में, जांच की अवधि के दौरान उच्चतर चौड़ाई की एचआर कॉइल्स का उत्पादन किया गया है और सीआर जिसकी बिक्री की गई है, का उत्पादन करने के लिए उसका ग्राही रूप से अंतरण किया है। इसलिए, प्राधिकारी यह संपुष्टि करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की चौड़ाई और मोटाई की सीमा जांच शुरुआत अधिसूचना में यथाईंगित के अनुरूप है।

22. प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि इसी उत्पाद के लिए अन्य देशों के विरुद्ध अपने दिनांक 11 अक्तूबर, 2011 के अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने ट्रिम एंज और मिल एंज दोनों के लिए चौड़ाई सहिष्णुता आईएसओ मानदंडों के अनुरूप अनुमति दी है। इसलिए, प्राधिकारी इस जांच में संबद्ध वस्तु के बारे में चौड़ाई सहिष्णुता समान आईएसओ मानदंडों के अनुरूप दर्शाना आवश्यक समझते हैं। आईएसओ मानदंड में हाटरोल्ड प्लेटों/शीटों तथा स्ट्रिप्स के लिए चौड़ाई सहिष्णुता + 20 एमएम (मिल एंज के लिए) और + 5 एमएम (ट्रिम एंज के लिए) है।

23. इस उत्पाद के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए प्राधिकारी सहिष्णुता सीमा के निगमन सहित इस विचाराधीन उत्पाद के विवरण संपुष्टि निम्नवत करने का प्रस्ताव करते हैं -

"हाट रोल्ड आस्टीनिटिक स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पाद; 304 या 304 एच या 304 एल या 304 एन या 304एलएन या ईएन 1.4311, ईएन 1.4301, ईएन 1.4307 या एक्स 5 सीआर एनआई 1810, या एक्स 04 सीआर 19 एनआई 9 ग्रेड के या किसी अन्य मानदंड में उसके समकक्ष जैसे यूएनएस, डीआईएन, जेआईएस, बीआईएस, ईएन आदि के चाहे वे नम्बर बन या ब्लैक फिनिश की हों या न हों, चाहे वह प्राइम या गैर-प्राइम गुणवत्ता की हों या न हों; उनकी एंज स्थिति मिल एंज या ट्रिम एंज की हो या न हो; कॉइल्स में उनकी मोटाई 1.2 एमएम से 10.5 एमएम के बीच और प्लेटों और शीटों की मोटाई 3 एमएम से 105 एमएम के बीच हो; 1650 एमएम तक की चौड़ाई (मिल एंज के लिए चौड़ाई सहिष्णुता +20 एमएम और ट्रिम एंज के लिए चौड़ाई सहिष्णुता 5 एमएम) की आयताकार आकार की (हाट रोल्ड एनील्ड और पिकल्ड या ब्लैक) प्लेटें शीट्स या कॉइल्स।"

24. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन पश्चात किए गए अपने विवरण प्रस्तुतिकरणों में इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अपने-अपने तर्कों को पुनः दोहराया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए मुद्दों का इससे पहले के पैराग्राफों में समुचित निराकरण कर दिया गया है और उन्हें पुनः स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद की उपर्युक्त के रूप में संपुष्टि करते हैं।

ग. घरेलू उद्योग और आधार

25. यह आवेदनपत्र मैसर्स जिंदल स्टील, नई दिल्ली द्वारा दायर किया गया है और आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में इस संबद्ध वस्तु के केवल दो अन्य उत्पादक भी हैं मैसर्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और मैसर्स शाह अलायज जो भारत में संबद्ध वस्तु का विनिर्माण भी करते हैं।

26. इस जांच की शुरुआत करने से पहले प्राधिकारी ने आवेदक घरेलू उद्योग के आधार पर निर्धारण करने के लिए इस संबंध में उपर्युक्त ज्ञात घरेलू उत्पादकों से भी सूचना मंगाई थी। अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तु के उत्पादन का सुनिश्चयन करने के लिए भी प्रयास किए गए। प्राधिकारी ने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु के अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन और उनकी क्षमताओं के बारे में भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना की जांच की। प्राधिकारी की जानकारी में यह लाया गया कि कोई भी अन्य इस्पात विनिर्माता, उपर्युक्त उल्लेख के अलावा, वाणिज्यिक बिक्री के लिए हाट रोल्ड स्टेनलेस स्टील का उत्पादन नहीं करता है और इसलिए वह घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में अर्ह नहीं है।

27. संबद्ध वस्तु के अन्य ज्ञात उत्पादकों के उत्पादन तथा रिपोर्ट की गई। अनुमानित क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए आवेदक का देश में इस संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आवेदक के आधार के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है। इसलिए, प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि आवेदक भारत में इस संबद्ध वस्तु के उत्पादन के एक बड़े हिस्से का उत्पादन करता है और इस जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक अर्थात् मैसर्स जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड का नियम 5(3) के अनुसार आधार बनता है और वह नियम 2(ख) में उल्लिखित निबंधनों के अनुरूप घरेलू उद्योग है -

घ. न्यूनतम सीमा

28. प्राधिकारी को वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) तथा अन्य गौण स्रोतों (आईबीआईएस) से प्राप्त आयात आंकड़ों तथा संबद्ध देशों के सहयोगकर्ता निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों को न्यूनतम स्तर से अधिक पाया गया।

ड. इस जांच के हितबद्ध पक्षकार

29. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन में संबद्ध वस्तु के एक उत्पादक/निर्यातक अर्थात् लिआन्झांग स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन और मलेशिया के एक उत्पादक/निर्यातक अर्थात् बाहरू स्टेनलेस स्टील ने अपना निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है। चीन में संबद्ध वस्तु के एक उत्पादक/निर्यातक अर्थात् लिआन्झांग स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन और मलेशिया के एक उत्पादक/निर्यातक अर्थात् बाहरू स्टेनलेस स्टील ने अपना निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है। चीन में विनिर्मित संबद्ध वस्तु के सिंगापुर स्थित एक व्यापारी/निर्यातक अर्थात् मैसर्स सेंचुरी स्टील पीटीई लिमिटेड ने भी प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है। कोरिया के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। तथापि, मैसर्स पास्को, कोरिया, मैसर्स ह्युन्डई, कोरिया और मैसर्स ह्योउसंग, कोरिया ने घरेलू उद्योग के दावे का विभिन्न आधारों पर विरोध करते हुए संयुक्त क्षति प्रस्तुतिकरण दायर किया है।

30. निम्नलिखित आयातकों/उपभोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर/क्षति प्रस्तुतिकरण दायर किया है :

1. रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड
2. भंडारी फाइल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड
3. हिन्दुस्तान इनाक्स लिमिटेड
4. जेएनबी स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
5. कंसारा पोपटलाल तिभुवनदास मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
6. संतोष स्टील इंडस्ट्रीज
7. शाल्को इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
8. शुभलक्ष्मी मेटल्स एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड

9. एसएनवी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
10. सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
11. सनराइज स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड
12. वरुण फाइल्स लिमिटेड
13. सनसिटी शीट्स प्राइवेट लिमिटेड
14. नवग्रह फासेनर्स प्राइवेट लिमिटेड

31. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि पास्को कोरिया ने पहले भी कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों से संबंधित एक जांच में भाग लिया था और प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया था। तथापि, कंपनी ने इस बार प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करने से यह कहकर मना कर दिया कि वे वस्तु का पाटन नहीं कर रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि पाटन की मौजूदगी होना या न होना यह एक तथ्य है और इस पाटन का होना या न होना इसका निर्धारण इन तथ्यों का विश्लेषण करने के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है। संगत तथ्यों युक्त प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रदान किए बिना कोई पक्षकार यह अभिकथा नहीं कर सकता है कि वे पाटन नहीं कर रहे हैं। वास्तव में प्रत्युत्तर दायर न करने का आशय यह है कि पास्को द्वारा भारी मात्रा में पाटन किया जा रहा है।

32. घरेलू उद्योग ने पुनः यह तर्क दिया है कि यद्यपि किसी भी पक्षकार को जांच में भाग लेने और अपने तर्क प्रस्तुत करने का अधिकार है परंतु इसका पहला दायित्व प्राधिकारी द्वारा विनिर्धारित संगत सूचना प्रदान करना होता है। प्राधिकारी ने संगत सूचना प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली निर्धारित की है। इस निर्धारण का प्रतिलिखन नहीं किया जा सकता है यहां तक कि तर्क देकर भी नहीं। प्राधिकारी द्वारा प्रश्नावली के माध्यम से मांगी गई सूचना इस जांच से बहुत अधिक संगत होती है और निर्यातक को यह प्रश्नावली प्रत्युत्तर अवश्य दायर करना चाहिए।

33. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पास्को कोरिया तथा अन्य निर्यातकों ने पाटन, यदि कोई और उसके विस्तार का निर्धारण करने के लिए प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किए बिना ही इस जांच के विभिन्न पहलुओं के संबंध में कतिपय तर्क दिए हैं। इसलिए, प्राधिकारी कोरिया से पाटन के संबंध में उनके दावे की जांच करने की स्थिति में नहीं हैं। तथापि, इस जांच के अन्य पहलुओं से संबंधित उनके तर्कों को रिकार्ड में ले लिया गया है और उनकी अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों की जांच करते वक्त जांच की गई और उनका इस अंतिम जांच परिणाम में संगत पाई गई सीमा तक तथा सत्यापन योग्य साक्ष्यों द्वारा निराकरण कर दिया गया है।

च. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विविध प्रस्तुतिकरण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

34. हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग ने इस जांच के संबंध में विभिन्न मुद्दे उठाए हैं जिनमें घरेलू उद्योग के क्षति के दावे और पाटन का निर्धारण करने की क्रियापद्धति के मुद्दे शामिल हैं। यद्यपि पाटन एवं क्षति निर्धारण से संबंधित मुद्दे का इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर निराकरण कर दिया गया है, तथापि इस जांच के पक्षकारों द्वारा उठाए गए सामान्य मुद्दों की इसके अंतर्गत निम्नवत जांच की गई है। संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और उनमें उठाए गए मुद्दों को संक्षेप में निम्नवत प्रस्तुत किया गया है :

- यह कि यह जांच आंकड़ों का संग्रहण करने की अवधि समाप्त होने तथा जांच प्रारंभ होने के बीच नौ माह के अंतर से प्रारंभ की गई। 9 महीनों का इतना बड़ा अंतर डब्ल्यूटीओ अधिदेशित जांच की प्रक्रिया में उल्लिखित निबंधनों के अनुरूप "जांच शुरुआत की तारीख से निकट समाप्ति" के रूप में अर्ह नहीं है। वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित उपर्युक्त अपेक्षा का उल्लंघन किया है। इसलिए वर्तमान जांच विधि के अनुरूप नहीं है और इसे केवल इस आधार पर ही तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- यह कि आवेदक ने साधारणतः यह उल्लेख कर दिया है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमतों के संबंध में कोई कीमत विवरण या बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में विनिर्मित सामान्य मूल्य नहीं प्राप्त कर सका। यह संपूर्ण आवेदन दायर करने की अधिदेशित जरूरत को पूरा न करने का एक स्पष्ट मामला है। बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में किसी कीमत या विनिर्मित सामान्य मूल्य का प्रस्तुतिकरण किए बिना यह आवेदन स्पष्टतः अधूरा है।

- यह कि आवेदक इस संबद्ध वस्तु की बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में प्रचलित कीमत; ऐसे तृतीय देश से इस संबद्ध वस्तु की अन्य देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के लिए कीमतों संबद्ध वस्तु के लिए कच्चे माल की कीमतों, जिसे कथित रूप से "प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर" लिया गया है, निर्यात कीमत के संबंध में समायोजन (समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय परिवहन लागत, वैट घाटा, बिक्री कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन प्रहस्तन प्रभार और सामुद्रिक बीमा) के संबंध में एकमात्र साक्ष्य भी प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों के अंतर्गत प्राधिकारी स्वयं को प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की "यथार्थता और उपयुक्तता" के संबंध में संतुष्ट नहीं कर सकते हैं।
- यह कि यदि विनिर्मित सामान्य मूल्य आवेदक के अनुभव के आधार पर पूर्णतया स्वीकार्य है तब भी सामान्य मूल्य को किसी साक्ष्य के साथ प्रदान करने की जरूरत अनावश्यक हो जाती है क्योंकि जब भी कहीं कीमत अधोरदन/अधोविक्रयण होता है, वहां सामान्य मूल्य निर्यातक के परिकल्पित पाटन व्यवहार को तब भी दर्शाएगा जब वास्तविक सामान्य मूल्य के संदर्भ में कोई पाटन न भी हुआ हो।
- हितबद्ध पक्षकारों ने अपने प्रस्तुतिकरणों में यह तर्क दिया है कि वर्तमान जांच में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रतिभागिताकारी निर्यातक के खपत मानकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- यह कि मैसर्स जिंदल स्टील भी 304 श्रृंखला से ऊपर के एचआरएसएस कॉइल्स और सीआरएसएस कॉइल्स का निर्यात कर रही है और उनकी कीमतें चीन, कोरिया और मलेशिया के आपूर्तिकर्ताओं की निर्यात कीमतों से तुलनीय है। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क के लिए तो कोई आधार ही नहीं बनता है।
- यह कि आवेदक का उद्देश्य एकाधिकारवादी स्थिति प्राप्त करना और घरेलू उद्योग को ऐसी परिष्कृत वस्तु की क्षति पहुंचाना है जहां इनपुट के रूप में 304 सीरीज की एचआरएसएस कॉइलों/ सीआरएसएस काइलों का प्रयोग किया जाता है।
- यह कि आवेदक द्वारा घरेलू बाजार तथा निर्यात बाजार में प्रभारित की जा रही कीमतें पहले से ही काफी अधिक हैं और आवेदक इन उच्चतर कीमतों को घरेलू बाजार में बनाए रखने के लिए पाटनरोधी शुल्क की मांग कर रहा है।
- यह कि आवेदक उद्योग मुख्यतः 304 श्रृंखला के सीआर एसएस कॉइल्स का निर्यात कर रहा है और सीआर एसएस काइल्स का निर्यात कर रहा है और सीआर एसएस काइल्स और एचआर एसएस कॉइल्स की कीमतों में अंतर अनुमानतः 200 यूएस डालर प्रति एमटी है और इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात कीमत 304 श्रृंखला की सीआर एसएस की तुलना में 200 यूएस डालर कम होगी। इसलिए, एचआर कॉइल्स की कीमतों का निर्धारण प्रतिलोभ प्रभार प्रणाली द्वारा किया जा सकता है।
- यह कि यदि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया जाता है तो भारतीय बाजार में यह उत्पाद अधिक महंगा हो जाएगा और इससे अंतिम प्रयोक्ता प्रभावित होगा। इस उत्पाद पर पाटनरोधीशुल्क का घरेलू उपयोगकर्ता उद्योग तथा उसके परिष्कृत उत्पादों जैसे प्रसंस्करण उपकरणों, रि-रोलिंग, रिएक्टर वैसल, सामग्री प्रहस्तन उपकरणों, रेलवेज, पाइप्स एवं ट्यूब्स, स्वचालित संघटकों, रोलड एवं फार्म्ड सेक्सनों आर्किटेक्चरल एवं भवन तथा विनिर्माण उद्योग, फेब्रीकेशन और पावर सेक्टर आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
- यह कि चीन जनगण, कोरिया और मलेशिया के अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड के प्रतिस्पर्धी नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रदायक 900 एमएम तक की चौड़ाई की एचआर कॉइल्स का विनिर्माण करते हैं जबकि आवेदक उद्योग 1000 एमएम से अधिक के एचआर कॉइल्स का विनिर्माण करता है। इन देशों द्वारा प्रयोग की जा रही प्रौद्योगिकी और विनिर्माण प्रक्रिया भी भिन्न है।
- यह कि विदेशी विनिर्माताओं की विनिर्माण लागत उनके प्रचालन की दक्षता और उत्पादन के पैमाने के कारण कम होती है। वे कम कीमत पर स्टेनलेस स्टील के बेहतर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान कर रहे हैं और भारत में अपने उत्पाद का पाटन नहीं कर रहे हैं।
- यह कि अधिकांश उत्पादन अर्थात् 90 प्रतिशत उत्पादन आवेदक द्वारा किया जाता है और शेष 10 प्रतिशत उत्पादन मैसर्स सेलम स्टील द्वारा किया जाता है। यह आवेदक इस वस्तु की आपूर्ति उन लोगों को नहीं कर रहा है जो पूर्णतया उससे ही खरीद नहीं कर रहे हैं और वह अपनी शर्तों को मनवाकर छोटे क्रेताओं का शोषण कर रहे हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण कर दिया जाता है तो आवेदक की बाजार में पूर्ण एकाधिकारिता हो जाएगी।

- यह कि आवेदक का पहले से ही उपरिमूल्यित संयंत्र है और वह इन उत्पादों के विदेशी विनिर्माताओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है और पाटनरोधी शुल्क इसका कोई समाधान नहीं होगा।
- यह कि आवेदक को विदेशी आपूर्तिकर्ता की तुलना में पहले से ही लाभ हो रहा है क्योंकि उन्हें प्रमुख कच्चा माल जैसे लौह अयस्क, क्रोम आदि अपने देश के अंदर से ही प्राप्त हो रहा है जबकि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को इस कच्चे माल का आयात करना पड़ता है।
- यह कि आवेदक घरेलू उद्योग की वित्तपोषण प्रणाली की जांच यह निश्चय करने के लिए की जानी चाहिए कि क्या वे व्याज मुक्त ऋण का उपयोग पूरी तरह से विनिर्माण प्रक्रिया के लिए कर रहे हैं या अपनी अनुपंगी कंपनी में कर रहे हैं।
- यह कि जेएसएल द्वारा उत्पादित हाट रोल्ड उत्पादों में दोनों ओर ही हॉट रोलिंग मार्क्स ऐसे होते हैं जो समुद्रपारीय वेंडरों को दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। पाइप विनिर्माताओं को इस खराबी को दूर करने के लिए अतिरिक्त चौड़ाई की खरीद करनी पड़ती है।
- यह कि आवेदक एक विशिष्ट चौड़ाई और विशिष्ट मोटाई के माल का अल्प मात्रा में विनिर्माण करने की स्थिति में नहीं है। जेएसएल द्वारा आपूर्ति किए गए कॉइल्स, जिनकी फ्रंट ईड और रियर ईड तक की न्यूनतम 3 मीटर लंबाई होती है, में गुणवत्ता संबंधी बड़ा मुद्दा होता है जिसके कारण क्षति बढ़ जाती है।
- यह कि जेएसएल माल की समय पर सुपुर्दगी नहीं करता है और उनके परिवहन प्रभार बहुत महंगे हैं क्योंकि वे अपने माल की आपूर्ति सड़क परिवहन से करते हैं जिसकी लागत 4000 प्रति एमटी बैठती है।
- यह कि इस याचिका का अगोपनीय पाठ पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है और यह गोपनीय के रूप में मानी गई सूचना का तर्कसंगत सार प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है जिससे गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमों का इस याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लंघन हो रहा है।
- यह कि घरेलू उद्योग ने लागत सूचना के संबंध में अवांछित और अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और उसका सार्थक सारांश भी प्रदान नहीं किया गया है।
- यह कि घरेलू उद्योग ने पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ विनिर्मित सामान्य मूल्य का सहारा लिया है और विनिर्मित सामान्य मूल्य से संबंधित सूचना पर यदि आयातकों/प्रयोक्ताओं को टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो यह पूर्णतया अनुचित होगा और इसका उन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।
- यह कि प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों को एक सार्वजनिक फोल्डर के जरिए संपूर्ण व्यापारिक संव्यवहारवार आयात आंकड़ों का प्रकटन करें।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

35. घरेलू उद्योग ने अपने प्रस्तुतिकरणों में हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों का खंडन किया है। इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

- यह कि इस याचिका को अत्यधिक अभिनव अवधि में दायर किया गया है। किसी भी हाल में, जांच की वर्तमान अवधि पर विचार करके कोई पूर्वावधारणा नहीं बनाई गई है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में जांच की वर्तमान अवधि के पश्चात की अवधि में और अधिक गिरावट आई है जैसाकि इस प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरण के साथ संलग्न विवरण से स्पष्ट हो जाता है। यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि के पश्चात आयातों में भारी वृद्धि हुई और जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा सहन किए गए घाटे में और अधिक वृद्धि हुई है।
- यह कि चीन में अपनी क्षमता में भारी विस्तार और अनुचित लागत लाभ से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां यह वैश्विक पाटन में अंतर्ग्रस्त हो गया है। स्टील में अंतर्ग्रस्त होने के संबंध में चीन के विरुद्ध कारणों का एक जखीरा है। इसलिए, उद्योग को विश्व बाजार में अपनी मौजूदगी भी बनाए रखने के लिए अपनी कीमतें उसके अनुरूप करनी पड़ी। हालांकि याचिकाकर्ता के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं जिससे वह अन्य देशों को संपूर्ण विश्व में पाटन करने से रोक सके, फिर भी याचिकाकर्ता को यह अधिकार है और उसे अपने देश की सरकार से यह उम्मीद है कि वह अपनी मातृ भूमि में होने वाले पाटन के विरुद्ध कोई समाधान सुझाए।

- यह कि इस समायोजन के संबंध में यथासंभव सीमा तक साक्ष्य जैसे समुद्री भाड़े और वैंट के साक्ष्य, उपलब्ध कराए गए हैं। अन्य समायोजनों के लिए रूढ़िवादी आंकड़ों पर विचार किया गया है। इस जांच में प्रतिभागिता करने वाले निर्यातक निश्चय ही यह सूचना प्रदान करने में सक्षम होंगे क्योंकि यह उनका अधिकार है।
- यह कि जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता ने पाटित आयातों के वास्तविक एवं संभावित प्रभावों के संबंध में भरोसेमंद सूचना प्रदान नहीं कराई है, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि संभाव्य शब्द का आशय "संभावित" या "प्रसंभाव्य" है और यह कि इसे साक्ष्यांकित किया गया है कि इस पाटन के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में विभिन्न पैरामीटरों में मौजूदा गिरावट आई है। यह तथ्य स्वयं ही घरेलू उद्योग के निष्पादन में भविष्य में होने वाली संभावित गिरावट का एक आधार है।
- यह कि प्राधिकारी संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन की सतत जांच कर रहे हैं। यदि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन में क्षति न होने की स्थिति में ही प्राधिकारी को विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों के संबंध में संभावित स्थिति की जांच करना अपेक्षित होता है।
- यह कि केवल यथावांछित गोपनीयता का ही दावा किया गया है और प्राधिकारी ने उसकी जांच करने के पश्चात ही गोपनीयता प्रदान की है। याचिकाकर्ता ने जहां की आवश्यक हुआ इंडेक्स सूचना प्रदान कराई है। ऐसे कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं बताए गए हैं जहां याचिकाकर्ता को वास्तविक सूचना प्रदान कराई जानी चाहिए और याचिकाकर्ता ने उसे ही रोके रखा है। घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आयातकों ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किए हैं जिनमें मात्रा पैरामीटरों से संबंधित विवरण जैसे आयातों और मालसूची का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि आयात मात्रा और मालसूचियों का इन आयातकों के लिए बिजनेस संवेदी के रूप में दावा किया गया है वहीं वे यह मानते हैं कि उत्पादन लागत, बिक्री कीमत और लाभ/हानि याचिकाकर्ता के लिए गोपनीय नहीं है।
- यह कि हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का कोई विधिक या तथ्यात्मक आधार नहीं है कि प्राधिकारी द्वारा संग्रहित सौदेवार आयात आंकड़े सार्वजनिक फोल्डर में रखे जाने चाहिए। प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं से यह अपेक्षा करते हैं कि वह आयातों के मूल्य एवं उसकी मात्रा तथा सूचना के स्रोत के संबंध में जानकारी प्रदान करें। प्राधिकारी याचिकाकर्ता से यह अपेक्षा नहीं करते हैं कि वह उन्हें सौदेवार सौदा आंकड़े प्रदान कराएं। ऐसी सीमा तक यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराई गई सौदेवार सौदा सूचना प्राधिकारी की विहित अपेक्षाओं से परे है।
- यह कि जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के अधिकारों के संबंध है, उनके अधिकार आयातों की मात्रा, मूल्य और आयातों की कीमत के संबंध में घरेलू उद्योग के दावों पर टिप्पणी करने तक सीमित है। हितबद्ध पक्षकारों को इस सूचना के आधार पर अपने हितों की रक्षा करने से छूट प्राप्त है। हितबद्ध पक्षकार इस आधार पर सौदेवार आंकड़ों के संबंध में सूचना की मांग नहीं कर सकते हैं।
- यह कि प्राधिकारी द्वारा संव्यवहारवार आंकड़े याचिका में उल्लिखित सूचना/साक्ष्य की यथार्थता और परिशुद्धता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए मंगाना अपेक्षित होता है। तथापि, यह अपेक्षा भी निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए होती है और इससे संगत साक्ष्यों की मांग करने का हितबद्ध पक्षकारों को कोई अधिकार नहीं मिल जाता है।
- यह कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान कराई गई सूचना की यथार्थता और उपयुक्तता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने का अधिकार है और इस प्रयोजनार्थ, निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यातकों से विस्तृत सूचना की मांग करते हैं और उसका सत्यापन करते हैं। तथापि, घरेलू उद्योग को इस सूचना तक पहुंच प्रदान नहीं कराई जाती है।
- यह कि निर्यातकों के तर्क स्वीकार कर लिए गए, इसका आशय यह है कि निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों और घरेलू बिक्रियों के बीजकवार विवरण भी घरेलू उद्योग को उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिससे कि वह उनके आंकड़ों की परिशुद्धता की जांच कर सके।
- यह कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा आयातों के सौदेवार विवरण बिना किसी पूर्वावधारण के उपलब्ध कराए गए हैं। अतः, यद्यपि याचिकाकर्ता को सूचना प्रदान करना विधिक रूप से अपेक्षित नहीं है तथापि, तथ्यात्मक रूप से याचिकाकर्ता ने वास्तव में यह सूचना उपलब्ध कराई है और इसलिए यह सारा तर्क निराधार है।
- यह कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश से भारत को कीमत को इस कारण से नहीं अपनाया जा सकता है कि तृतीय देशों से भारत को यह कीमतें चीन द्वारा किए गए पाटन से प्रभावित होती है और इसलिए वे उपयुक्त नहीं होती हैं। इन हालातों के अंतर्गत सामान्य मूल्य का निर्धारण समान उत्पादों के लिए भारत में वास्तविक रूप से संदेय या संदत्त कीमतों पर, तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करते हुए, विधिवत समायोजन करने के पश्चात विचार करके किया जाना चाहिए।

- यह कि भारत में वास्तविक रूप से संदत्त कीमतों पर इस कारण से विचार नहीं किया जा सका कि वे उत्पादन लागत से कम थी। अतः, प्राधिकारी के पास केवल एकमात्र विकल्प यही बचता था कि भारत में उत्पादन लागत पर विचार विधिवत समायोजन करने के पश्चात किया जाए जिससे कि उसमें कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें और इष्टतम संपरिवर्तन लागत, बिक्री, सामान्य प्रशासन व्यय और युक्तियुक्त लाभ परिलक्षित होता हो। चीन के उत्पादकों या आयातकों या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कीमत या बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विनिर्मित मूल्य के संबंध में न तो कोई दावा किया है और न ही कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया है।
- सामान्य मूल्य के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए यूएन कामट्रेड आंकड़ों को नहीं अपनाया जा सकता है क्योंकि सीमाशुल्क वर्गीकरण इस विचाराधीन उत्पाद के प्रति समर्पित नहीं है। इस विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या 7219 और 7220 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। यूएन कामट्रेड 6 अंकीय स्तर के सीमाशुल्क वर्गीकरण के संबंध में सूचना प्रदान करता है। वर्गीकरण कोड स्टेनलेस स्टील उत्पादों की श्रृंखला का भी वर्णन नहीं करता है। यह संभव है कि यूएन कामट्रेड में विचाराधीन उत्पाद के अलावा अन्य उत्पाद शामिल हों। ऐसा मामला होने पर, अन्य देशों के सीमाशुल्क आंकड़ों को नहीं अपनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, तृतीय देश से भारत को आयात कीमत को भी इस कारण से नहीं अपनाया जा सकता है क्योंकि वे या तो पाटित कीमतों पर होती है या वे वर्तमान पाटन द्वारा प्रभावित होती हैं।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न विविध मुद्दों की जांच की गई है और उनका निम्नवत समाधान किया गया है :

- जहां तक जांच की अवधि और जांच की शुरुआत के बीच अंतराल होने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि को अंगीकार करने के लिए किसी विशिष्ट समय-सीमा को अपनाने की प्राधिकारी पर विधिक बाध्यता नहीं है हालांकि प्राधिकारी अब तक किए गए सर्वोत्तम प्रयास मार्गदर्शनों के आधार पर पूर्णतया मार्गदर्शित होते हैं और वह जांच के प्रयोजनार्थ अत्यधिक अभिनव अवधि को अपनाने का प्रयास करते हैं। इस मामले के तथ्यात्मक आधारी प्रणाली में यह जांच एक ऐसी अवधि के आंकड़ों का संग्रह करके शुरू की गई जो घरेलू उद्योग तथा निर्यातकों दोनों पर ही लागू होती है। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि होने के कारण जांच की अवधि के पश्चात क्षति तीव्र हो गई थी। इसलिए, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के हित जांच की शुरुआत की तारीख और आंकड़े संग्रहित करने की अवधि के बीच अंतर होने के कारण प्रभावित नहीं हुए हैं।
- जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के साक्ष्य के संबंध में प्रस्तुत सूचना की उपयुक्तता और यथार्थता का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह जांच याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों की उद्देश्यपरक जांच करने के पश्चात शुरू की गई। याचिकाकर्ता ने उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण दिया है जिनके अंतर्गत निर्यात के देश में सामान्य मूल्य के प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं और उसकी उद्देश्यपरक जांच करने के पश्चात ही सामान्य मूल्य के आकलन के वैकल्पिक तरीके को शुरुआती स्तर पर स्वीकार किया गया है। निर्यात कीमतों का समायोजन याचिकाकर्ता द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई सूचना की जांच करने के पश्चात ही प्रभावित हुआ है। इसलिए, प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि यह जांच किसी भी तरह से विधि विरुद्ध नहीं है क्योंकि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का आकलन, संबद्ध देशों में प्रचलित कीमतों को प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण वैकल्पिक तरीके का उपयोग करके शुरुआती स्तर पर ही कर लिया गया था।
- जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहीं भी संभावित गिरावट को सिद्ध नहीं किया है और क्षति के संबंध में लगाए गए आरोपों को अनुच्छेद 3.4 की असंगतता के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के समक्ष की गई अपनी याचिका में पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग के भौतिक और वित्तीय निष्पादन के संबंध में कतिपय पैरामीटरों में गिरावट होने की सूचना प्रथम दृष्टया ही प्रदान कर दी थी। इसलिए इस स्तर पर पाटित आयातों के संभावित या प्रसंभाव्य प्रभाव के संबंध में सूचना की मांग करने की जरूरत नहीं है।
- जहां तक कतिपय हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के घरेलू बाजार में और निर्यात बाजार में व्यवहार के संबंध में उठाए गए मुद्दे का सवाल है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का यह प्रस्तुतिकरण कि बाह्य बाजार में उनका कीमत व्यवहार कई बाजारों में संबद्ध देशों के पाटित आयातों की भारी मौजूदगी के कारण प्रभावित हुआ है जो इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि डब्ल्यूटीओ के कई सदस्यों ने स्टील उत्पादों के संबंध में कई व्यापार उपचारी

कार्यवाहियों की हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि बाह्य बाजार में निर्यात कीमत के कारण याचिकाकर्ता के निष्पादन पर इस मामले में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू प्रचालनों के कारण सहन की गई क्षति की ही जांच की गई है और निर्यात के कारण होने वाली किसी क्षति को याचिकाकर्ता के घरेलू प्रचालनों में हुई क्षति पर उपरोपित नहीं किया गया है। इसलिए, इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों को प्रतिपाद्यनीय नहीं माना गया है।

- जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है उन्हें इस जांच में प्राधिकारी द्वारा विचारित सौदेवार आयात आंकड़े प्रदान कराए जाएं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियम में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की गई है कि प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अगोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना के अलावा अन्य स्रोतों से संग्रहित सूचना को भी सार्वजनिक फोल्डर में उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी द्वारा अन्य एजेंसियों से संग्रहित सूचना/आंकड़ों का सर्वोत्तम संभव ढंग से विश्लेषण किया गया है कि उनका इस जांच परिणाम में संगत समझी गई सीमा तक उपयोग किया गया है। इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के याचिकाकर्ता के प्रतिस्पर्धा विरोधी और एकाधिकारवादी व्यवहार; गुणवत्ता और सुपुर्दगी संबंधी मुद्दों और जनहित संबंधी मुद्दों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच का उद्देश्य पाटित आयातों के प्रभावों की पहचान करना और उन्हें दूर करना होता है जिससे विदेशी उत्पादकों के अनुचित कीमत व्यवहार के विपरीत घरेलू विनिर्माताओं के लिए समान अवसर सृजित किए जा सकें, न कि आयातों को प्रतिबंधित करना या एकाधिकारवादी स्थिति सृजित करना। घरेलू उद्योग को विधि के अंतर्गत उपचारी उपायों की मांग करने का अधिकार है। आयातक और उपभोक्ता अपनी जरूरतों के अनुसार वस्तु का गैर-पाटित कीमतों पर आयात करने के लिए स्वतंत्र है।
- जहां तक गोपनीयता के दावे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सूचना प्रस्तुत करने वाले विभिन्न पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की व्यवहार्य रूप से और यथासंभव सीमा तक जांच की गई है और पक्षकारों द्वारा प्रदान कराई गई सूचना की प्रकृति के आधार पर गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयात आंकड़े तथा मात्रा सांख्यिकी आदि को सार्वजनिक फोल्डर में रख दिया गया है और ऐसी किसी भी सूचना के लिए गोपनीयता की अनुमति नहीं दी गई है जो घरेलू उद्योग की व्यवसाय स्वामित्व संबंधी सूचना या अत्यधिक संवेदनशील सूचना नहीं है। तथापि, इसको ध्यान में रखते हुए कि चीन के निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का आकलन घरेलू उद्योग की प्रचालन सूचना के आधार पर किया गया है और इस तरह अनुमानित मूल्य के विभिन्न तत्वों का ब्यौरा घरेलू उद्योग के लिए व्यवसाय संवेदी है इसलिए उसका विस्तृत विवरण सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध नहीं कराया गया है। जहां तक निर्यातकों के प्रस्तुतिकरणों का संबंध है निर्यातकों द्वारा प्रदान कराई गई सूचना, जहां तक वह उक्त सूचना प्रदान कराने वाले के लिए व्यवसाय संवेदनशील सूचना नहीं है, उसे सार्वजनिक फोल्डर में रखा गया है। विरोधकर्ता पक्षकारों के गोपनीयता के दावों के संबंध में सभी पक्षकारों की आपत्तियों को उपयुक्त के मद्देनजर निस्तारित किया जाता है।

छ. पाटन मार्जिन का निर्धारण और उसकी क्रियापद्धति

37. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है :

- (i) मैसर्स बाह्रू स्टेनलेस मलेशिया; और
- (ii) मैसर्स लिआनझांग स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन, चीन; और
- (iii) मैसर्स सेंचुरी स्टील पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (निर्यातक)

38. कोरिया आरपी के किसी उत्पादक/निर्यातक से कोई प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। कतिपय हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्रतिभागिताकारी निर्यातक के खपत मानकों पर वर्तमान मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यात के देशों में सामान्य मूल्य का निर्धारण इस जांच में निर्यातकों की प्रतिभागिता के स्तर और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी के समक्ष रखी गई। खपत मानको आदि के आधार पर यथासंभव विश्वसनीय सूचना को उस सीमा तक प्रयोग किया गया है जहां तक वे सत्यापन योग्य साक्ष्य द्वारा समर्थित है। तदनुसार, कथित पाटन के दावे की जांच की गई और प्रत्येक देश के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नवत किया गया है :

ख.1 मलेशिया

39. प्राधिकारी द्वारा विश्लेषण किए गए आयात आंकड़ों के अनुसार 1584 एमटी संबद्ध वस्तु का आयात जांच की अवधि के दौरान मलेशिया से किया गया था। मलेशिया के केवल एक निर्यातक अर्थात् मैसर्स बाहरू स्टेनलेस स्टील ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया। इस प्रश्नावली प्रत्युत्तर की जांच की गई और निर्यातक से अनुपूरक जानकारी मांगी गई और निर्यातक ने अपने प्रत्युत्तर में कतिपय अनुपूरक सूचना प्रदान कर दी। इस निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर और आंकड़ों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई।

40. मैसर्स बाहरू स्टेनलेस स्टील ने प्रस्तुत किया कि यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका निगमन और मलेशिया में पंजीकरण 27 मार्च, 2008 को किया गया था। इसमें मैसर्स एक्रिनाक्स, एस ए., स्पेन और मैसर्स निशिन स्टील कंपनी, लिमिटेड की **** शेयरधारिता है। बाहरू की मलेशिया में मैसर्स एक्रिनाक्स एससी मलेशिया, एसडीएन बीएचडी (एक्रिनाक्स एससी) नामक एक संबद्ध कंपनी भी है, जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को इस संबद्ध वस्तु की अल्प मात्रा (**** एमटी) का निर्यात किया है।

41. मैसर्स बाहरू स्टेनलेस ने अपने प्रस्तुतिकरण में यह प्रस्तुत किया कि एक्रिनाक्स एससी ने अप्रैल 2013 में एक्रिनाक्स मलेशिया एसडीएन बीएचडी (एक्रिनाक्स मलेशिया) का अधिग्रहण किया था। एक्रिनाक्स मलेशिया ने भी जांच की अवधि के दौरान भारत को संबंधित उत्पाद का अल्प मात्रा में (**** एमटी) निर्यात किया था। एक्रिनाक्स मलेशिया एसडीएन बीएचडी का अधिग्रहण करने के पश्चात एक्रिनाक्स एससी मलेशिया एसडीएन बीएचडी ने सितम्बर, 2013 से भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात करना बंद कर दिया था।

42. इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुतिकरण किया गया कि एक्रिनाक्स एससी; मलेशिया एसडीएन बीएचडी और एक्रिनाक्स मलेशिया एसडीएन बीएचडी ने "हाट रोलड एन1 कॉइल" का अधिप्रापण कर लिया जो स्पेन, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए का एक परिष्कृत उत्पाद है और उसकी वांछित लंबाई प्राप्त करने के लिए उक्त सामग्री पर कुछ कटिंग प्रचालन किया। इस तरह की कटी हुई लंबाई के माल का भारत को निर्यात किया गया। एक्रिनाक्स एससी मलेशिया एसडीएन बीएचडी और एक्रिनाक्स मलेशिया एसडीएन बीएचडी द्वारा निर्यातित उत्पाद का उद्भव स्पेन, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए की बना रहा जहां से यह हाट रोलड नं. 1 कॉइल का अधिप्रापण किया गया था और वह दिनांक 25 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 104/2011-सीमा-शुल्क के तहत पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के अध्वधीन है। इसलिए बाहरू स्टेनलेस से संबद्ध इन दो कंपनियों अर्थात् मैसर्स एक्रिनाक्स एससी मलेशिया एसडीएन बीएचडी और मैसर्स एक्रिनाक्स मलेशिया एसडीएन ने इस जांच में भारत को किए गए अपने निर्यात का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

i) मैसर्स बाहरू स्टेनलेस, मलेशिया

43. मैसर्स बाहरू स्टेनलेस ने विस्तृत प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है और यह प्रस्तुत किया है कि उनका मुख्य क्रियाकलाप कोल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों का उत्पादन करना है। तथापि, उन्होंने भारत को स्टेनलेस स्टील (एन 1 उत्पादों) के हाट रोलड फ्लैट उत्पादों का निर्यात भी किया है, जो इस जांच के अंतर्गत उत्पाद के दायरे में कवर होता है। परंतु उनके द्वारा भारत को निर्यातित स्टेनलेस स्टील के हाट रोलड फ्लैट उत्पादों का "उद्गम का देश" मलेशिया नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि बाहरू स्टेनलेस ब्लैक कॉइल्स की मलेशिया के बाहर के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से खरीद करता है और फिर इन ब्लैक कॉइल्स पर एनीलिंग और पिकलिंग के कार्यकलाप किए जाते हैं। एनीलिंग और पिकलिंग करने के बाद इन कॉइल्स को अपेक्षित आकार में काटा जाता है और फिर उनकी भारत में ग्राहकों को आपूर्ति की जाती है। बाहरू स्टेनलेस द्वारा अधिप्राप्त ब्लैक कॉइल्स के लिए एचएस कोड और बाहरू स्टेनलेस द्वारा भारत को निर्यातित एन 1 उत्पादों का एचएस कोड समान है और प्रशुल्क शीर्षक (4 अंकीय सतर पर) या उप-शीर्षक (छह अंकीय स्तर पर) में कोई अंतर नहीं है। तदनुसार, बाहरू स्टेनलेस द्वारा भारत के निर्यातित स्टेनलेस स्टील के इन हाट रोलड फ्लैट उत्पादों के उद्गम का देश मलेशिया नहीं है बल्कि वह देश है जहां से इन ब्लैक कॉइल्स का अधिप्रापण किया जाता है। जांच की अवधि के दौरान बाहरू स्टेनलेस ने ब्लैक कॉइल का भारत को इस विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने के लिए दक्षिण अफ्रीका, जापान, स्पेन, कोरिया, चीन, सिंगापुर और हांगकांग में स्थित कई संबद्ध और असंबद्ध कंपनियों से अधिप्रापण किया था।

44. यद्यपि बाहरू के विनिर्माण निर्यात प्रचालन एक्रिनाक्स एससी मलेशिया एसडीएन बीएचडी और एक्रिनाक्स मलेशिया एसडीएन बीएचडी के विनिर्माण एवं निर्यात प्रचालनों से काफी भिन्न हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तथापि बाहरू द्वारा यह तर्क दिया गया कि उपर्युक्त प्रक्रियाओं ने मुश्किल से ही कोई मूल्य संवर्धन होता है, और यदि कोई, मूल्य संवर्धन किया भी जाता है तो वह दिनांक 31.12.2009 को अधिसूचना सं. 189/2009-सीमा-शुल्क (एनटी) के अंतर्गत अधिसूचित आशियान भारत उद्गम नियमावली एफटीए के अंतर्गत मलेशिया में उद्गम की स्थिति के रूप में कवालीफाई नहीं करता है। आशियान भारत उद्गम नियमावली एफटीए में दो अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं जिन्हें किसी सदस्य देश द्वारा एफटीए देश के

सदस्य से उद्गम का दर्जा प्राप्त करने की मांग करने और सीमा-शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिए पूरा किया जाना होता है। प्रथमतः, नियम 5(1)(i) में सदस्य एफटीए देश जैसे मलेशिया में कोई निकाय होना अपेक्षित है जो उस एफटीए देश के मूल के रूप में विचारित इसकी एफओबी कीमत के अनुपात के रूप में कम से कम 35 प्रतिशत मूल्य वर्धन कर सकता है। द्वितीयतः, नियम 5(1)(ii) में यह अपेक्षा की जाती है कि यदि गैर मूल के माल में प्रशुल्क उप-शीर्षक (सीटीएसएच) स्तर अर्थात् सुमेलीकृत प्रणाली के छह अंकीय स्तर तक परिवर्तन किया जाता है तो इस उत्पाद को मलेशिया के मूल के रूप में माना जाएगा।

45. इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया है कि कटिंग के कार्य से कोई उत्पाद आशियान-भारत उद्गम नियमावली के अंतर्गत मलेशिया के उद्गम का होने के लिए अर्ह नहीं हो जाता है, क्योंकि कटिंग कार्य को नियम 7(1)(ख) के अंतर्गत अपवर्जित किया गया है और यह ही वह कारण है कि बाह्रू आशियान भारत एफटीए के अंतर्गत कोई रियायती लाभ प्राप्त करने के लिए भारत में आयातकों को उद्गम का प्रमाणपत्र प्रदान नहीं करता है।

46. बाह्रू ने तर्क दिया है कि मलेशिया में संबद्ध उत्पाद का कोई उत्पादन नहीं होता है, इसलिए मलेशिया के विरुद्ध वर्तमान जांच को भारत की संगत प्रक्रिया और अन्य न्याय व्यवस्था के अनुसार समाप्त कर देना चाहिए।

47. बाह्रू ने पुनः यह तर्क दिया है कि बाह्रू और इसकी संबद्ध कंपनियां मलेशिया से संबद्ध वस्तु की केवल निर्यातक हैं और उन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद की केवल अल्प मात्रा का ही निर्यात किया है। इसके अतिरिक्त, मलेशिया से संबद्ध वस्तु का कोई अन्य निर्यातक नहीं है। बाह्रू ने शुरुआत में प्रश्नावली प्रत्युत्तर का केवल परिशिष्ट-2 ही दायर किया था, जो भारत को निर्यात बिक्री से संबंधित है। तथापि, तदुपरांत, अपूर्णता पत्र के प्रत्युत्तर में उन्होंने घरेलू बिक्रियों के विवरण सहित अन्य परिशिष्ट प्रस्तुत किए।

48. बाह्रू ने पुनः यह तर्क दिया कि जांच की अवधि के दौरान मलेशिया से संबद्ध उत्पादों के आयात की कुल मात्रा, याचिका में प्रक्षेपित 1584 एमटी की मात्रा की तुलना में 1232.02 एमटी ही है। इसलिए, जांच की अवधि के दौरान मलेशिया से संबद्ध उत्पाद की आयात मात्रा से संबंधित याचिका में प्रस्तुत किए गए आंकड़े तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि मलेशिया से संबद्ध उत्पादों के आयात कुल घरेलू मांग (ग्राही सहित) का 0.75 प्रतिशत ही है। यदि यह मान भी लिया जाए कि यह आंकड़े सही हैं तो भी मलेशिया के आयात 1 प्रतिशत से कम हैं, जो घरेलू उद्योग को कोई क्षति कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

घरेलू उद्योग के विचार

49. घरेलू उद्योग ने निर्यातक के इस दावे का विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि बाह्रू स्टेनलेस एसडीएन बीएचडी पर, यदि उक्त वस्तु का उत्पादन इसके सिस्टर कन्सर्न कोलम्बस स्टेनलेस (पीटीवाई) लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका द्वारा उत्पादन किया जाता है तो उस पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लगता हुआ है। वास्तव में, कोलम्बस स्टेनलेस (पीटीवाई) लिमिटेड, दक्षिण अफ्रीका (उत्पादक) तथा एक्रिनाक्स मलेशिया एसडीएन, बीएचडी (पैरेंट कंपनी) के संयोजन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है। यह बाह्रू की वार्षिक रिपोर्ट और स्वतंत्र रूप से प्रकाशित अन्य रिपोर्टों से स्पष्ट है कि ब्लैक कॉइल्स का अधिप्रापण इसके सिस्टर कन्सर्न अर्थात् कोलम्बस स्टेनलेस (पीटीवाई) लिमिटेड, दक्षिण अफ्रीका से किया जा रहा है। यह स्वीकार करके कि वे ब्लैक कॉइल्स का केवल आयात कर रहे हैं और मलेशिया में केवल अनीलिंग पिकलिंग प्रचालन ही करते हैं, यह निर्यातक दो भिन्न प्राधिकारियों के समक्ष दो भिन्न स्थितियों को प्रस्तुत कर रहा है अर्थात् (क) सीमाशुल्क प्राधिकारियों के समक्ष जहां यह घोषित किया गया है कि यह वस्तु मलेशिया मूल की है; और (ख) निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष, जहां यह दावा किया गया है कि निर्यातक उनका उत्पादक नहीं है, परंतु वह किसी अन्य देश में उत्पादित वस्तु का केवल निर्यातक है। जहां सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को पाटनरोधी शुल्क और वस्तु के उद्गम की अनुप्रयोज्यता के संबंध में समुचित कार्रवाई करने की जरूरत है वहीं, निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष मौजूदा आवेदन मलेशिया से संबद्ध वस्तु के निर्यात के बारे में है और इसलिए यह स्पष्टतः अनुरक्षणीय है क्योंकि आयात सांख्यिकी में आयातों को मलेशिया से होना दर्शाया गया है।

50. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भारत में किसी भी देश से होने वाले आयात पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया जाता है। विधि में ऐसी किसी संबद्ध देश के उत्पादकों तक कोई सीमा अंकित नहीं की गई है बल्कि इस देश के 'निर्यातक' तक भी संबंधित किया गया है। पाटनरोधी शुल्क उत्पादकों और निर्यातकों के संयोजन पर आधारित है। यदि यह मान भी लिया जाता है कि मलेशिया में इसका वास्तविक उत्पादन नहीं होता है तब भी किसी देश से संबद्ध वस्तु के न्यूनतम स्तर से अधिक के निर्यात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है। इस मुद्दे का निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा डीवीडी-आर, सीएफएल, सीडीआर जैसी विगत में की गई कुछ जांचों में स्पष्ट निर्धारण किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच एवं सामान्य मूल्य का निर्धारण

51. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मलेशिया के प्रतिवादी निर्यातक ने यह दावा किया है कि उनके द्वारा ब्लैक एचआर कॉइल्स का आयात कई देशों में कई विनिर्माताओं से कराया जाता है उनमें से कुछ उनके संबद्ध/ग्रुप कंसर्न हैं और उसको भारत को निर्यात करने पहले संसाधित किया जाता है। इसका घरेलू उद्योग द्वारा भी विरोध नहीं किया गया है। केवल मुद्दा जिसका विरोध किया जा रहा है वह यह है कि क्या उनके द्वारा मलेशिया में किए जा रहे अनीलिंग, पिकलिंग और स्लिटिंग कार्य भारत-आशियान एफटीए के अनुसार इस वस्तु को मलेशिया में उद्धृत वस्तु का दर्जा प्रदान करता है या नहीं। बाहरू ने दावा किया है कि उनके द्वारा किए जाने वाले अनीलिंग, पिकलिंग और स्लिटिंग कार्यों से एफटीए के अनुसार वस्तु के उद्धृत वस्तु का दर्जा प्रदान किया जा सकता है क्योंकि इससे इसमें विहित मूल्यवर्धन नहीं होता है और इससे प्रशुल्क शीर्षक (4 अंकीय स्तर तक) या उपशीर्षक (छह अंकीय स्तर तक) में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए, बाहरू का दावा है कि भारत को बाहरू स्टेनलेस द्वारा निर्यातित स्टेनलेस स्टील के हाट रोलड फ्लैट उत्पादों के उद्गम का देश मलेशिया नहीं हो जाता है बल्कि उसके उद्गम का देश वही रहता है जहां से ब्लैक कॉइल्स का अधिप्रापण किया गया है और इसलिए मलेशिया के विरुद्ध होने वाली जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

52. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि बाहरू ने सीमाशुल्क प्राधिकारियों के समक्ष यह दावा किया है कि यह वस्तु मलेशिया मूल की है क्योंकि डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़े इस वस्तु को मलेशियाई मूल का दर्शाते हैं और आयातक ने मलेशिया में निर्यातक द्वारा जारी उद्गम प्रमाणपत्र नियमावली के आधार पर एफटीए के अंतर्गत अधिमानी शुल्क का दावा किया है।

53. बाहरू ने प्रस्तुतिकरण किया है कि बाहरू भारत में किसी आयातक को भारत-आशियान एफटीए के अंतर्गत किसी रियायती लाभ का दावा करने के लिए मलेशिया में उद्गम दर्शाते हुए उद्गम प्रमाणपत्र प्रदान नहीं करता है। परंतु तथ्य यह है कि डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदान कराए गए आयात आंकड़े दर्शाते हैं कि यह वस्तु मलेशिया मूल की है, जिसका आशय यह है कि आयातक ने इस वस्तु की निकासी मलेशिया के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी उद्गम के प्रमाणपत्र के आधार पर मलेशिया के मूल की वस्तु के रूप में की है।

54. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने मलेशिया से निर्यातित वस्तु के तथाकथित उद्गम की गलत घोषणा के संबंध में और दक्षिण अफ्रीका, ईयू एवं यूएसए मूल की वस्तु पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क के संग्रहण का मामला राजस्व विभाग में उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष उठाया है।

55. यह कि क्या इस संबद्ध वस्तु के उद्गम की घोषणा मलेशियाई मूल की गलती से की गई है और इसकी निकासी भारत-आशियान एफटीए के अंतर्गत अधिमानी शुल्क व्यवस्था के रूप में की गई है, यह संबद्ध एजेंसियों/प्राधिकारियों द्वारा एक अलग जांच का मुद्दा है, इसलिए इस तथ्य से मना नहीं किया जा सकता है कि मलेशिया से निर्यातित वस्तु एफटीए के अंतर्गत उद्गम की नियमावली के अनुसार मलेशियाई मूल की नहीं है।

56. बाहरू का यह तर्क कि चूंकि यह वस्तु मलेशिया मूल की नहीं है, इसलिए मलेशिया के विरुद्ध जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, मलेशिया से निर्यात की जा रही वस्तु के तथ्यों के मद्देनजर प्रतिपाद्यनीय नहीं है। प्रतिवादी निर्यातक द्वारा ब्लैक कॉइल का अधिप्रापण विभिन्न देशों में कई विनिर्माताओं से किया गया और इन कॉइल्स में कुछ छोटी पूरी प्रोसेसिंग मलेशिया में की गई और उसके बाद फिर उसका भारत तथा अन्य देशों को निर्यात किया गया। इसलिए प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि बाहरू को संबद्ध वस्तु के उत्पादक के रूप में नहीं माना जा सकता है और उन्हें पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए व्यक्तिगत उपचार नहीं दिया जा सकता है।

57. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रतिवादी निर्यातक मैसर्स बाहरू स्टेनलेस स्टील के अलावा उसकी संबद्ध कंपनी मैसर्स एक्रिनाक्स एससी मलेशिया एसडीएन बीएचडी ("एक्रिनाक्स एससी") भी जांच की अवधि के दौरान **** एमटी का निर्यात किया था। एक्रिनाक्स मलेशिया ने भी जांच की अवधि के दौरान **** एमटी का निर्यात किया था। बाहरू द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों के अनुसार इन दोनों कंपनियों ने अब भारत को निर्यात करना बंद कर दिया है। इनमें से किसी भी पक्षकार ने अपने निर्यात के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए, मलेशिया के सभी निर्यातकों को असहयोगकर्ता के रूप में माना गया है और मलेशिया के सभी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

58. ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति के मद्देनजर मलेशिया में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए किसी अन्य तर्कसंगत प्रणाली के अभाव में प्राधिकारी ने मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य को विनिर्मित किया है। मलेशिया में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, जहां तक वह उपलब्ध थी, और घरेलू उद्योग की सर्वाधिकतम संपरिवर्तन लागत पर विचार किया गया है। मलेशिया में संबद्ध वस्तु के एक्स-वर्क्स स्तर पर भारित औसत सामान्य मूल्य का विनिर्माण करने के लिए लाभ के तर्कसंगत मार्जिन को जोड़ा गया है। तदनुसार, मलेशिया में इस विचाराधीन उत्पाद के लिए भारित औसत एक्स-वर्क्स कीमत का निर्धारण **** अमरीकी डालर/प्रति एमटी के रूप में किया गया है।

निर्यात कीमत

59. आयात आंकड़ों के अनुसार जांच की अवधि के दौरान मलेशिया से 137384/-रुपए (2512 अमरीकी डालर) प्रति एमटी की औसत सीआईएफ कीमत पर 1584 एमटी संबद्ध वस्तु का आयात किया गया था। सहयोगकर्ता निर्यातकों के प्रत्युत्तर में उपलब्ध सूचना में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतरदेशीय एवं समुद्री भाड़ा, और बीमा तथा बैंक प्रभारों एवं क्रेडिट लागत आदि सहित विक्री पश्चात होने वाले सभी व्ययों के लिए सीआईएफ कीमत का समायोजन करने के पश्चात एक्स-वर्क्स स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण ****यूएस डालर प्रति एमटी के रूप में किया गया है।

पाटन मार्जिन : मलेशिया

60. पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए एक्स-वर्क्स सामान्य मूल्य की तुलना एक्स-वर्क्स निर्यात कीमत से निम्नवत की गई है :

सीआईएफ	समायोजन	निर्यात कीमत	सीएनवी	पाटन मार्जिन	डीएम %
यूएस डालर/ एमटी	यूएस डालर/ एमटी	यूएस डालर/ एमटी	यूएस डालर/ एमटी	यूएस डालर/ एमटी	
2,512.05	****	****	****	****	10-20%

छ. 2 चीन जन.गण.

61. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विश्लेषण किए गए आयात आंकड़ों के अनुसार चीन ने जांच की अवधि के दौरान 30589 एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। तथापि, चीन की केवल एक उत्पादकर्ता कंपनी अर्थात् मैसर्स लिआनझांग स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन ("लिस्को") ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्रश्नावली प्रत्युत्तर के साथ-साथ एक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है। जांच की अवधि के दौरान लिस्को ने भारत में ****एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है जिसमें से ****एमटी का निर्यात मैसर्स सेंचुरी स्टील पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (सेंचुरी) के जरिए किया गया है। सेंचुरी ने लिस्को, चीन द्वारा विनिर्मित वस्तु के निर्यातक के रूप में एक पृथक प्रश्नावली प्रत्युत्तर भी दायर किया है।

i) मैसर्स लिआंगझांग स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन, चीन जन.गण.**लिस्को के बाजार अर्थव्यवस्था दावे की जांच**

62. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों एवं निर्यातकों में से एक मैसर्स लिआनझांग स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर और बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंडन किया है। प्रश्नावली प्रत्युत्तर और इस निर्यातक के एमईटी दावे के संबंध में प्रारंभिक जांच के आधार पर उन्हें दिनांक 14 अगस्त, 2014 के एक पत्र के तहत कतिपय अतिरिक्त सूचना/ स्पष्टीकरण मांगते हुए एक पत्र जारी किया गया था। निर्यातक ने अपने दिनांक 8 सितम्बर और 18 सितम्बर, 2014 के पत्रों के तहत कतिपय स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत की है।

63. लिस्को ने प्रस्तुत किया है कि वह एक उत्पादक एवं निर्यातक है जो केवल चीन में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और निर्यात करता है। लिस्को ने यह भी प्रस्तुतिकरण किया है कि चीन जनगण, जापान, कोरिया, यूरोपीयन यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान (चाइनीज ताइपेई) थाईलैंड और यूएसए से स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों की एक इससे पहले की पाटनरोधी जांच (दिनांक 24 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/06/2008-डीजीएडी) में लिस्को को प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया गया था।

64. प्रश्नावली प्रत्युत्तर के अनुसार लिस्को एक पूर्णतया विदेशी स्वामित्व का उद्यम था जिसकी स्थापना दिसम्बर, 2001 में इसकी ताइवान की मूल कंपनी यीह यूनाइटेड स्टील कारपोरेशन ("यूस्को") द्वारा की गई थी। लिस्को के शेयरों में यूस्को का **** प्रतिशत हिस्सा, ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में निगमित एक धारक कंपनी के जरिए और समोआ में निगमित एक अन्य धारक कंपनी के जरिए है। यूस्को में इन दोनों धारक कंपनियों का **** प्रतिशत स्वामित्व है। लिस्को की स्थापना की शुरुआत के समय प्रथम धारक कंपनी लिस्को की सोल (एकमात्र) शेयर होल्डर थी। इसने 8 जुलाई, 2002 को लिस्को के **** प्रतिशत

शेयर द्वितीय होल्डिंग कंपनी को अंतरित कर दिए गए। शेयरों के इस अंतरण के पश्चात पहली धारक कंपनी का लिस्को में **** प्रतिशत स्वामित्व रह गया और द्वितीय धारक कंपनी का लिस्को **** प्रतिशत स्वामित्व रह गया। धारक कंपनियों के बीच शेयरों के इस अंतरण से लिस्को की पूर्णतया विदेशी स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में विधिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। लिस्को और इसकी मूल कंपनी यूस्को दोनों ही ताईवान में "ई-यूनाइटेड ग्रुप" की सदस्य है। ई यूनाइटेड ग्रुप कोई विधिक निकाय नहीं है परंतु वह क्रास स्वामित्व वाले और/या मैसर्स आईएस लिन, यूस्को के अध्यक्ष द्वारा सामान्यतः नियंत्रित कंपनियों का एक ग्रुप है। स्टील उद्योग के अलावा ई यूनाइटेड ग्रुप शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रियल एस्टेट विकास आदि जैसे व्यवसायों में भी अंतर्गस्त है।

65. यह प्रस्तुत किया गया कि लिस्को को इसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा पूर्ण विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में नियंत्रित किया जाता है और यह लिस्को के संगम अनुच्छेदों में यथाविनिर्धारित निदेशक मंडल के संकल्प के आधार पर अपने लाभ एवं पूंजी को प्रत्यावर्तित करने के लिए स्वतंत्र है। लिस्को का चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के साथ, सरकार के मंत्रालयों या किसी भी स्तर के कार्यालय सहित, कोई संबंध नहीं है।

66. घरेलू उद्योग के इस प्रस्तुतिकरण का उत्तर देते हुए कि लिस्को को राज्य स्वामित्व वाले एक उद्यम द्वारा अधिग्रहीत किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, लिस्को ने पुनः यह प्रस्तुत किया है कि ताईवान मूल, के यीह यूनाइटेड स्टील कारपोरेशन की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में लिस्को के विधिक ढांच में वर्तमान जांच में जांच की अवधि के दौरान कभी कोई परिवर्तन नहीं आया है, जबकि यह सत्य है कि लिस्को इस वर्ष लिस्को के शेयरों के कुछ भाग को अवाप्त करने के लिए कई संभावित व्यवसाय भागीदारों (जिनमें ताईवान, कोरिया, जापान, चीन तथा कई अन्य देशों की कंपनियां शामिल हैं) के साथ वार्ता चल रही है। परंतु अभी तक इस मुद्दे पर कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है।

घरेलू उद्योग के विचार

67. घरेलू उद्योग ने अपने प्रस्तुतिकरण में यह तर्क दिया है कि चीन एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है और उसे पिछले तीन वर्षों में ऐसा यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और इस प्राधिकारी द्वारा भी माना गया है। यहां तक कि चीन भी अभिगमन संधि में इस बात से सहमत है कि डब्ल्यूटीओ सदस्य 11 दिसम्बर, 2016 तक एनएमई पाटनरोधी क्रियाविधि का उपयोग कर सकते हैं। घरेलू उद्योग ने पुनः यह तर्क दिया है कि :

- यह कि पाटनरोधी नियमावली में कुछ निश्चित शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनकी बाजार अर्थव्यवस्था उपचार के दावे को सिद्ध करने के लिए पूर्ति करनी पड़ती है। यह नोट किया जाता है कि बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने वाले प्रत्येक निर्यातक को प्रत्येक शर्त पूरी करनी चाहिए।
- यह कि केवल उनको छोड़कर जहां चीन के प्रतिवादी निर्यातक इन मानदंडों में से प्रत्येक मानदंड की संपुष्टित करते हैं निर्दिष्ट प्राधिकारी को सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली में अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार करना अपेक्षित होता है।
- यह कि भारत तथा अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे की जांच के संबंध में विभिन्न उद्घोषणाओं के आधार पर कुछ विधियां स्पष्टतः उभरकर सामने आई है और बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा कुछ शर्तों को पूरा/सिद्ध नहीं कर दिया जाता है, इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल है :
 - यह कि कोई बड़ा राज्य स्वामित्व/नियंत्रण नहीं होना चाहिए;
 - यह कि प्रमुख इनपुटों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित बाजार मूल्यों को पर्याप्ततः प्रदर्शित कर रही हो;
 - यह कि उनकी बहियों की लेखापरीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानकों के अनुरूप की जाती हो।
- यह कि चीन के किसी भी प्रतिवादी निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता है जब तक चीन के निर्यातक नियमों में निर्धारित प्रत्येक पैरामीटर को पूरा नहीं कर लेते हैं। चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध करें कि वे बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता है जब तक प्रतिवादी कंपनी और उसका ग्रुप समग्र रूप से इसका दावा नहीं करते हैं। यदि इस समूह का भाग बनने वाली किसी एक या अधिक कंपनियों ने प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है तो उसके बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे को नामंजूर किया जा सकता है।
- यह कि कई ऐसी समाचार मंदा हैं जो यह दर्शाती है कि अंशटील ग्रुप लिस्को में 60 प्रतिशत पण अवाप्त करने वाला है। अंशटील ग्रुप, चीन आधारित एक बड़े आकार का स्टील उत्पादन ग्रुप है, राज्य के स्वामित्व वाला एक उद्यम है और

उसे "चीन के इस्पात उद्योग का पालना (क्रेडल)" होने की ख्याति मिली हुई है और उसे "एलडेस्ट सन आफ दि रिपब्लिक्स स्टील इंडस्ट्री" के नाम से जाना चाहिए है। यह तर्क दिया गया है कि इसके 60 प्रतिशत शेयर राज्य स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा धारित किए जा रहे हैं अतः यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और निर्यातक की इस विधिक स्थिति में प्रस्तावित परिवर्तन का इस मामले पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- यह कि इस विचाराधीन उत्पाद की कुल उत्पादन लागत का 87 प्रतिशत कच्चे माल के रूप में होता है और इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि क्या इन इनपुटों की कीमतें तर्कसंगत ढंग से बाजार मूल्यों को प्रतिबिम्बित कर रही है। निर्यातक ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि निर्यातक द्वारा उपभोग की गई इनपुटों की कीमतें तर्कसंगत ढंग से बाजार मूल्यों को परावर्तित कर रही है। वास्तव में निर्यातक ने यह माना है कि एक प्रमुख कच्चे माल अर्थात् स्टील स्क्रेप का अधिप्रापण इसकी दो संबद्ध कंपनियों से किया जाता है। इस कंपनी के कच्चे माल की खरीद अन्य स्थानीय घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से भी की जाती है जो बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति के अंतर्गत प्रचालन नहीं कर रहे हैं।
- यह कि लिस्को को सर्वसम्मति से चीन की कीमत निर्धारण विधि द्वारा शासित किया जाता है जिसका निरूपण समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था का संवर्धन करने के लिए किया जाता है। इस विधि के अनुच्छेद 6 में स्वयं कीमत निर्धारण नीति बनाने का प्रावधान है। इसका अपवाद अनुच्छेद 18 में दिया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि "सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण पण्य वस्तुओं के लिए सरकार के सेट या मार्गदर्शित कीमतें जारी करेगी। स्टील उद्योग निश्चित रूप से एक अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पण्य है और उपर्युक्त अनुच्छेद के मद्देनजर स्टील की कीमतों पर राज्य द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है।
- यह कि चीन की सरकार ने चीन में विकास के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बड़े उद्योगों, उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का एक सूचीपत्र में "लोहा एवं इस्पात", "लो अलायस्टील और माइक्रो अलाय स्टील", "स्टेनलेस स्टील स्मेल्टिंग", "हाट एंड कोल्ड रोलिंग स्टेनलेस स्टील शीट" "प्रासेसिंग एंड ट्रीटमेंट आफ स्क्रेप स्टील" को प्रोत्साहित उद्योग के रूप में अभिज्ञात किया है।
- यह कि प्रोत्साहित विदेशी निवेश उद्योग के सूचीपत्र में "निकेल सेविंग स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स का विनिर्माण, "कोल्ड फायर्ड पावर प्लांट एंड डि-निट्रीफिकेशन फार सिन्टरिंग मशीन इन स्टील इंडस्ट्री के उपकरणों का विनिर्माण" को प्रोत्साहित उद्योग के रूप में अभिज्ञात किया है।
- यह कि चीन सरकार ने लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास करने के लिए नीतियों की उद्घोषणा की है जिनमें स्टील उद्योग को कई सुविधाएं देने का प्रावधान है।

प्राधिकारी द्वारा जांच और सामान्य मूल्य का निर्धारण (लिस्को)

68. यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंड किया जा सकता है यदि चीन के निर्यातक पैरा 8 के उप-पैराग्राफ 3 में विनिर्दिष्ट मापदंड के आधार पर सूचना एवं पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करते हैं और इसके विपरीत सिद्ध कर देते हैं। चीन जनवादी गणराज्य के संबद्ध वस्तु के सहयोगकर्ता उत्पादकों/निर्यातकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्रश्नावली के प्रत्युत्तर के पैरा 8 के उप-पैराग्राफ (3) में यथा-उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रदान कराए जिससे निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित प्रक्रिया पर विचार कर सकें कि क्या :

- (क) चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों की कीमत, लागत और इनपुट के संबंध में जिसमें कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत शामिल है, आउटपुट, बिक्री के संबंध में निर्णय उन बाजार संकेतकों के प्रत्युत्तर में किए जाते हैं जिनमें इस संबंध में राज्य के भारी हस्तक्षेप के बिना मांग एवं आपूर्ति प्रदर्शित होती हो और क्या बड़े इनपुटों की लागत पर्याप्ततः बाजार मूल्यों को प्रदर्शित करती है।
- (ख) इन फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति इससे पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से की गई भारी विकृतियों के और खासकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते में डाले गए, बार्टर व्यापार और ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान के अध्यधीन है।
- (ग) यह फर्में दिवालियापन और संपत्ति विधियों के अध्यधीन है जो इन फर्मों का प्रचालन करने के लिए स्थिरता और विधिक निश्चितता की गारंटी प्रदान करती है।
- (घ) विनिमय दर संपरिवर्तन बाजार दर पर किया जाता है।

69. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लिस्को को कतिपय कोल्ड रोल्ड स्टील उत्पादों के संबंध में वर्ष 2009 में आयोजित की गई पिछली जांचों में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया गया था। लिस्को ने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुतिकरण में यह तर्क दिया है कि तब से प्रबंधन या व्यवसाय के ढांचे के रूप में कंपनी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यद्यपि लिस्को के शेयर के कुछ भाग को अवाप्त करने के लिए इसके कई व्यवसाय भागीदारों (ताईवान, कोरिया, तापान, चीन तथा कई अन्य देशों में) के साथ वार्ता चल रही है परंतु कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है।

70. कंपनी द्वारा प्रदान कराई गई सूचना का चीन में दिनांक 29-30 जनवरी, 2015 को स्थल सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान कंपनी ने यह सूचित किया कि लिस्को के **** प्रतिशत हिस्से को दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को चीन जन.गण. के एक राज्य स्वामित्व वाली कंपनी मैसर्स एन्स्टील ग्रुप कारपोरेशन ने अधिग्रहीत कर लिया है और तदनुसार इस कंपनी का नाम साइनो-फारेन संयुक्त उद्यम सीमित देयता के रूप में मैसर्स एन्स्टील लिआन्झांग स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन के रूप में परिवर्तित हो गया है और इसकी पंजीकृत पूंजी **** आरएमबी है। इस अधिग्रहण के उपरांत इस कंपनी की शेयरधारिता की स्थिति निम्नवत है : ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स में पंजीकृत पब्लिक जोन कंपनी लिमिटेड **** प्रतिशत; एन्स्टील ग्रुप कारपोरेशन, चीन **** प्रतिशत और वैलीफील्ड लिमिटेड, समोआ **** प्रतिशत यह भी नोट किया गया कि इस अधिग्रहण से बोर्ड के संघटन में भी परिवर्तन हुआ है। अब बोर्ड में सात सदस्य हैं जिनमें चार सदस्य एन्स्टील का, दो सदस्य पब्लिक जोन कंपनी का और एक सदस्य वैलीफील्ड लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी द्वारा यह उल्लेख किया गया कि एन्स्टील चीन में एक प्रमुख कार्बन स्टील का उत्पादक है और इस अधिग्रहण के साथ वह स्टेनलेस स्टील व्यवसाय में विविधीकरण कर रहा है।

71. कंपनी ने यह भी सूचना दी है कि वे शीघ्र ही प्राधिकारी के समक्ष अपेक्षित दस्तावेज दायर करेंगे जिनमें इस विकास और स्थिति में परिवर्तन के साथ-साथ कंपनी के नाम में हुए परिवर्तन की सूचना दी जाएगी और लिस्को द्वारा विगत में किए गए प्रस्तुतिकरणों के स्थान पर नए निकाय अर्थात् मैसर्स एन्स्टील लिआन्झांग स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन की ओर से प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।

72. उपर्युक्त के आलोक में कंपनी द्वारा जांच की अवधि के दौरान विनिर्मित संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उत्पादन प्रक्रिया की जांच की गई। निर्यात द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की जांच से यह संकेत मिलता है कि इसने अधिकांश कच्चे माल का अधिप्रापण स्थानीय रूप से अपनी सहबद्ध एवं असहबद्ध कंपनियों से किया है। कच्चे माल के अधिकांश भाग की खरीद चीन में असंबद्ध आपूर्तिकर्ताओं से की गई है। चीन में असहबद्ध आपूर्तिकर्ताओं से अधिप्राप्त प्रमुख कच्चे माल की कीमतों की तुलना उन कीमतों से करने पर जिन पर वस्तुओं को चीन के बाहर से तथा सहबद्ध आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया गया है तो भारी अंतर प्रतीत होता है। चीन में कच्चे माल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं की बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है और निर्यातक द्वारा विभिन्न स्रोतों से अवाप्त विभिन्न कच्चे माल की कीमतों का अंतर यह दर्शाता है कि निर्यातक द्वारा चीन में संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए अवाप्त कच्चे माल की लागत और कीमत वस्तु के बाजार मूल्य की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कंपनी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कच्चा माल बिक्री लागत का एक बड़ा भाग (82 प्रतिशत) बनता है। इसलिए इस उत्पादक/निर्यातक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत विश्वसनीय नहीं है और उसपर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

73. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। अनुबंध-1 का पैरा 7 निम्नवत पठित है :

"पैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था में निर्मित मूल्य या कीमत या ऐसे तृतीय देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत के आधार पर अथवा जहां यह संभव नहीं है वहां किसी अन्य न्यायोचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक प्रदत्त या देय कीमत जिसका तर्कसंगत लाभ मार्जित शामिल करने के लिए यथावश्यक समायोजन किया गया हो, भी शामिल हो, किया जा सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास का स्तर तथा प्रश्नाधीन उत्पाद को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्थायुक्त तृतीय देश का चयन किया जाना चाहिए और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय जानकारी को उचित रूप से ध्यान में रखना चाहिए। किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में किसी समान मामले में की गई जांच, यदि उपयुक्त हो, की लेखाओं पर समय-सीमा के अंतर्गत विचार किया जाना चाहिए। उपर्युक्त बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के चयन की जानकारी जांच के पक्षकारों को अविलंब दी जानी चाहिए और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उपयुक्त समयावधि दी जानी चाहिए।"

74. उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में घरेलू बिक्री कीमत या बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में संरचित मूल्य या ऐसे तृतीय देश से भारत सहित किसी अन्य देश को निर्यातक कीमत के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। तथापि, यदि ऊपर उल्लिखित विकल्पों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर कर सकते हैं, जिसमें तर्कसंगत लाभ मार्जिन का समायोजन करने के लिए विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय कीमत शामिल है।

75. किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में संबद्ध वस्तु की भरोसेमंद कीमत और लागत विवरण के अभाव में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन में सामान्य मूल्य का विनिर्माण समान उत्पादन के लिए भारत में वास्तव में संदत्त या संदेय कीमत के आधार पर, लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, विधिवत समायोजन के आधार पर किया गया है। तदनुसार चीन में सभी निर्यातकों द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य **** अमरीकी डालर/एमटी निर्धारित किया गया है।

निर्यात कीमत : मैसर्स एन्स्टील लिस्को, चीन, मैसर्स सेंचुरी स्टील पीटीई सिंगापुर के जरिए

76. लिस्को ने जांच की अवधि के दौरान भारत को **** एमटी संबद्ध वस्तु के निर्यात की सूचना दी है। भारत में इस वस्तु का निर्यात हांगकांग, ताईवान और सिंगापुर में 4 असहबद्ध निर्यातकों के जरिए किया गया है। जांच की अवधि के दौरान निर्यात की गई कुल मात्रा में से **** एमटी का निर्यात मैसर्स सेंचुरी स्टील लिमिटेड पीटीई सिंगापुर के जरिए किया गया जिसने एक पृथक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है। लिस्को द्वारा जांच की अवधि के दौरान भारत को आयातित शेष मात्रा के किसी भी अन्य निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत के इस उत्पादक द्वारा निर्यातित वस्तु के मामले में निर्यात की कुल मूल्य श्रृंखला पूरी नहीं की है और संपूर्ण श्रृंखला पूरी हुए बिना निर्यात कीमत का निर्धारण करना संभव नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि लिस्को को जांच की अवधि के दौरान निर्यातित वस्तु के लिए पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण करने हेतु व्यक्तिगत उपचार प्रदान नहीं किया जा सकता है।

77. चीन के किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। जांच की अवधि के दौरान चीन से आयात आंकड़ों के अनुसार 30589 एमटी का निर्यात हुआ जिसकी सीआईएफ कीमत 138236/- (2527.62 यूएस डालर) प्रति एमटी है। इस सीआईएफ कीमत का समायोजन सभी एक्स वर्क्स व्ययों जैसे अंतरदेशीय एवं समुद्री भाड़ा और बीमा, बैंक प्रभार तथा क्रेडिट लागत आदि के लिए और सहयोगकर्ता निर्यात के आंकड़ों से उपलब्ध सूचना के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर 4 प्रतिशत के विभेदकारी वैट के लिए समायोजन किया गया। तदनुसार चीन के सभी निर्यातकों के लिए एक्स-वर्क्स निवल निर्यात कीमत **** यूएस डालर प्रति एमटी है।

पाटन मार्जिन : चीन

78. एक्स वर्क्स स्तर पर इस तरह निर्धारित एक्स-वर्क्स सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना चीन के सभी निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन से की गई है जो निम्नवत है :

सीआईएफ	समायोजन	ईपी	सीएनवी	डीएम	डीएम %
यूएस डालर/ एमटी	यूएस डालर/ एमटी	यूएस डालर/ एमटी	यूएस डालर/ एमटी	यूएस डालर/ एमटी	
2527.62	****	****	****	****	10-20%

छ. 3 कोरिया आरपी

79. कोरिया आरपी के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध आयात आंकड़ों के अनुसार जांच की अवधि के दौरान कोरिया आरपी से 3813 एमटी संबद्ध वस्तु का आयात किया गया था। कोरिया का एक प्रमुख विनिर्माता पास्को ने प्राधिकारी के समक्ष अपने सीमित प्रस्तुतिकरण में यह तर्क दिया कि इस जांच से उसका अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए। तथापि, इन तर्कों को असाध्यांकित पाया गया।

80. न तो पास्को ने और न ही कोरिया के किसी अन्य उत्पादक या निर्यातक में अपने सामान्य मूल्य या निर्यात कीमत के संबंध में कोई सूचना दी है। इसलिए प्राधिकारी ने कोरिया के सभी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है।

कोरिया आरपी में सामान्य मूल्य

81. कोरिया आरपी के उत्पादकों/निर्यातकों से किसी भी सहयोग के अभाव में और किसी अन्य ऐसी विश्वसनीय सूचना के अभाव में जो निर्यात देश की घरेलू बाजार में या तृतीय देशों को निर्यात की वास्तविक लागत और कीमत के आधार पर कोरिया आरपी में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का आधार बन सके, प्राधिकारी ने कोरिया आरपी के लिए सामान्य मूल्य निर्धारण कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, उस सीमा तक जिस तक वे उपलब्ध थीं और घरेलू उद्योग की सर्वाधिक कार्यकुशल संपरिवर्तन लागत पर विचार किया है। कोरिया आरपी में एक्स वर्क्स स्तर पर संबद्ध वस्तु के भारित औसत विनिर्मित सामान्य पर पहुंचने के लिए तर्कसंगत लाभ मार्जिन को जोड़ा गया है। तदनुसार कोरिया आरपी में इस विचाराधीन उत्पाद के लिए भारित औसत एक्स-वर्क्स सामान्य मूल्य **** यूएस डालर प्रति एमटी निर्धारित किया है।

निर्यात कीमत : कोरिया आरपी

82. कोरिया आरपी में सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के लिए आईबीआईएस से प्राप्त सौदावार आंकड़ों में परावर्तित आयात कीमत के आधार पर किया गया है। आयात आंकड़ों में प्रतिबिम्बित इस औसत सीआईएफ कीमत का समायोजन एक्स-वर्क्स निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतरदेशीय एवं समुद्री भाड़ा एवं बीमा प्रहस्तन और अन्य विक्री व्ययों के लिए किया गया है। तदनुसार, कोरिया आरपी के सभी निर्यातकों के लिए एक्स-वर्क्स औसत भारित निर्यात कीमत **** यूएस डालर प्रति एमटी निर्धारित की गई है।

पाटन मार्जिन : कोरिया आरपी

83. पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ भारित औसत एक्स-वर्क्स सामान्य मूल्य और भारित औसत निवल एक्स-वर्क्स निर्यात कीमत की तुलना व्यापार के समान स्तर से की गई। कोरिया आरपी के निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नवत है :

सीआईएफ	समायोजन	ईपी	सीएनवी	डीएम	डीएम %
यूएस डालर/ एमटी	यूएस डालर/ एमटी	यूएस डालर/ एमटी	यूएस डालर/ एमटी	यूएस डालर/ एमटी	
2,656.73	****	****	****	****	5-15 %

84. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के लिए इस तरह निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक एवं पर्याप्त है।

ज. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों का निर्धारण

85. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में वे सभी कारक अंतर्ग्रस्त किए जाएंगे जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत मिलता हो। ".....पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु पर उन कीमतों के प्रभाव और इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों पर विचार करते हुए कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह आवश्यक समझा जाता है कि यह जांच की जाए कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन हुआ है अथवा इन आयातों के प्रभाव से कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण होगा या यह कीमतों में वृद्धि होने से वंचित कर रही है जो अन्यथा भारी मात्रा घटित हुआ होता।

86. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के लिए आवेदनपत्र मैसर्स ज़िंदल स्टेनलेस स्टील द्वारा दायर किया गया है जो भारत में इस संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन के बड़े अनुपात का उत्पादन करते हैं। नियमावली के नियम 2(ख), के अनुसार याचिकाकर्ता को इस जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है। इसलिए इस निर्धारण के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता की लागत एवं क्षति सूचना की, नियम 2(ख) में यथापरिभाषित घरेलू उद्योग के रूप में जांच की गई है।

ज. 1 घरेलू उद्योग के क्षति के दावे के संबंध में निर्यातकों आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

87. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि कोरियाई निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है तथापि उन्होंने प्राधिकारी के समक्ष कतिपय क्षति प्रस्तुतिकरण दायर किए हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी घरेलू उद्योग की क्षति एवं

कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त प्रस्तुतिकरण किए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा दावाकृत क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

- यह कि कोरिया के निर्यातकों ने भारत को इस विचाराधीन उत्पाद का निर्यात तथाकथित पाटित कीमतों पर नहीं किया है या वे केवल क्षति के संबंध में प्रस्तुतिकरण दायर की रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि याचिकाकर्ता को वास्तविक क्षति को छोड़कर, कोई अन्य क्षति नहीं हुई है;
- यह कि याचिकाकर्ता जब भी वह अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाता है, चाहे वह कोल्ड रोलड या हाट रोलड स्टेनलेस स्टील उत्पादों के लिए हो तब वह क्षति का दावा करते हुए संरक्षण की मांग करते हुए भारत सरकार के पास पहुंचाने का आदी है। यह कई जांचों से स्पष्ट है जहां याचिकाकर्ता ने व्यापार उपचारी साधनों का दुरुपयोग करके अपने लाभ के लिए त्रुटिपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत करके याचिका दायर की है।
- यह कि याचिकाकर्ता ने पिछली जांचों में अपने क्षमता विस्तार और क्षमता उपयोग के संबंध में असत्य एवं भ्रामक सूचना दी। वर्तमान जांच में भी याचिकाकर्ता ने यह दर्शाया है कि इसने अपनी क्षमता में वृद्धि की है परंतु याचिकाकर्ता इस मुद्दे पर अभी भी चुप है कि क्या इसका वाणिज्यिक उत्पादन स्थिर हुआ या नहीं। याचिकाकर्ता से यह पूछा जाए कि वह संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराए कि इस विचाराधीन उत्पाद के लिए संस्थापित क्षमता आकलन उसने ऐसी स्थिति में कैसे किया जब उसके लिए कोई समर्पित संयंत्र क्षमता नहीं है।
- यह कि याचिकाकर्ता ने एसटीएसएचआर 304 के संवर्धित आयातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है और जानबूझकर वास्तविक क्षति की खोज की है जो न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है बल्कि वह मौजूदा भी नहीं है। इसके विपरीत याचिकाकर्ता ने पिछले एक वर्ष में अपनी क्षमता में लगभग 100 प्रतिशत का विस्तार कर लिया और वह रैम्प-अप समस्या के कारण उसे पूर्णतया प्रचालनात्मक बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है।
- यह कि प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के क्षमता उपयोग में गिरावट को लिए दिए गए कारणों पर और क्षति के लिए अन्य कारणों पर समुचित रूप से विचार करना चाहिए और उन्हें क्षति तथा अन्य कारकों के बीच कारणात्मक संबंध भी प्राप्त करने का प्रयास करें।
- यह कि याचिकाकर्ता का हिसार संयंत्र, जो पूर्णतया सुस्थापित है, अपनी 90 प्रतिशत उपयोगिता के साथ प्रचालनात्मक है जबकि ओडिशा संयंत्र जो वर्ष 2011 में शुरू किया गया था, 15 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा है। ओडिशा संयंत्र का निम्नतर क्षमता उपयोग इस तथ्य के कारण है कि ओडिशा संयंत्र के अंतर्गत स्टेनलेस स्टील के उत्पादन की क्षमता रैम्प-अप के अधीन है और उसे अभी स्थिर किया जाना है। याचिकाकर्ता को तथाकथित घाटा इस अस्थिर उत्पादन पर उपरोपित किया जा सकता है, न कि संवर्धित आयातों पर जैसा कि उन्होंने अपनी विभिन्न अंकेक्षित न की गई रिपोर्टों और प्रेस रिलीजों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है।
- यह कि आधार वर्ष से कुल आयातों में ग्राही खपत सहित मांग के रूप से कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, मांग में निरंतर उच्च वृद्धि की शर्त के अंतर्गत विगत वर्ष तथा जांच की अवधि के दौरान कुल आयातों की तुलना पर संगत रूप से और समग्र रूप से दोनों तरह से विचार किया जाना चाहिए, जो व्यापक तौर पर कुल आयातों में कमी का संकेत देता है।
- यह कि कोरिया मूल की 540 एमटी संवर्धित मात्रा बहुत कम है और इसका जांच की अवधि के दौरान 168510 एमटी के आकार की मांग युक्त एसटीएस एचआर 304 की कुल भारतीय बाजार को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है।
- यह कि यद्यपि कुल मांग में 24331 एमटी तक की वृद्धि हुई है, वहीं कोरिया से आयातित एसटीएस एचआर 304 की मात्रा केवल 540 एमटी ही है, इस वृद्धि को बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता है।
- यह कि जांच की अवधि के दौरान भारतीय बाजार में कुल 168510 एमटी की मांग की तुलना में कोरिया से केवल 3052 एमटी का ही आयात किया गया है, यह संदेहास्पद है कि किस तरह कुल मांग की केवल 1.8 प्रतिशत मात्रा संपूर्ण भारतीय बाजार में इतनी बहुरी तरह से प्रभावित कर सकती है कि उसे इसमें "वास्तविक क्षति" कारित होने लगे।
- यह कि इस जांच में संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के संवर्धित बाजार हिस्से की प्रकृति पर और यूरोपियन यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान और यूएसए से निर्यातित सभी आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क द्वारा एसटीएस एचआर 304 के आयातों के बीच बाजार हिस्से के पुनर्वितरण पर सोच समझकर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। इस कारण से प्राधिकारी को चाहिए कि वि संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि को घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के किसी कारण या क्षति के प्रतीक के रूप में नहीं मानना चाहिए।

- यह कि सीईपीए से होने वाले लाभ के रूप में कोरियाई निर्यातक भारत के निर्यात किए गए उत्पादों पर, यदि उनके उत्पाद उदगम के नियमों के अंतर्गत अर्ह होते हैं तो, अधिमानी शुल्क दर प्राप्त करने के पात्र हैं। इस संबंध में, कोरिया के तथा भारत के कई उत्पादकों इस सीईपीए से लाभ हुआ है, जिसमें पास्को भी शामिल है। दूसरे शब्दों में पास्को ने सीमाशुल्क दर में कटौती से संबंधित लाभों को प्राप्त किया है तथा इसने प्रभावी वर्ष 2010 से 540 एमटी की आयात मात्रा में वृद्धि की है।
- यह कि कोरिया आयातित एसटीएस एचआर 304 की संवर्धित मात्रा को सीईपीए के एक सकारात्मक प्रभाव के रूप में मानना चाहिए न कि भारतीय घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के एक कारण के रूप में मानना चाहिए।
- यह कि प्राधिकारी को क्षति जांच अवधि के दौरान, जो वर्ष 2011 का लगभग पहला अर्धार्ध है, निकिल की कीमतों में भारी गिरावट पर एक ऐसे संवेदनशील कारक के रूप में विचार करना चाहिए जिसके कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और आयातों की उतराई कीमत में गिरावट आई।
- यह कि कोरिया से एसटीएस एचआर 304 के आयातों का भारतीय घरेलू उद्योग पर कीमत अधोरदन का गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि कोरिया से एसटीएस एचआर 304 के आयातों के परिणामस्वरूप न ही कीमत निग्रहण हुआ है और न ही कीमत अवमंदन।
- यह कि याचिकाकर्ता के उत्पादन और उसकी बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के उस तर्क को इस जांच में क्षति विश्लेषण के लिए नकार दिया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग को उत्पादन और बिक्री के रूप में क्षति हुई है।
- यह कि इस जांच में घरेलू उद्योगों को होने वाली क्षति के प्रमुख कारणों का सावधानी से विश्लेषण करना चाहिए। क्षमता उपयोग में गिरावट के संबंध में कोरिया से होने वाले आयात एक कारण नहीं हो सकते हैं। इसके विपरीत, नया उत्पादन भिन्न स्थापित करने के संबंध में प्रबंधकीय निर्णय की बाजार भविष्यवाणी में गलती को याचिकाकर्ता के क्षमता उपयोग में गिरावट के लिए एक कारण माना जा सकता है।
- यह कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पाटन के कारण बाजार हिस्से में 17.30 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान गलत हालत में किया गया गलत परिकलन है। याचिका में यह परिकल्पना अनन्य तथ्यों पर विचार किए बिना की गई है कि जिन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगा है उससे न होने वाले आयातों के कारण बाजार हिस्से की अनुपस्थिति स्वतः ही अंतरित हो जाएगी, जो ग्राहकों के क्रय निर्णय तथा उसके उपरांत बाजार हिस्से को प्रत्यक्षतः या प्रमुखतः प्रभावित करते हैं।
- यह कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने विभिन्न वित्तीय विवरणों में किए गए उल्लेख के अनुसार सम्बर्धित उत्पादन लागत के कारणों में से एक कारण यू एस डालर की तुलना में भारतीय रूपए का अवमूल्यन होना है।
- यह कि उत्पादन लागत में वृद्धि होने का एक अन्य सम्भावित कारण श्रम लागत में वृद्धि होना है। अन्य सम्भावित कारणों में विनिर्माण उपरिशीर्षों की मदों जैसे मूल्यहास और परिशोधन व्यय तथा विद्युत एवं ईंधन व्यय है।
- यह कि पास्को ने जांच की अवधि के दौरान एसटीएसएचआर 304 की उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं की है। यद्यपि पास्को के निजी निगम, झांगजियांगंग पोहांग स्टेनलेस स्टील कंपनी लि. (जिसे एतदपश्चात जेडपीएसएस कहा गया है) चीन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई थी, परन्तु जेडपीएसएस ने क्षति जांच अवधि के दौरान भारत को एसटीएस एच आर 304 का निर्यात नहीं किया है। अतः कोरिया से आयात के परिणामस्वरूप क्षति की चुनौती की कोई संभावना नहीं है।
- यह कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका में प्रथम दृष्टया कारणात्मक संबंध के साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिसके अभाव में एकमात्र कारक जिसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई वह है स्वयं का पैदा किया हुआ कुप्रबंधन और उसका कोरिया के आयातों से कोई संबंध नहीं है।
- यह कि एसटीएस एचआर 304 पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से एसटीएस एचआर के उपभोक्ता उद्योग पर घातम प्रभाव पड़ेगा जिससे उन्हें अपने कच्चे माल की खरीद शेष जगत से उच्चतर कीमतों पर करनी होगी। क्रय कीमत अधिक होने के कारण भारत में एसटीएस एचआर 304 की उपभोक्ता निकायों की विनिर्माण लागत बढ़ जाएगी।

- यह कि जिंदल की हिसार में हाट रोलिंग मशीन है जिसकी क्षमता 750000 टन प्रतिवर्ष है, इससे वे 1000 एमएम और 1250 एमएम की चौड़ाई के कॉइल्स का विनिर्माण करते हैं जबकि चीन जैसे देशों में फैक्टरियां अधिकांशतः कम मोटाई के कॉइल्स, 400 एमएम से लेकर 700 एमएम तक की मोटाई के कॉइल्स का निर्माण करती है और उनकी अनुमानित क्षमता 1000000 टन प्रति वर्ष है, जिससे उन्हें लागत लाभ प्राप्त होता है। इन परिस्थितियों के अंतर्गत जिंदल की उत्पादन लागत की तुलना चीन के उत्पादकों की उत्पादन लागत के साथ नहीं की जा सकती है।
- यह कि जिंदल को एक कार्यकुशल उत्पादक के रूप में मानना चाहिए और यदि उनको कोई क्षति होनी है तो वह उनकी अपनी अक्षमता के कारण और उत्पाद मिक्स के कारण होती है, न कि सम्बद्ध देशों से किसी पाटन के कारण;
- यह कि रिकार्ड में उपलब्ध आवेदन में घरेलू उद्योग को सम्बद्ध देशों से कथित पाटन के कारण कोई वास्तविक क्षति नहीं होती है अतः वर्तमान जांच को बिना किसी अन्य कारण के समाप्त किया जा सकता है;
- अपनाया जाने वाला रिटर्न तर्कसंगत होना चाहिए न कि प्राक्कल्पित लगाई गई पूंजी के दोनों संघटनों पर समान रूप से 22 प्रतिशत को अपना कर प्रतिलाभ का परिकलन करना पूर्णतया गलत है;
- यह कि सम्बद्ध देशों से आयात की मात्रा में वर्ष 2010-11 और 2011-12 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है। तथापि, उसी अवधि के दौरान घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री में भारी वृद्धि हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सम्बद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।
- यह कि ऐसी स्थिति में जहां सम्बद्ध देशों से आयातों में गिरावट आई है और उसी अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की बिक्री में वृद्धि हुई है, इससे याचिकाकर्ता द्वारा क्षति का सारा दावा ध्वस्त हो जाता है। आयातों और याचिकाकर्ता के बीच इस तरह का प्रतिलोभित संबंध ही इस जांच को सिरे से खारिज कर देने के लिए पर्याप्त है;
- यह कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2011-12 और जांच की अवधि के दौरान भारी क्षमता विस्तार किया है। यह स्पष्ट है कि इतनी अधिक मात्रा में की गई क्षमता विस्तार का वाणिज्यीकरण तत्काल नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह भी दर्शाता है कि क्षमता में यह विस्तार याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध बेशी क्षमता और बाजार की स्थिति पर विचार किए बिना, बिना सोचे-विचारे किया गया है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि क्षमता सम्वर्धन में भारी वृद्धि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का प्रधान कारण है।
- यह कि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग ने जांच की अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। तथापि, उत्पादन में वृद्धि की भारी प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। स्पष्टतः क्षमता उपयोग के संबंध में विपरीत निष्पादन का एक कारण संयंत्र क्षमता में वृद्धि होना है, और कुछ नहीं।
- यह कि घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा आधार वर्ष के दौरान 46356 एमटी थी जो बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 63916 एमटी हो गई। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की निर्यात बाजार की मात्रा में भी जांच की अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। इसलिए कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- मालसूची के वास्तविक स्तर का खुलासा न करना संदेहास्पद है। आवेदन के बिक्री आंकड़े यह संकेत देते हैं कि यह जांच की अवधि के क्षति अवधि के दौरान अपने उत्पादन का लगभग 100 प्रतिशत की बिक्री करने में सफल रहा है। इसलिए बढ़ती माल सूची का दावा बढ़ते बिक्री आंकड़ों से मेल नहीं खाता है।
- यह कि याचिकाकर्ता की उत्पादन लागत जांच की अवधि के दौरान उच्च वेतन लागत, ब्याज लागत, उच्च क्षमता और निवेश, न्यून उपयोगिता के परिणामस्वरूप उच्चतर लागत और वित्तीय घाटे कारण बहुत अधिक है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा हायर की गई क्षतिसूचना से स्पष्ट है।
- यह कि याचिकाकर्ता की लागत निर्यातक की लागत की तुलना में अधिक है और अकुशलता के कारण उत्पादन लागत में हुई वृद्धि का आयातकों पर पाटनरोधी शुल्क के रास्ते भारी बोझ पड़ेगा जिससे उपभोक्ता उद्योग, जो पहले से ही श्रम गहन है, के हितों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अतः पाटन रोधी शुल्क का उद्ग्रहण करने से कई उपभोक्ता उद्योगों के

लिए कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप अंतिम उत्पाद की लागत अधिक हो जाएगी और इससे उपभोक्ताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

- यह कि पाटनरोधी नियमावली में डीजीएडी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह गैर क्षतिकारी कीमत पर पहुंचने के लिए जांच की अवधि और विगत तीन वर्षों के दौरान सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करेंगे। अतः डीजीएडी को गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ क्षति अवधि के दौरान सर्वोत्तम क्षमता उपयोग को अर्थात् 92 प्रतिशत को लेना चाहिए और न कि जांच की अवधि के दौरान के 59 प्रतिशत क्षमता उपयोग को।
- आवेदक को वास्तव में इसके कम कीमत वाले निर्यातों से क्षति हो रही है न कि सम्बद्ध देशों से आयातों के कारण।

ज. 2 घरेलू उद्योग के विचार

88. घरेलू उद्योग ने अपने प्रस्तुतिकरणों में निम्नलिखित तर्क दिए हैं।

- यह कि हितबद्ध पक्षकारों का यह आरोप निराधार है कि याचिकाकर्ता आदतन संरक्षण ग्राही है और इससे यह सुझाव मिलता है कि अब तक अधिरोपित किया गया शुल्क केवल याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पत्र के आधार पर ही अधिरोपित किया गया है। यह बात तथ्यों की जांच किए बिना और यह सिद्ध किए बिना कही गई है कि विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण क्षति हुई है। पाटन, क्षति और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों का विस्तृत विश्लेषण करने के पश्चात ही प्राधिकारी द्वारा शुल्क की सिफारिश की जाती है।
- यह कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारी वृद्धि हुई है और वे घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोदहन एवं निग्रहण कर रहे हैं। जिसके कारण उसे भारी घाटा हुआ है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, नकदी प्रवाह के रूप में प्रपाती गिरावट आई है और वह ऋणात्मक स्तर तक पहुंच गई है। घरेलू उद्योग को भारीवित्तीय घाटा, नकद घाटा हुआ है और उसे निवेश पर ऋणात्मक प्रतिलाभ हुआ है। अतः याचिकाकर्ता को वास्तव में क्षति हो रही है।
- यह कि पास्को ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है और कंपनी के सत्यापित आंकड़ों के बिना पाटन न होने के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए यह तर्क नामंजूर किया जाता है।
- यह कि रक्षोपाय जांच की शुरुआत तथा अंतरिम शुल्क की सिफारिश के कारण आयातों में कुछ आंशिक सुधार हुआ और उसके कारण क्षमताओं में वृद्धि की गई जिससे आयातों में कुछ कमी हुई। तथापि, जैसे ही रक्षोपाय शुल्क समाप्त हुआ वैसे ही आयातों में फिर वृद्धि होने लगी। इसके अतिरिक्त, यदि विचाराधीन उत्पाद के सम्पूर्ण क्षति अवधि के दौरान हुए आयातों पर विचार किया जाता है तो यह देखा जा सकता है कि आयातों में निरूपाधिरूप से वृद्धि हुई है।
- यह कि आयातों का न्यूनतम नियम कुल आयातों की तुलना में अलग-अलग देशों के संबंध में आयातों के प्रतिशत से संबंधित है। विधि में भी यह मान्यता है कि यदि किसी देश से आयात कुल आयातों के 3 प्रतिशत से अधिक है तो उससे घरेलू उद्योग को क्षतिकारित करने की संभावना बन सकती है। मांग के संबंध में आयातों का किसी देश को जांच के दायरे से हटा देने का कोई लेना देना नहीं है। याचिका में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कोरिया से संबद्धवस्तु के आयातों का भारी क्षति एवं पाटन मार्जिन मौजूद है। अतः, कोरिया से हुए आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की लागत के स्तर से बहुत कम है।
- यह कि याचिकाकर्ता की वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट में यह स्पष्टतः उल्लेख है कि ओडिशा संयंत्र की फिनिशिंग सुविधा का रैम्प-अप कार्य प्रगति पर है। स्टेनलेस स्टील उद्योग में सामान्यतः यह माना जाता है कि फिनिशिंग एक प्रक्रिया है जिसे पश्चात कोल्ड रोलिंग की जाती है और इसका हाट रोलिंग और एनीलिंग एवं पकिलिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है;
- यह कि याचिकाकर्ता ने अपनी क्षमता में विस्तार मांग में वृद्धि होने की प्रत्याशा में और अन्य देशों से होने वाले आयातों पर पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण करने के कारण माल के उत्पादन तथा उसकी घरेलू बाजार में बिक्री करने के पर्याप्त उचित अवसर प्रदान होंगे। याचिका के पास पर्याप्त क्षमता है और इसलिए भारतीय बाजार में वस्तुतः आयातों के कारण अपनी क्षमता का सम्पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं हुआ।
- यह कि विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बिक्री कीमत में गिरावट घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में आई गिरावट की तुलना में बहुत अधिक है।

- यह कि चीन इससे पूर्व स्टेनलेस स्टील के उत्पादों का निवल आयातक था और अब वह निवल निर्यातक बन गया है। चीन कभी कोरिया के निर्यातकों के लिए क बड़ी बाजार था। तथापि, अब चीन स्टेनलेस स्टील के सबसे बड़े निर्यातक में परिवर्तित हो गया है और इसलिए कोरिया की बाजार समाप्त हो गई है। तदनुसार, कोरिया के ये निर्यात अब भारत तथा अन्यत्र की ओर मुड़ गए हैं। इस तथ्य के साथ ही यह भी सच है कि कोरिया के पास বেশी क्षमता है जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि पाटन के कारण ही क्षति की गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई है;
- यह कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के लिए क्षति का निर्धारण सभी पाटित स्रोतों से संचयी रूप से करना अपेक्षित होता है। अतः निर्यातक द्वारा यथा दावाकृत कीमत अधोरदन, निग्रहण और अवमंदन की व्यक्तिगत जांच अनुपयुक्त है और यह भ्रामक भी हो सकती है।
- यह कि कोरिया के मामले में क्षति मार्जिन भारी सकारात्मक है। अतः किसी भी हाल में, केवल चीन और मलेशिया से होने वाले आयातों पर ही शुल्क का अधिरोपण करना और कोरिया से पाटित व क्षतिकारी आयातों पर शुल्क का अधिरोपण नकरना उपयुक्त नहीं होगा। वास्तव में ऐसी कोई कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबंधित विधिक उपबंधों के विपरीत होगी। कोरिया से हो रहे आयातों की मात्रा नगण्य नहीं है। यह बहुत अधिक तथा विधिक सीमा से परे है।
- यह कि यह तर्क दिया गया है कि पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं होगा, परन्तु किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई मान्य दावा नहीं किया है;
- यह कि कोरिया के निर्यातकों द्वारा दिए गए तर्कों में भारी विपरीतार्थक बातें हैं। एक ओर तो यह तर्क दिया गया है कि कोरिया से होने वाले आयात नगण्य हैं और वहीं दूसरी ओर यह तर्क दिया गया है कि कोरिया से हो रहे आयातों में सीईपीए और अधिमानी सीमा शुल्क के कारण वृद्धि हो रही थी।
- यह कि सीईपीए के अंतर्गत रियायतें प्रदान करना पाटन करने के लिए दिया गया प्रमाण पत्र नहीं कहा जा सकता है। निर्यातक के इस तर्क के विपरीत, अधिमानी सीमाशुल्क के साथ कोई भी निर्यातक अपने उत्पाद की बिक्री सामान्य मूल्य से अधिक की कीमतों पर कर सकता है। निर्यातक को पाटित कीमतों पर निर्यात नहीं करना चाहिए।
- यह कि विनिमय दर में अवमूल्यन होने और उसका घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव के मुद्दे का अच्छी तरह समाधान कर दिया गया है और उसे पूर्णतया असंगत माना गया है। भारतीय रूपए के अवमूल्यन के तथ्य से तो वास्तव में क्षति में कमी होनी चाहिए और उसमें बढोत्तरी तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। यदि यूएस डालर में उछाल आया है तो रूपए की कीमत में वृद्धि हुई होगी और क्षति मार्जिन में गिरावट आनी चाहिए। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति में वृद्धि हुई है।
- यह कि सामग्री लागत पर हो सकता है कि विनिमय दर का प्रभाव पड़े परन्तु उसका उत्पाद की कीमत पर भी समान रूप से प्रभाव पड़ता है। अतः किसी भी हाल में, विनिमय दर का कच्चे माल की कीमत पर या परिष्कृत उत्पाद की कीमत पर को चुनिंदा प्रभाव नहीं पड़ता है।
- यह कि संकीर्णतर कॉइलों की जरूरत को अधिक चौड़े कॉइलों की नाममात्र की लागत पर स्लिटिंग करके आसानी से पूरा किया जा सकता है और याचिकाकर्ता के पास इसकी भारी सुविधा है। याचिकाकर्ता ने संकीर्णतर मोटाई के कॉइल्स की आपूर्ति भी की है। इसके अतिरिक्त, यह एक ज्ञात तथ्य है कि एक बड़ी मिल प्रति यूनिट समय में काफी अधिक आउटपुट दे सकती है और तद्वारा अन्य प्रचालन दक्षमाओं के अतिरिक्त प्रति एमटी न्यूनतर लागत का निर्धारण भी हो सकता है। इसलिए संकीर्ण चौड़ाई के कॉइल का उत्पादन करने की तुलना में अधिक चौड़ी कॉइल का उत्पादन करना अधिक समझदारीपूर्ण कार्य प्रतीत होता है। यह ही वह स्टैण्डर्ड मानक है जिसका सम्पूर्ण विश्व में उत्पादकों द्वारा अनुपालन किया जाता है।
- यह तर्क पूर्णतया निराधार है कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत सम्बद्ध देशों की उत्पादन लागत की तुलना में दस गुना अधिक है।
- यह कि आंकड़ों से यह स्पष्ट होगा कि हिसार संयंत्र में किए गए निवेश पर प्रतिलाभ तर्कसंगत है। जहां तक ओडिशा संयंत्र पर किए गए निवेश पर प्रतिलाभ का संबंध है उस पर पहले तो नवीन प्रचालनां का प्रभाव पड़ा जबकि इसके उत्तरवर्ती रूप पर भारत में पाटन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। अतः यदि अर्जित किए गए निवेश पर प्रतिलाभ पर

प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाता है तो वह घरेलू उद्योग द्वारा वर्ष 2005-06 में किए गए निवेश पर प्राप्त प्रतिलाभ पर विचार कर सकते हैं जो पाटन से पहले देश में हुए उत्पाद पर प्रतिलाभ का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवधि के दौरान जब घरेलू उद्योग पाटन की मार झेल रहा था, तो घरेलू उद्योग द्वारा निवेश पर अर्जित प्रतिलाभ पर विचार करना किसी भी हाल के उपयुक्त नहीं होगा।

- यह कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और उसकी बिक्री में वृद्धि होना क्षमताओं में वृद्धि का परिणाम है। तथापि, नई उत्पादन सुविधा पर उत्पादन प्रारम्भ होने के बावजूद और विगत में पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता अपनी बिक्री में उतनी अधिक वृद्धि करने में अक्षम रहा जितनी वृद्धि की पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के पश्चात उसे उम्मीद थी।
- यह कि ओडिशा की आदर्शात्मक लागत यह दर्शाती है कि हिसार संयंत्र के निष्पादन में स्टैण्ड अलोन आधार पर गिरावट आई है। इससे यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में दावाकृत गिरावट ओडिशा संयंत्र के उत्पादन का वाणिज्यीकरण करने के कारण नहीं आई है।
- यह कि क्षमता में विस्तार के कारण उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने अपनी बिक्री में वृद्धि कीमत की लागत पर की। इससे उसकी बिक्री में वृद्धि हुई। अन्य स्रोतों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने से याचिकाकर्ता को वह बाजार प्राप्त करने की उम्मीद जगी जिस पर पहले अन्य देशों का कब्जा था। तथापि, पाटित स्रोतों के एक सेट द्वारा खाली की गई बाजार पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के साथ ही पाटित स्रोतों के अन्य स्रोत द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया। यह पाटल के एक स्रोत का दूसरे स्रोत को अंतरित होने का उदाहरण है और इसके कारण घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हुई।
- यह कि मजदूरी में वृद्धि को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। क्षमता में विस्तार करने से मजदूरी में वृद्धि हुई। यह देखा जा सकता है कि मजदूरी में यह वृद्धि लाभ में आई गिरावट की तुलना में बहुत कम है।
- यह कि निम्नलिखित से कारणात्मक संबंध स्पष्ट होता है:
 - i. घरेलू उद्योग तथा विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई कीमत में भारी अंतर है। अतः लागत बढ़ने पर कीमत में वृद्धि न कर पाने की घरेलू उद्योग अक्षमता के परिणामस्वरूप देश में इस उत्पाद का पाटन हुआ।
 - ii. यहां तक कि जब घरेलू उद्योग उप- इष्टतम कीमतों की पेशकश कर रहा था और अपनी कीमतों में कमी कर रहा था, तब भी इसकी बिक्री के मौके समाप्त हो रहे थे। अतः घरेलू उद्योग की मौजूदा बिक्री मात्रा सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों का स्पष्ट परिणाम है।
 - iii. कीमत अधारदन के कारण उप- इष्टतम कीमतें हुई। इसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में घरेलू उद्योग के लाभ में ऋणात्मक स्तर तक गिरावट आ गई।
 - iv. लाभ में कमी होने का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि लगाई गई पूंजी पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह में गिरावट आई। अतः लाभ लगाई गई पूंजी पर प्रतिलाभ और नगदी प्रवाह में गिरावट होना पाटित आयातों का प्रत्यक्ष प्रभाव है।
 - v. कीमत अधोरदन से घरेलू उद्योग के लाभ निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह के संबंध में गिरावट आई।
- यह कि घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति को विनिर्माण उपरिशीर्षों जैसे मूल्यहास और परिशोधन व्यय तथा विद्युत एवं ईंधन पर होने वाले व्यय पर उपरोपित नहीं किया जा सकता है। यह दोनों संयंत्रों की पृथक जांच करके स्पष्टतः सिद्ध किया जा सता है। हिसार संयंत्र का निष्पादन स्पष्टतः यह सिद्ध करता है कि निष्पादन में यह गिरावट पाटन के कारण आई है न कि नए संयंत्र के उत्पादन का वाणिज्यीकरण करने के कारण विनिर्माण उपरिशीर्षों पर हुए अधिक व्यय के कारण हुई है।

ज. 3 इन मुद्दों की प्राधिकारी द्वारा जांच

89. प्राधिकारी क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों तथा उनके उठाए गए मुद्दों को तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए प्रति तर्कों को नोट करते हैं। यद्यपि

विभिन्न क्षति एवं कारणात्मक संबंधों जैसे पैरामीटरों की जांच इस अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराग्राफों में निम्नवत की गई है और उनमें उठाए गए कुछ सामान्य मुद्दों का निम्नवत् समाधान कर दिया गया है:

90. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे का संबंध है कि याचिकाकर्ता का व्यवहार संरक्षण प्राप्तकर्ता का है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब तक विभिन्न देशों के निर्यातकों द्वारा विभिन्न समयावसरो पर अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं की मौजूदगी रहेगी और घरेलू उद्योग को इन पाटित आयातों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता रहेगा तब तक घरेलू उद्योग को डब्ल्यूटीओ करार तथा घरेलू विधि के ढांचे के अंतर्गत उपचारी उपायों की मांग करने का अधिकार है। यह उपचारी उपाय संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न सूचनाओं की विस्तृत एवं उद्देश्यपरक मूल्यांकन के पश्चात प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान मामले में भी प्राधिकारी ने विभिन्न दावों तथा प्रतिदावों की नियमावली के ढांचे के अंतर्गत उद्देश्यपरक जांच की है। इसलिए इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिया गया तर्क प्रतिपादनीय नहीं है।

91. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि कतिपय देशों से आयात की मात्रा इतनी कम है कि संबंधित घरेलू उद्योग पर उसका कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ सकता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी संबद्ध देशों से आयात की मात्रा नियमावली और करारों में निर्धारित न्यूनतम मात्रा से अधिक है और ऐसे प्रत्येक देश से पाटन मार्जिन भी बहुत अधिक है। इसलिए आयातित उत्पादों तथा समान घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति के आलोक में आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन करना उपयुक्त होगा। तदनुसार, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का आकलन संचयी रूप से किया गया है और इसलिए इस संबंध में कोरिया के निर्यातकों द्वारा दिया गया तर्क स्वीकार्य नहीं है।

92. जहां तक क्षमता संवर्धन और क्षमता उपयोग नए संयंत्र का स्थिरीकरण और लागत तथा कीमत पर उसके प्रभाव और अन्य पैरामीटरों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन का संबंध है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन मुद्दों का निराकरण संगत शीर्षकों के अंतर्गत जहां तक उन्हें संगत पाया गया और पर्याप्त साक्ष्य द्वारा समर्थित पाया गया वहां तक उनका निराकरण कर दिया गया है।

ज. 4. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों की जांच

93. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; और (ख) इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की उद्देश्यपरक जांच करने का प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में भारत में उत्पादन या खपत के समग्र रूप में या संगत रूप में भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है या क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों को भारी मात्रा में निग्रह करना है अथवा कीमतों वृद्धि होने से रोकना है, जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई है।

क्षति का संचयी आकलन

94. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (iii) में प्रावधान है कि यदि ऐसे अधिक देश से होने वाले आयात पर साथ-साथ ही पाटनरोधी जांच की जाती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी इन आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेंगे, यदि वह यह निर्धारित करते हैं कि:

क) प्रत्येक देश/ भू-भाग से आयातों के संबंध में पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात के तीन प्रतिशत से अधिक है अथवा जहां किसी एक देश का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है और उस समान वस्तु का आयात संचयी रूप से सात प्रतिशत से अधिक है; और

ख) आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति के आलोक में करना उपयुक्त है।

95. वर्तमान मामले में प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन के मार्जिन को निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया है; प्रत्येक संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है; और संबद्ध देश से हो रहे आयात घरेलू उद्योग द्वारा भारतीय बाजार में प्रस्तुत की जा रही समान वस्तु के साथ प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसलिए, प्राधिकारी आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उपयुक्त समझते हैं।

96. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उन सभी संगत आर्थिक कारकों और देशनाकों की जांच की गई जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, इनमें बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों; पाटन की मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी या निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक या संभावित ऋणात्मक प्रभाव पर नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है। घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले ऊपर यथाउल्लिखित सभी आर्थिक पैरामीटरों की जांच निम्नवत् की गई है :

(क) पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव : आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

क) संबद्ध देशों की आयात मात्रा और उनका हिस्सा

97. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में भारत में उत्पादन अथवा खपत के संगत रूप में या समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की संबद्ध देशों से तथा अन्य देशों से आयात की मात्रा की जांच डीजीसीआईएंड एस द्वारा प्रदान कराए गए सौदेवार आयात आंकड़ों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आईबीआईएस आंकड़ों के आधार पर की है। यद्यपि डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान आईबीआईएस आंकड़ों की तुलना में आयात मात्रा में मामूली सी वृद्धि दर्शाई गई है वहीं इसने जांच की अवधि के दौरान अत्यधिक न्यून मात्रा के आयातों को दर्शाया है। इसलिए डीजी सिस्टम्स से प्राप्त आंकड़ों को संपुष्टि के लिए भी मंगाया गया। डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों की तुलना में भारी मात्रा प्रदर्शित की है वहीं यह आईबीआईएस आंकड़ों के निकटस्थ थे। इसलिए, आईबीआईएस आंकड़ों को अधिक संगत होने के कारण क्षति विश्लेषण के लिए अपनाया गया। संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा और क्षति जांच की अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा आईबीआईएस आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित है :

क्र. सं.	विवरण	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
1	आयात मात्रा						
(i)	संबद्ध देश	एमटी	8,490	31,797	38,744	35,985	28,788
	प्रवृत्ति		100	375	456	424	339
क	चीन	एमटी	5,117	26,293	34,905	30,589	24,471
ख	मलेशिया	एमटी	860	1,300	1,345	1,584	1,267
ग	कोरिया आरपी	एमटी	2,512	4,204	2,494	3,813	3,050
(ii)	पाटनरोधी शुल्क आकृष्ट करने वाले अन्य देश	एमटी	22,779	10,012	6,585	6,309	5,047
	प्रवृत्ति		100	44	29	28	22
(iii)	अन्य देश	एमटी	1,065	1,182	2,551	1,832	1,466
	कुल	एमटी	32,334	42,991	47,881	44,126	35,301
	प्रवृत्ति		100	133	148	136	109
2	आयातों का हिस्सा						
(i)	संबद्ध देश	%	26.26	73.96	80.92	81.55	81.55
	प्रवृत्ति		100	282	308	311	311

क	चीन	%	15.83	61.16	72.90	69.32	69.32
ख	मलेशिया	%	2.66	3.02	2.81	3.59	3.59
ग	कोरिया आरपी	%	7.77	9.78	5.21	8.64	8.64
(ii)	पाटनरोधी शुल्क आकृष्ट करने वाले अन्य देश	%	70.45	23.29	13.75	14.30	14.30
	प्रवृत्ति		100	33	20	20	20
(iii)	अन्य देश	%	3.29	2.75	5.33	4.15	4.15
	प्रवृत्ति		100	83	162	126	126
	कुल	%	100	100	100	100	100

98. आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि आधार वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 तक कुल आयातों में लगभग 50 प्रतिशत तक भारी वृद्धि हुई थी। तथापि, इसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात में 350 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई। परंतु कुल आयातों तथा संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान मामूली सी गिरावट आई। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण उस देश से आयातों में भारी वृद्धि होने के कारण दिनांक 04 जनवरी, 2013 को किया गया और इस उत्पाद पर यह शुल्क जांच की अवधि के पर्याप्त हिस्से पर अर्थात् 22 जुलाई, 2013 तक रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस रक्षोपाय शुल्क में जांच की अवधि के दौरान हो रही आयातों की वृद्धि को कम किया जिसके कारण इस अवधि के दौरान आयातों में गिरावट आई।

99. विगत वर्ष और जांच की अवधि के दौरान केवल चीन से होने वाले आयात ही कुल आयातों का लगभग 70 प्रतिशत थे। जांच की अवधि के लिए अधोलिखित तिमाही आयात आंकड़े दर्शाते हैं कि यद्यपि जांच की अवधि की पहली दो तिमाहियों के दौरान चीन से भारी मात्रा में आयात हो रहे थे वहीं तीसरी तिमाही के प्रारंभ से ही इन आयातों में कमी होना शुरू हो गई और चीन विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क लगाने पर अंतिम दो तिमाहियों में आयात की मात्रा बहुत कम हो गई।

विवरण	मात्रा एमटी में				
	जांच की अवधि पहली तिमाही	जांच की अवधि दूसरी तिमाही	जांच की अवधि तीसरी तिमाही	जांच की अवधि चौथी तिमाही	जांच की अवधि पांचवीं तिमाही
संबद्ध देश	11,980	10,942	7,829	3,674	1,560
चीन	11,066	9,134	6,936	2,232	1,221

100. चूंकि जांच की अवधि के आयात आंकड़े आंशिक रूप से रक्षोपाय शुल्क द्वारा प्रभावित हैं इसलिए प्राधिकारी ने जुलाई, 2013 के पश्चात जब रक्षोपाय शुल्क समाप्त हो गया तब आयातों की प्रवृत्ति की जांच करने के लिए रक्षोपाय शुल्क के पश्चात के परिदृश्य पर भी नजर डाली है। जांच की अवधि के पश्चात को पांच तिमाहियों के डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों की जांच, रक्षोपाय शुल्क की समाप्ति के पश्चात आयातों की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए की गई। आयातों की प्रवृत्ति निम्नलिखित हैं :

क्र. सं.	विवरण	मापन की इकाई	जांच की अवधि अप्रैल 12 – जून 13	जांच की अवधि वार्षिकीकृत	जांच की अवधि के पश्चात की अवधि जुलाई 13 – सितम्बर 14	जांच की अवधि के पश्चात की अवधि वार्षिकीकृत
1	आयात मात्रा					
(i)	संबद्ध देश	एमटी	35,985	28,788	46,518	37,215
क	चीन	एमटी	30,589	24,471	43,895	35,116
ख	मलेशिया	एमटी	1,584	1,267	1,183	946
ग	कोरिया आरपी	एमटी	3,813	3,050	1,440	1,152
(ii)	अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	एमटी	6,309	5,047	11,400	9,120
(iii)	अन्य देश	एमटी	1,832	1,466	1,920	1,536
	कुल	एमटी	44,126	35,301	59,839	47,871

101. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण समाप्त कर दिए जाने के पश्चात आयातों में भारी वृद्धि हुई। संबद्ध देशों से आयातों में वार्षिकीकृत वृद्धि जांच की अवधि के दौरान हुई वृद्धि की तुलना में लगभग 29 आधार बिंदु अधिक है।

ख) उत्पादन और क्षमता उपयोग पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

102. घरेलू उत्पाद की मात्रा तथा घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों पर पाटित आयातों के संभावित एवं वास्तविक प्रभावों की जांच घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों के रूप में की गई।

103. घरेलू उद्योग की संस्थापित मेल्टिंग क्षमता हाट रोलड और कोल्ड रोलड दोनों तरह के उत्पादों के लिए जोड़ा गया और यह 16.00 लाख एमटी बनती है जिसमें हिसार और ओडिशा दोनों संयंत्र शामिल हैं। हाट रोलिंग के उपरांत इस उत्पाद का एक भाग ग्राही रूप से कोल्ड रोलिंग के लिए अंतरित कर दिया जाता है। इसलिए, याचिकाकर्ता की समग्र मेल्टिंग क्षमता समर्पित नहीं है और इसलिए यह इस क्षति जांच के लिए संगत नहीं है। तथापि इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच करने के प्रयोजनार्थ इस क्षमता को इस विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रयुक्त हीट्स की संख्या के आधार पर इस विचाराधीन उत्पाद की प्रभाजित मेल्टिंग क्षमता के रूप में व्युत्पन्न की गई है।

104. प्राधिकारी हितवद्ध पक्षकारों के इस तर्क को भी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनी ने ओडिशा इकाई को वर्ष 2011-12 में जोड़ा है और यह जांच की अवधि के दौरान रैम्प-अप प्रक्रिया में था। इसलिए, जांच की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग तथा अन्य पैरामीटर याचिकाकर्ता द्वारा सहन की गई क्षति को पूरी तरह वास्तविक रूप से परावर्तित नहीं करते होंगे। इसे क्षमता और क्षमता उपयोग के जांच के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखते हुए ओडिशा यूनिट के केवल भाग पर विचार किया है जो कंपनी की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार रैम्प-अप प्रचालनों के दौरान उत्पाद के लिए उपलब्ध था। तदनुसार, जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और बिक्री की जांच निम्नवत् की गई है :

विवरण	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की क्षमता (पीयूसी)	एमटी	1,08,869	1,16,654	2,11,359	4,75,014	3,80,011
अनुक्रमित		100	107	194	436	349

घरेलू उद्योग का उत्पादन	एमटी	1,00,265	98,448	1,29,900	3,00,577	2,40,462
अनुक्रमित		100	98	130	300	240
घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग	%	92%	84%	61%	63%	63%
अनुक्रमित		100	92	67	69	69
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	46,356	37,655	43,121	79,895	63,916
अनुक्रमित		100	81	93	172	138
घरेलू उद्योग की ग्राही खपत	एमटी	56,713	53,846	60,555	1,69,362	1,35,489
अनुक्रमित		100	95	107	299	239
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	8,777	5,645	5,450	4,125	3,300
ग्राही को छोड़कर कुल मांग	एमटी	87,467	86,291	96,452	1,28,146	1,02,517
अनुक्रमित		100	99	110	147	117
ग्राही सहित कुल मांग	एमटी	1,44,179	1,40,137	1,57,006	2,97,508	2,38,006
अनुक्रमित		100	97	109	206	165

105. ओडिशा का नया संयंत्र 2011-12 में जोड़ा गया था और इसने लगभग 1 लाख टन क्षमता की संवृद्धि सहित उसी वर्ष उत्पादन शुरू कर दिया था। इसकी क्षमता को आधार वर्ष की तुलना में लगभग 250 प्रतिशत की कुल क्षमता मानकर जांच की अवधि में पुनः रैम्प-अप किया गया। तथापि, उक्त अवधि के दौरान उत्पादन में केवल 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसलिए, क्षमता उपयोग जो आधार वर्ष में, जब केवल हिसार संयंत्र प्रचालन में था, 92 प्रतिशत था घटकर 63 प्रतिशत रह गया। चूंकि क्षति अवधि के दौरान एक बड़ी क्षमता संवृद्धि की गई और यह क्षमता पूर्णतया रैम्प-अप नहीं थी और इस मामले में क्षमता उपयोग भारी क्षति पैरामीटरों से संगत नहीं है।

106. जहां तक मांग का संबंध है, कोल्ड रोलिंग के लिए वाणिज्यिक मांग के साथ-साथ ग्राही मांग में भारी वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान (वार्षिकीकृत आधार पर) घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में आधार वर्ष की तुलना में लगभग 38 प्रतिशत वृद्धि हुई। तथापि, यह वृद्धि जांच की अवधि के अधिकांश भाग के दौरान प्रभावी चीन विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क के अंतर्गत उपलब्ध संरक्षण और ओडिशा की नई इकाई में उत्पादन प्रवर्धन होने के कारण स्पष्ट है। जब इसका विश्लेषण उपलब्ध क्षमता के संदर्भ में और उद्योग की उत्पादन करने तथा आपूर्ति करने की क्षमता के संदर्भ में की गई तो ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू बिक्रियां इसकी संभाव्य क्षमता की तुलना में कम थी।

ग) बाजार हिस्से पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

107. घरेलू बिक्रियों और बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नवत् की गई है :

घरेलू मांग में बाजार हिस्सा (ग्राही खपत के बिना)					
विवरण	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
संबद्ध देश	%	9.71	36.85	40.17	28.08
अनुक्रमित		100.00	379.64	413.85	289.32
वह देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	%	26.04	11.60	6.83	4.92
अनुक्रमित		100.00	44.55	26.22	18.90
अन्य देश	%	1.22	1.37	2.65	1.43

अनुक्रमित		100.00	112.50	217.34	117.45
घरेलू उद्योग	%	53.00	43.64	44.71	62.35
अनुक्रमित		100.00	82.34	84.36	117.64
अन्य भारतीय उत्पादक	%	10.03	6.54	5.65	3.22
अनुक्रमित		100.00	65.20	56.31	32.08
* जांच की अवधि: अप्रैल 12 – जून 13					

108. आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि हालांकि संबद्ध वस्तु की घरेलू बाजार में मांग आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में लगभग 17 प्रतिशत तक बढ़ गई है वहीं घरेलू मांग में संबद्ध देशों से पाटित आयातों का बाजार हिस्सा जो आधार वर्ष में लगभग 10 प्रतिशत था बढ़कर इस तथ्य के बावजूद कि जांच की अवधि के एक भाग के लिए चीन विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क मौजूद था जांच की अवधि में 28 प्रतिशत हो गया। उन देशों का बाजार हिस्सा, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा था, जो आधार वर्ष में 26 प्रतिशत था, घटकर जांच की अवधि में केवल 5 प्रतिशत रह गया। कुल मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा वर्ष 2011-12 तक घटकर 8 प्रतिशत रह गया और तत्पश्चात इसमें सुधार हुआ तथा यह आधार वर्ष में लगभग 9 प्रतिशत हो गया, यह स्पष्टतः कुछ देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव के कारण हुआ था। अन्य भारतीय उत्पादकों को बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान भारी क्षति हुई। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि जिन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगा था उनके द्वारा रिक्त किए गए बाजार हिस्से को संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा किनारे लगा दिया गया और इसने घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में अपनी बिक्री मात्रा उस सीमा तक बढ़ाने से वंचित कर दिया जिस सीमा तक उत्पादन और बिक्री करने की उनकी क्षमता थी।

109. आयातों की प्रवृत्ति की उत्पादन और खपत के संदर्भ में संगत रूप से भी जांच की गई है जैसाकि अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
आयात-संबद्ध देश	एमटी	8,490	31,797	38,744	35,985	28,788
खपत के संबंध में आयात	एमटी	10%	37%	40%	28%	28%
उत्पादन के संबंध में आयात	एमटी	8%	31%	29%	12%	12%

110. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से आयात में खपत और उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आधार वर्ष से जांच की अवधि तक क्रमशः 10 प्रतिशत से 28 प्रतिशत और 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जिससे यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में भारी वृद्धि प्रदर्शित की है।

ख) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

111. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का भारी मात्रा में अवमंदन करने का हुआ है या इसने कीमतों को बढ़ने से वंचित किया है जो अन्य भारी मात्रा में हुई होती।

i) आयातों की प्रवृत्ति

112. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की भारित औसत सीआईएफ आयात कीमत का विश्लेषण आईबीआईएस आंकड़ों के आधार पर निम्नवत् किया गया है :

	सीआईएफ आयात कीमतें	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
(i)	संबद्ध देश	रुपए/ एमटी	1,08,002	1,40,100	1,46,866	1,38,946
	प्रवृत्ति		100	130	136	129
क	चीन	रुपए/ एमटी	1,11,881	1,40,190	1,45,905	1,38,236
	प्रवृत्ति		100	125	130	124
ख	मलेशिया	रुपए/ एमटी	1,03,709	1,39,247	1,55,128	1,37,384
	प्रवृत्ति		100	134	150	132
ग	कोरिया आरपी	रुपए/ एमटी	1,01,568	1,39,798	1,55,870	1,45,297
	प्रवृत्ति		100	138	153	143
(ii)	वे देश जिन पर पाटन रोधी शुल्क लगा है	रुपए/ एमटी	98,425	1,35,673	1,48,418	1,66,418
	प्रवृत्ति		100	138	151	169
(iii)	अन्य देश	रुपए/ एमटी	97,055	1,15,718	1,43,539	1,27,042
	प्रवृत्ति		100	119	148	131
	कुल	रुपए/ एमटी	1,00,895	1,38,399	1,46,902	1,42,380
	प्रवृत्ति		100	137	146	141

113. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की सीआईएफ आयात कीमत तथा जिन देशों पर आयात शुल्क लगा है उनकी सीआईएफ आयात कीमत में वर्ष 2011-12 तक लगभग 30 प्रतिशत से 53 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और उसके पश्चात जांच की अवधि में संबद्ध देशों से कीमतों में भारी गिरावट आई है जबकि जिन देशों पर शुल्क लगा है उनकी कीमतों में विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान लगभग 18 बिंदुओं तक की वृद्धि हुई। जांच की अवधि के दौरान भारत औसत सीआईएफ कीमत में यह गिरावट चीन विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क प्रभावी होने के कारण आई।

ii) कीमत अधोरदन प्रभाव

114. घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे रिबेटों, डिस्काउंट और कमीशन तथा संदत्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क रिबेट दी गई है। चूंकि संबद्ध देशों से पाटित आयात घरेलू उद्योग को एक साथ क्षति पहुंचा रहे हैं इसलिए सभी स्रोतों से पाटित आयातों के संचयी कीमत अधोरदन प्रभाव की जांच निम्नवत् की गई है :

कुल संबद्ध देश	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
आयातों की भारत औसत उतराई कीमत	रुपए/एमटी	1,14,699	1,48,788	1,55,974	1,47,517
अनुक्रमित		100	130	136	129
निवल बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	****	****	****	****
अनुक्रमित		100	127	130	122
कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	****	****	****	****

अनुक्रमित		100	83	15	9
कीमत अधोरदन (%)	%	****	****	****	****
रेंज		5-10	0-5	0-5	0-5

115. उपर्युक्त आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि पाटित आयातों की उतराई कीमत में संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान वर्ष 2011-12 तक वृद्धि हुई है और फिर इसमें कमी आई है। तथापि, यह उतराई कीमत संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है। भारत औसत कीमत अधोरदन समग्र और प्रतिशत दोनों रूपों में बहुत अधिक रहा है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्ष 2011-12 और जांच की अवधि के दौरान कीमत अधोरदन में आधार वर्ष की तुलना में भारी गिरावट आई है जो स्पष्टतः इस कारण से आई है कि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपनी अवस्थिति बनाए रखने के लिए पाटित कीमतों का प्रत्युत्तर न्यूनतर बिक्री कीमतों से दे रहा था। इसलिए, कीमत अधोरदन को पाटित आयातों के कीमत निग्रहण प्रभाव के साथ देखने की जरूरत है।

116. हितवद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि कतिपय देशों का कीमत अधोरदन ऋणात्मक रहा है और इसलिए उससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं हुई है। अतः, प्राधिकारी ने प्रत्येक संबद्ध देश से पाटित आयातों के कीमत अधोरदन की अलग-अलग जांच निम्नवत् की है :

चीन					
विवरण	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	1,18,820	1,48,884	1,54,953	1,46,808
अनुक्रमित		100	125	130	124
निवल बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	****	****	****	****
अनुक्रमित		100	127	130	122
कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	****	****	****	****
अनुक्रमित		100	241	94	60
कीमत अधोरदन (%)	%	****	****	****	****
रेंज		0-5	0-5	0-5	0-5
मलेशिया					
विवरण	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	1,10,141	1,47,882	1,64,748	1,45,904
अनुक्रमित		100	134	150	132
निवल बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	****	****	****	****

अनुक्रमित		100	127	130	122
कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	****	****	(****)	****
अनुक्रमित		100	57	-72	20
कीमत अधोरदन (%)	%	****	****	(****)	****
रेंज		5-10	0-5	0-(-5)	0-5

कोरिया					जांच की अवधि	
विवरण	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	कुल आयात	रियायती शुल्क सहित आयात
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	1,07,867	1,48,467	1,65,537	1,53,874	1,47,962
अनुक्रमित		100	138	153	143	137
निवल बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	****	****	****	****	****
अनुक्रमित		100	127	130	122	122
कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	****	****	(****)	(****)	****
अनुक्रमित		100	42	(66)	(44)	1
कीमत अधोरदन (%)	%	****	****	(****)	(****)	****
रेंज		10-15	0-5	0-(-5)	0-(-5)	0-5

117. उपर्युक्त विपृथक्कीकृत आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि कोरिया से आयातों से कीमत अधोरदन जांच की अवधि तथा विगत वर्ष के दौरान मामूली तौर पर ऋणात्मक रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि सीईपीए के अंतर्गत रियायती शुल्क सहित पाठित आयात जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों का मामूली तौर पर अधोरदन कर रहे थे। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह हो सकता है कि कीमत अधोरदन विश्लेषण घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव की स्पष्ट समझ तब तक प्रदान न करें जब तक कीमत निग्रहण/अवमंदन प्रभाव की जांच भी ऐसी स्थिति में न की जाए जहां घरेलू उद्योग को नव सृजित क्षमता के कारण अपनी बिक्री और बाजार हिस्से को बढ़ाने के लिए अपनी कीमतों का निग्रहण करने के लिए मजबूर हों।

iii) कीमत अधोविक्रयण प्रभाव

118. कीमत अधोविक्रयण निर्धारण के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से आयातों की भारित औसत उतराई कीमत की तुलना जांच की अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी बिक्री कीमत से की गई है।

विवरण	मापन की इकाई	चीन	मलेशिया	कोरिया आरपी	
				कुल आयात	रियायती शुल्क पर आयात
गैर क्षतिकारी कीमत	रुपए/एमटी	****	****	****	****
उतराई कीमत	रुपए/एमटी	1,46,808	1,45,904	1,53,874	1,47,962
कीमत अधोविक्रयण	रुपए/एमटी	****	****	****	****
कीमत अधोविक्रयण	%	****	****	****	****
कीमत अधोविक्रयण (रेंज)		10-20	10-20	5-15	5-15

119. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से आयात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत से बहुत कम कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं जिससे घरेलू कीमतों पर भारी कीमत अधोविक्रयण प्रभाव का संकेत मिलता है।

(iv) पाटित आयातों का कीमत निग्रहण एवं अवमंदन प्रभाव

120. घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत निग्रहण प्रभाव की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्रापण की प्रवृत्ति की तुलना घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और पाटित आयातों की उतराई कीमत से निम्नवत की गई है :

विवरण	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
उत्पादन लागत	रुपए/एमटी	****	****	****	****
अनुक्रमित		100	137	142	143
बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	****	****	****	****
अनुक्रमित		100	127	130	122
संबद्ध देशों के आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	1,14,699	1,48,788	1,55,974	1,47,517
प्रवृत्ति		100	130	136	129

121. आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में कतिपय फैक्टर लागत में वृद्धि होने के कारण जैसे प्रमुख कच्चे माल अर्थात् स्टेनलेस स्टील और निकिल की कीमत में वृद्धि जिसका संबंध उस वर्ष के दौरान आयात कीमतों में भारी वृद्धि से भी है, वर्ष 2010-11 में भारी वृद्धि हुई थी। तत्पश्चात लागत में यह वृद्धि सामान्य ही बनी रही। तथापि, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई जिस अनुपात में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई थी। वास्तव में तो विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बिक्री कीमत में भारी गिरावट आई है जबकि उसी अवधि के दौरान इसकी लागत में मामूली सी वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में यह गिरावट संबद्ध देशों से पाटित आयातों की उतराई कीमत में गिरावट की संपुष्टि करता है। इससे यह संकेत मिलता है कि पाटित आयात घरेलू उद्योग को लाभकर कीमतें वसूल करने से वंचित कर रहे हैं और तद्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों का निग्रहण कर रहे हैं।

ज.5 अन्य क्षति कारकों की जांच

122. पिछले खंड में कुछ क्षति कारकों जैसे बिक्री और बाजार हिस्से में वास्तविक एवं प्रसंभावित गिरावट; आयातों की मात्रा में वास्तविक एवं प्रसंभावित वृद्धि की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी ने अन्य अनिवार्य क्षति पैरामीटरों की जांच निम्नवत की है :

क) लाभ/हानि तथा निवेश पर प्रतिलाभ

123. प्राधिकारी द्वारा उत्पादन तथा उससे जुड़ी अन्य लागतों एवं बिक्री कीमत की विस्तृत जांच के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्रियों से अर्जित लाभ का निर्धारण किया गया है :

विवरण	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
उत्पादन लागत	रुपए/एमटी	****	****	****	****	****
अनुक्रमित		100	137	142	143	143
बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	****	****	****	****	****
अनुक्रमित		100	127	130	122	122
लाभ/हानि	रुपए/एमटी	****	(****)	(****)	(****)	(****)
अनुक्रमित		100	-141	-206	-437	-437
नकद लाभ	लाख रुपए	****	(****)	(****)	(****)	(****)
अनुक्रमित		100	-52	-103	-347	-347
पीवीआईटी	लाख रुपए	****	(****)	(****)	(****)	(****)
अनुक्रमित		100	-62	-103	-248	-248
आरओसीई	%	****	(****)	(****)	(****)	(****)
अनुक्रमित		100	-69	-70	-113	-113

124. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि उत्पादन लागत में वर्ष 2010-11 में लगभग 37 प्रतिशत तक भारी वृद्धि हुई और फिर उसके पश्चात शेष क्षति जांच अवधि के दौरान इसमें मामूली सी वृद्धि हुई। बिक्री कीमत में भी वर्ष 2010-11 के दौरान लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी परंतु यह पूर्ण लागत की वसूली करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जिसके कारण घाटा हुआ। ईयू, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका और ताईवान पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने के बाजवूद भी वर्ष 2010-11 में घाटे में बढ़ोतरी हुई क्योंकि संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने भारत में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया था। संबद्ध देशों से आयात कीमतों में गिरावट होने के कारण बिक्री कीमत में भारी कमी किए जाने से इस घाटे में जांच की अवधि के दौरान और अधिक वृद्धि हुई। आधार वर्ष में प्रति यूनिट सकारात्मक लाभ मार्जिन से क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में निरंतर गिरावट आई और इसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि में घरेलू बिक्रियों पर निवल घाटा हुआ। घरेलू उद्योग के घरेलू निवेश पर प्रतिलाभ में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारी गिरावट आई और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को इस संबद्ध वस्तु पर भारी ऋणात्मक प्रतिलाभ हुआ।

125. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि कंपनी को घाटा ओडिशा संयंत्र के रैम्प-अप प्रचालन के कारण हो सकता है, जिसे अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता से अभी भी स्थिर बनाने की आवश्यकता है और इसलिए क्षति की जांच याचिकाकर्ता के हिसार संयंत्र के बारे में की जानी चाहिए जो 90 प्रतिशत क्षमता से प्रचालन कर रहा था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए क्षति का निर्धारण समग्र रूप से किया जाता है। इसलिए, किसी एक इकाई के संबंध में विपृथक्कृत विश्लेषण अपेक्षित नहीं है।

ख) रोजगार एवं वेतन

126. कर्मचारियों की संख्या और उनको किया गया भुगतान यह दर्शाता है कि ओडिशा में नए संयंत्र का प्रचालन होने के कारण उत्पादन और क्षमता दोनों में वृद्धि होने से रोजगार में बढ़ोतरी हुई।

विवरण	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
उत्पादन लागत	रुपए/एमटी	****	****	****	****	****
अनुक्रमित		100	137	142	143	143

बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	****	****	****	****	****
अनुक्रमित		100	127	130	122	122
लाभ/हानि	रुपए/एमटी	****	(****)	(****)	(****)	(****)
अनुक्रमित		100	-141	-206	-437	-437
नकद लाभ	रुपए/एमटी	****	(****)	(****)	(****)	(****)
अनुक्रमित		100	-52	-103	-347	-347
पीवीआईटी	रुपए/एमटी	****	(****)	(****)	(****)	(****)
अनुक्रमित		100	-62	-103	-248	-248
आरओसीई	%	****	(****)	(****)	(****)	(****)
अनुक्रमित		100	-69	-70	-113	-113

127. यद्यपि, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन तथा उसकी बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में क्रमशः 140 प्रतिशत और 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई, तथा रोजगार और वेतन में क्रमशः 50 प्रतिशत और 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसलिए, रोजगार और वेतन में यह वृद्धि उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के अनुरूप नहीं है।

ग) मालसूची

128. औसत भंडार के रूप में घरेलू उद्योग की मालसूची धारिता आधार वर्ष की तुलना में 170 आधार बिंदुओं की वृद्धि और विगत वर्ष की तुलना में 90 आधार बिंदुओं की वृद्धि दर्शाती है बिक्री के प्रतिशत के रूप में मालसूची आधार वर्ष की तुलना में लगभग 96 आधार बिंदु की भारी वृद्धि दर्शाती है और इससे जांच की अवधि में भारी मालसूची का संकेत मिलता है।

विवरण	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
अथ भंडार	एमटी	****	****	****	****	****
इति भंडार	एमटी	****	****	****	****	****
औसत भंडार	एमटी	****	****	****	****	****
अनुक्रमित		100	53	180	270	270
घरेलू बिक्री के प्रतिशत के रूप में औसत भंडार	%	11	7	21	17	21
प्रवृत्ति		100	65	194	157	196

घ) नकद लाभ

129. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का नकद लाभ निम्नवत् रहा है :

विवरण	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
कर पूर्व लाभ	लाख रुपए	****	(****)	(****)	(****)
अनुक्रमित		100	(115)	(191)	(603)
व्याज	लाख रुपए	****	****	****	****
अनुक्रमित		100	24	43	340
मूल्यहास	लाख रुपए	****	****	****	****
अनुक्रमित		100	99	108	265

मूल्यहास, कर और ब्याज से पहले लाभ	लाख रुपए	****	(****)	(****)	(****)
अनुक्रमित		100	(30)	(60)	(141)
मूल्यहास, कर और ब्याज से पहले लाभ	रुपए/एमटी	****	(****)	(****)	(****)
अनुक्रमित		100	(37)	(65)	(103)
नकद लाभ	लाख रुपए	****	(****)	(****)	(****)
अनुक्रमित		100	-52	-103	-347

130. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता के ब्याज और मूल्यहास में जांच की अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई क्योंकि ओडिशा यूनिट का पूंजीकरण मार्च, 2012 में किया गया था। इसलिए, जांच की अवधि के दौरान नकद घाटे में भारी वृद्धि हुई। तथापि, विगत वर्ष के ब्याज, मूल्यहास और नकद लाभ की प्रवृत्ति, जो ओडिशा संयंत्र के पूंजीकरण द्वारा प्रभावित नहीं थी, यह दर्शाती है कि घरेलू प्रचालनों में भारी नकद घाटा घरेलू बाजार में कम कीमतों के कारण हुआ।

ड.) उत्पादकता

131. घरेलू उद्योग की उत्पादकता की जांच प्रतिदिन उत्पादन और प्रति कर्मचारी उत्पादन के रूप में निम्नवत् की गई है :

विवरण	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
उत्पादकता प्रतिदिन	एमटी/दिन	132	108	123	183
प्रवृत्ति		100	81	93	138
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी/सं.	251	249	189	231
प्रवृत्ति		100	99	75	92

132. आंकड़े यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की दैनिक उत्पादकता में सुधार हुआ है। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट आई है, जबकि विगत वर्ष से इसमें सुधार प्रदर्शित हुआ है। यह नोट किया जाता है कि ओडिशा संयंत्र क्षति जांच अवधि के अंतिम दो वर्षों के दौरान प्रचालन में आया और इसलिए प्रति कर्मचारी उत्पादकता उद्योग के निष्पादन को समग्र रूप से परावर्तित नहीं करती है।

च) वृद्धि

133. घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और बिक्री में वर्ष 2011-12 में ओडिशा में नए संयंत्र द्वारा उत्पादन शुरू कर दिए जाने को देखते हुए सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है और घरेलू उद्योग द्वारा वित्तीय लागत के घाटे पर निर्यात बाजारों के साथ-साथ घरेलू बाजार में बिक्री करने के प्रयास किए गए। लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ जैसे पैरामीटर ऋणात्मक वृद्धि दर्शाते हैं।

वृद्धि प्रतिशत में	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
उत्पादन एमटी में		-1.81%	31.95%	85.11%
क्षमता उपयोग विचाराधीन उत्पाद प्रतिशत में		-7.70%	-22.93%	1.82%
घरेलू बिक्री एमटी में		-18.77	14.52	48.23
लाभ रुपए/एमटी में		-241%	-46%	-113%

नकद लाभ लाख रुपए में		-152%	-100%	-236%
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशत में		-17.77%	-0.03%	-4.54%

छ) नवीन निवेश उगाहने की क्षमता

134. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस संबद्ध वस्तु के लिए घरेलू मांग में स्वस्थ वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि करने के लिए नया पूंजी निवेश घरेलू बाजार तथा निर्यात बाजार में इस उत्पादन के लिए मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया है।

ज) पाटन की मात्रा

135. संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटित आयातों का पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक हैं।

झ. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

136. पाटित आयातों की मात्रा और संबद्ध देशों से पाटित आयातों की कीमत तथा घरेलू कीमतों की प्रवृत्ति की जांच से यह संकेत मिलता है कि पाटित आयातों ने मात्रा एवं कीमत प्रभाव के जरिए घरेलू उद्योग की कीमतों को घरेलू उद्योग में कीमत निग्रहण एवं कीमत अवमंदन के जरिए प्रभावित करते हैं।

ज.6. समग्र आकलन

137. इन कारकों का उपर्युक्त विश्लेषण यह संकेत करता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में विस्तार किया है और आधार वर्ष तथा विगत वर्ष की तुलना में अपने उत्पादन और बिक्री में वृद्धि की है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में, इस अवधि के दौरान चीन विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित होने के कारण, वृद्धि हुई है। तथापि, कतिपय भौतिक पैरामीटरों जैसे मात्रा और उत्पादन तथा बिक्री, में सुधार के बावजूद घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान निवल बिक्री प्रापण में गिरावट होने के कारण क्षति हुई इसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ में गिरावट आई है।

138. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में क्षति जांच अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई और इसमें चीन विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित होने के कारण जांच की अवधि में काफी कमी आई। तथापि, जांच की अवधि के पश्चात् की अवधि के आयात आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि चीन विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क समाप्त होने के पश्चात् आयातों में पुनः वृद्धि होने लगी। इसलिए, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जांच की अवधि से पहले आयात मात्रा की प्रवृत्ति जारी रहने अथवा उसके और अधिक तीव्र होने की संभावना है।

139. पाटित आयातों की कीमतें, जिनमें वर्ष 2011-12 तक वृद्धि हुई, यह दर्शाती हैं कि जांच की अवधि में उनमें भारी कमी आई जिससे घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का निग्रहण हुआ। क्षति जांच अवधि के दौरान कीमत निग्रहण से घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा हुआ। घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति वास्तविक एवं बहुत अधिक है।

झ. कारणात्मक संबंध तथा अन्य कारक

140. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत प्रभाव तथा वास्तविक क्षति की मौजूदगी की जांच करने के पश्चात् कीमत अधोरदन, कीमत अधोविक्रयण और कीमत निग्रहण प्रभाव तथा पाटन रोधी करार एवं भारतीय नियमावली में उल्लिखित अन्य संकेतात्मक पैरामीटरों की जांच यह देखने के लिए की गई कि क्या पाटित आयातों के अलावा कोई अन्य कारक भी घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति में अपना योगदान कर रहा है। तदनुसार निम्नलिखित प्राचलों की जांच की गई है :

i) अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा एवं कीमतें

141. जांच किए गए आयात आंकड़े यह दर्शाते हैं कि इस संबद्ध वस्तु का कुछ ऐसे अन्य देशों से भी आयात किया जा रहा है जो इस जांच के अधीन नहीं हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं जो इस जांच के अधीन नहीं हैं कि इस समय पाटनरोधी शुल्क यूरोपियन यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान और यूएसए से संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रभावी है। इन देशों से आयात की मात्रा तथा आयात में उनके हिस्से में पाटनरोधी शुल्क की अधिरोपण करने के पश्चात् भारी कमी आई है। संबद्ध देशों से आयात की मात्रा जांच की अवधि के दौरान हुए कुल आयातों की 81 प्रतिशत है। अन्य देशों से किया गया आयात का अलग-अलग कोई

महत्व नहीं है और कुल मिलाकर उनका आयात केवल 4 प्रतिशत है। इसलिए अन्य देशों से होने वाले आयात का घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

ii) मांग में संकुचन और/या खपत के मापदंड में परिवर्तन

142. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने मांग में संकुचन या खपत के मापदंड में हुए किसी परिवर्तन के संबंध में, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो, कोई मुद्दा नहीं उठाया है। संबद्ध वस्तु की घरेलू बाजार में खपत के मापदंड और मांग की जांच यह दर्शाती है कि क्षति अवधि के दौरान इसमें 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ग्राही खपत सहित घरेलू मांग लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसलिए, मांग में प्रसम्भाव्य संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

iii) विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं

143. यह वस्तु मुक्त रूप से आयात करने योग्य है और आयात आंकड़े यह दर्शाते हैं कि देश में इस संबद्ध वस्तु का भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है। भारतीय घरेलू बाजार में कोई अन्य बड़ा उत्पादक नहीं है और इसलिए आंतरिक प्रतिस्पर्धा, जिसकी स्वस्थ बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में आवश्यक होती है, के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति कारित नहीं हुई है।

iv) प्रौद्योगिकी में विकास

144. हाट रोल्ल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेटों और स्ट्रिप्स का इलेक्ट्रिकल आर्क फरनेस रूट के जरिए उत्पादन करना स्टेनलेस स्टील के उत्पादन की एक सुस्थापित प्रणाली है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जेएसएल ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए ओडिशा में एक अत्याधुनिक तकनीक वाला नया संयंत्र स्थापित किया है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि उनके द्वारा अपनाई गई कुछ विशिष्ट विनिर्माण प्रक्रिया से उन्हें कुछ लागत लाभ हुआ है। परंतु इन तर्कों/दावों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों में प्रतिभागिताकारी उत्पादकों की उत्पादन प्रक्रिया का निरीक्षण करने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उन्हें इस प्रौद्योगिकी से कोई लाभ हुआ हो या ऐसा कोई नया प्रौद्योगिकीय विकास हुआ हो। इसलिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रौद्योगिकी में विकास से घरेलू उद्योग को कोई क्षति कारित नहीं हुई है।

v) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

145. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता स्वयं इस विचाराधीन उत्पाद का निर्यात भारतीय घरेलू बाजार में प्रभारित की जा रही कीमतों से कम कीमतों पर किया जा रहा है और घरेलू उद्योग को क्षति का यह एक कारण हो सकता है। यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अपने घरेलू तथा निर्यात निष्पादन के संबंध में अलग-अलग सूचना दी है। याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन की जांच निम्नवत् की गई है :

	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
निर्यात बिक्री	एमटी	2,709	5,476	9,806	51,075	40,860
प्रवृत्ति		100	202	362	1,885	1,508
निर्यात कीमत	रुपए/एमटी	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति		100	120	121	113	113

146. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में वृद्धि हुई है, तथापि जांच की अवधि के दौरान कीमत में गिरावट आई है। जैसा कि इस जांच परिणाम में एक जगह अन्यत्र नोट किया गया है, कि घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि वे इस मामले में जांचाधीन देशों सहित कई देशों से वैश्विक पाटन के कारण निर्यात बाजार में लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं हैं। हर हाल में, क्षति विश्लेषण के लिए याचिकाकर्ता की केवल घरेलू बिक्रियों और घरेलू प्रचालनों से संबंधित पैरामीटरों पर ही विचार किया गया है और घरेलू उद्योग को निर्यात निष्पादन के कारण हुई क्षति, यदि कोई, को पाटित आयातों पर उपरोपित नहीं किया गया है।

vi) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

147. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में कुल आउटपुट के रूप में सुधार हुआ है। इसलिए, यह घरेलू उद्योग को क्षति के लिए उपरोपित नहीं की जा सकती है।

ज. अन्य कारक तथा हितबद्ध पक्षकारों के तर्क

148. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति ओडिशा स्थित नए संयंत्र के कारण हुई है जो अभी रैम्प-अप प्रचालन की स्थिति में है और इस क्षति के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इस मुद्दे की विस्तार से जांच की गई है और प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ओडिशा संयंत्र के रैम्प-अप प्रचालन के दौरान न्यूनतर क्षमता उपलब्धता के कारण अतिरिक्त लागत का मानकीकरण करने के पश्चात् यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता को वास्तविक क्षति हो रही है। हिसार स्थित संयंत्र के निष्पादन का स्टैंड अलोन विश्लेषण करने से भी यह संकेत मिलता है कि कीमत निग्रहण के कारण याचिकाकर्ता को भारी वास्तविक क्षति हुई है। इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क सही नहीं पाया गया है कि क्षति केवल ओडिशा संयंत्र के कारण ही हुई है।

149. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क भी दिया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और उसकी बिक्री में भारी वृद्धि हुई है, इसलिए याचिकाकर्ता को कोई क्षति नहीं हुई। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने अपनी क्षमता में भारी वृद्धि उच्चतर मांग होने की प्रत्याशा में की है जिसके कारण उसके उत्पादन और उसकी बिक्री में वृद्धि हुई, तथापि, उद्योग पाटित आयातों के कारण अपनी संपूर्ण लागत भी वसूल करने में सक्षम नहीं है।

150. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति का मुख्य कारण अपनी क्षमता में वृद्धि करने से उत्पादन लागत उपरिशीर्ष में बहुत अधिक वृद्धि होना है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता के दोनों ही संयंत्रों के निष्पादन की जांच की गई स्टैंड अलोन आधार पर की गई है। हिसार संयंत्र, जो 90 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रचालन करता है, को भी घाटा हुआ है। ओडिशा संयंत्र, रैम्प-अप प्रचालनों का प्रशमन करने के लिए, नार्मेशन के पश्चात्, क्षति प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि कीमतों का निग्रहण किया गया है। इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क सही नहीं है।

151. कोरिया के निर्यातकों के इस तर्क के संबंध में कि कोरिया से निर्यात कीमतों का कीमत अधोरदन या निग्रहण/अवमंदन प्रभाव नहीं हुआ है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति सभी पाटित आयातों को ध्यान में रखते हुए संचयी आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। तथापि, स्टैंड अलोन आधार पर भी कोरिया से निर्यातित संबद्ध वस्तु की कीमतें भी घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत तथा गैर-क्षतिकारी कीमतों की तुलना में बहुत कम हैं जिसके कारण भारी कीमत अधोविक्रयण और कीमत निग्रहण हुआ तथा सकारात्मक क्षति मार्जिन हुआ।

152. उपर्युक्त गैर-उपरोपण यह दर्शाता है कि पाटित आयातों के अलावा के अन्य कोई ऐसा ज्ञात कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

अ.1 कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

153. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तव में गिरावट आई है। इसलिए, पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को कारित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध हो जाता है :

- (क) संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में क्षति जांच अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है जबकि जांच की अवधि के दौरान, चीन विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण होने के कारण, इसमें कमी आई। आयातों ने, चीन विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क समाप्त होने के पश्चात्, जांच की अवधि के पश्चात् की अवधि के दौरान पुनः वृद्धि प्रदर्शित की। आयात कीमत लागत स्तर से कम बनी रही और इसके कारण भारी कीमत निग्रहण हुआ। संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि ने उन देशों द्वारा खाली किए गए बाजार हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा था।
- (ख) जांच की अवधि के दौरान उतराई कीमत में भारी गिरावट आई जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में बहुत अधिक कमी आई जिससे उनको भारी घाटा हुआ।
- (ग) आयात मात्रा में वृद्धि होने और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कमी होने से याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रति लाभ पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

154. इसलिए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और यह क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत प्रभाव के कारण हुई है।

ट. क्षति मार्जिन और क्षति का परिमाण

155. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु को आयातन के संबंध में क्षति मार्जिन का निर्धारण भी किया गया है। क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत (एनआईपी) का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा क्षति के दौरान प्राप्त प्रतिलाभ से उच्चतर प्रतिलाभ नहीं दिया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह एक सतत् परम्परा है कि गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करते समय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

156. प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना भारत को संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु का क्षति मार्जिन निर्धारित करने के लिए संबद्ध देशों से निर्यातों के उतराई मूल्य से की गई है। संबद्ध देशों के निर्यातों की भारित औसत उतराई कीमत और उनकी क्षति मार्जिन की गणना निम्नवत् की गई है :

देश	उत्पादक/निर्यात	एनआईपी	उतराई मूल्य	क्षति मार्जिन	आईएम	आईएम रेंज
		रुपए/एमटी	रुपए/एमटी	रुपए/एमटी	%	%
चीन	सभी निर्यातक	****	****	****	****	5-15
मलेशिया	सभी निर्यातक	****	****	****	****	5-15
कोरिया	सभी निर्यातक	****	****	****	****	0-10

ठ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात् किए गए प्रस्तुतिकरण

157. प्राधिकारी ने दिनांक 25 फरवरी, 2015 को एक प्रकटन विवरण प्रस्तुत किया जिसमें इस मामले में अनिवार्य तत्वों का प्रकटन किया गया और सभी हितबद्ध पक्षकारों से इस पर टिप्पणियां मांगी गईं। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच निम्नवत् की गई है :

ठ1. मैसर्स बाहुरू मलेशिया की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण

158. बाहुरू, मलेशिया की ओर से लक्ष्मी कुमारन एवं श्रीधरन ने अपने प्रकटन विवरण पश्चात् किए गए प्रस्तुतिकरण में इस जांच के विभिन्न मुद्दों के संबंध में विगत में किए गए अपने प्रस्तुतिकरणों और अपने आधार को पुनः दोहराया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उन सभी मुद्दों का समाधान इस जांच परिणाम में पहले ही कर दिया गया है और इसलिए संक्षिप्तता की दृष्टि से उन्हें यहां दोहराया नहीं जा रहा है। तथापि, निर्यातक द्वारा उठाए गए कुछ अतिरिक्त मुद्दों का समाधान निम्नवत् किया गया है।

159. अपने प्रस्तुतिकरण में उपर्युक्त निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने इस जांच में इधर-उधर से उठाए आंकड़ों का आश्रय लिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात के लिए सुनिश्चित नहीं है कि मलेशिया के विरुद्ध जांच जारी रखने के लिए आंकड़ों के किस स्रोत पर भरोसा किया जाए क्योंकि उन्होंने प्रकटन विवरण में डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों, आईबीआईएस आंकड़ों और डीजी सिस्टम्स आंकड़ों की जांच की है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया है कि न तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ने और न ही आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान मलेशिया से 1584 एमटी आयात मात्रा पर पहुंचने के लिए आधार का स्पष्टीकरण नहीं किया है। यह भी तर्क दिया गया कि मलेशिया से संबद्ध वस्तु की कुल आयात मात्रा आवेदन में दावाकृत 1584 एमटी की तुलना में केवल 1232.02 एमटी है और आवेदक ने मलेशियाई आयात मात्रा में स्कैप को तथा उन आयातों को शामिल करके आयात मात्रा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है जो पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन है। मलेशिया से आयात की मात्रा बहुत कम है और यह 3 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर से भी कम है। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि इस जांच के लिए आईबीआईएस आंकड़ों का प्रयोग, उनकी डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों की तुलना करने के पश्चात् किया गया है। प्रयोग किए गए आंकड़ों की वैधता के लिए डीजी सिस्टम्स आंकड़ों की भी जांच की गई है। इसलिए, प्रयोग किए गए आंकड़ों के स्रोत के बारे में कोई संभ्रम नहीं है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। जहां तक मलेशिया से आयात मात्रा का संबंध है, प्रकटन विवरण में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख

किया गया था कि बाहरू का प्रश्नावली प्रत्युत्तर स्पष्टतः यह उल्लेख करता है कि बाहरू तथा इसकी संबद्ध कंपनियों ने अकेले ही जांच की अवधि के दौरान 1360 एमटी का निर्यात किया था जो मलेशिया से इस आयात को शामिल करते हुए कुल आयात मात्रा का 3 प्रतिशत से अधिक है, इस तथ्य के बावजूद कि मलेशिया से कुछ अन्य निर्यातक भी हो सकते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि बाहरू और इसकी संबद्ध कंपनियां जांच की अवधि से पहले से ही संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रही थीं और उन्होंने कुछ समय के लिए जांच की अवधि के दौरान निर्यात करना बंद कर दिया था। इसलिए, इन निर्यातकों द्वारा जांच की अवधि के दौरान से पहले भी मलेशिया से निर्यात किया गया होगा जो जांच की अवधि के दौरान भारत में उतरा होगा जिसके कारण जांच की अवधि के दौरान मामूली रूप से उच्चतर आयात मात्रा की सूचना दी गई और यह मलेशिया से निर्यात तथा भारत में आयात के बीच समयान्तराल के कारण हुआ होगा। इसलिए प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि इस जांच परिणाम में जिन आयात आंकड़ों पर भरोसा किया गया और मलेशिया के संबंध में मात्रा निर्धारण किया गया वे सही हैं और मलेशिया से की गई आयात मात्रा न्यूनतम स्तर से अधिक है।

160. निर्यातक ने अपने तर्क में इस बात को पुनः दोहराया है कि प्राधिकारी को इस जांच में भरोसा किए गए सौदावार आयात आंकड़े सभी हितवद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना चाहिए और इसलिए, इस जांच से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का खंडन होता है। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सौदावार आयात आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय से प्राप्त आंकड़े गोपनीय प्रकृति के हैं और वे किसी हितवद्ध पक्षकार द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़े/सूचना नहीं हैं। इसलिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़े प्रदान करने का अनुरोध पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है। ऐसा होते हुए भी, यह नोट किया जा सकता है कि इस प्रकटन विवरण में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि निर्धारणों के लिए आईबीआईएस आंकड़ों का प्रयोग किया गया है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सौदावार आईबीआईएस आंकड़ों को घरेलू उद्योग द्वारा सार्वजनिक फोल्डर में पहले ही रख दिया गया है। इस विधि फर्म ने अपने क्लाइंट की ओर से इस पब्लिक फोल्डर कई बार देखा है और उनकी इस जांच में प्रयोग किए गए आयात आंकड़ों तक पहुंच पहले से ही हैं। इसलिए इस संबंध में निर्यातक द्वारा किया गया तर्क प्रतिपाद्यनीय नहीं है।

161. बाहरू ने संबद्ध वस्तु के उद्गम के देश के संबंध में अपने आधार को पुनः दोहराया है और यह तर्क दिया है कि उसने भारत में किसी भी आयातक को संबद्ध वस्तु के उद्गम के रूप में मलेशिया को दर्शाते हुए कोई उद्गम प्रमाणपत्र नहीं दिया है। वास्तव में, उद्गम के प्रमाणपत्र की जरूरत तो तभी पड़ती है जहां मुक्त व्यापार करार जैसे भारत-आशियान एफटीए के अंतर्गत अधिमानी सीमाशुल्क लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। बाहरू ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उसके निर्यात भारत-आशियान एफटीए के अंतर्गत यह लाभ प्राप्त करने के लिए अर्ह नहीं है। इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि भारत में आयातक संबद्ध वस्तु को मलेशिया मूल का दिखाकर, मलेशियाई प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के आधार पर क्लीयरिंग करा रहे हैं सही नहीं है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मुद्दे का हल प्रकटन विवरण में कर दिया गया है। यह भी संकेत दिया गया कि वस्तु को वृष्टिपूर्ण ढंग से मलेशिया मूल का दर्शाकर और उसे भारत-आशियान एफटीए के अंतर्गत अधिमानी शुल्क व्यवस्था के तहत क्लीयर कर लिया जाता है, एक अलग मुद्दा है परंतु इस तथ्य से मना नहीं किया जाता है कि मलेशिया से निर्यातित वस्तु एफटीए के अंतर्गत उद्गम की नियमावली के अनुरूप मलेशिया मूल की नहीं हैं। प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए आरोप के संबंध में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, यह मुद्दा भी किसी जांच प्राधिकारी द्वारा अलग से जांच कराए जाने के योग्य है। इसलिए इस संबंध में निर्यातक के तर्क प्रतिपाद्यनीय नहीं हैं।

162. बाहरू ने पुनः यह तर्क दिया है कि उन्हें असहयोगकर्ता निर्यातक के रूप में गलत ही माना गया है, यद्यपि उन्होंने संपूर्ण प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है। इस संबंध में निर्यातक ने पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 2.5 तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9क(ग) का उल्लेख किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अपने निजी प्रस्तुतिकरण के अनुसार बाहरू इस उत्पाद का विनिर्माता नहीं है और विनिर्माताओं ने कोई प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी की नीति के अनुसार व्यक्तिगत उपचार तब तक प्रदान नहीं कराया जा सकता है जब तक उत्पादक और निर्यातक दोनों प्राधिकारी के समक्ष न हों। इसलिए बाहरू के प्रश्नावली प्रत्युत्तर को स्वीकार नहीं किया गया है।

163. बाहरू ने तर्क दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अभी भी सामान्य मूल्य विनिर्मित करते हैं। इस विनिर्मित सामान्य मूल्य के लिए विचारित पैरामीटरों का प्रकटन किया जाना चाहिए क्योंकि इन पैरामीटरों को गोपनीय रखना निराधार है। इसलिए प्राधिकारी को चाहिए कि प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचारित तर्कसंगत लाभ मार्जिन का खुलासा करें। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्चे माल की लगभग 70 प्रतिशत लागत निकिल और स्टेनलेस स्टील स्क्रेप की होती है। निकिल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को संबद्ध देश की आयात कीमत के रूप में लिया गया है जिनकी सूचना जांच की अवधि के दौरान वर्ल्ड ट्रेड ऐटलस द्वारा दी गई है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ

एसएस स्क्रेप की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें मेटल बुलेटिन से ली गई हैं। विनिर्मित सामान्य मूल्य पर पहुंचने के लिए उत्पादन लागत पर 5 प्रतिशत के लाभ मार्जिन माइनस ब्याज लागत पर विचार किया गया है।

164. बाहरू ने तर्क दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ऐसे उत्पाद प्रकारों को शामिल करके गलती की है जो घरेलू बाजार के लिए वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। केवल यह भी पर्याप्त नहीं है कि आवेदक इन उत्पादों का उत्पादन करता है। मैग्नेट यूजर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [(2003) 157 ईएलटी 150 (ट्रि-डेल)] में माननीय अधिकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाटनरोधी जांच में संबद्ध वस्तु के उन ग्रेडों को शामिल नहीं किया जाएगा जिसका घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता है। इस संबंध में प्रकटन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि घरेलू उद्योग उच्चतर चौड़ाई के कोल्ड रोलड कॉइल्स का उत्पादन एवं उसकी बिक्री करता है जिन्हें फिर हॉट रोलड कॉइल्स के रूप में रोल आउट किया जाता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे एचआर कॉइल्स का उत्पादन करते हैं। इसलिए बाहरू का यह तर्क भी निराधार है।

165. क्षति एवं कारणात्मक संबंध का निर्धारण करने के बारे में निर्यातक ने पहले किए गए तर्कों और मुद्दों को ही दोहराया है और उनका इस अंतिम जांच परिणाम में संगत खंडों में समाधान कर दिया गया है। निर्यातक ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी को क्षति विश्लेषण करते समय पोस्ट पीओआई आंकड़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण में यह उल्लेख है कि पीओआई आयात मात्रा पर जांच की अवधि के दौरान छह माह तक चीन विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव रहा और इसलिए उसके पश्चात की प्रवृत्ति की जांच करना यह देखने के लिए अपेक्षित था कि क्या इस शुल्क की समाप्ति के पश्चात आयातों में भारी वृद्धि हुई है। इसलिए निर्यातक की आपत्तियां प्रतिपाद्यनीय नहीं हैं।

8.2 मैसर्स सेंचुरी स्टील की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण

166. सेंचुरी स्टील सिंगापुर की ओर से लक्ष्मी कुमारन एवं श्रीधरन ने प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण में यह तर्क दिया है कि पूर्ण प्रतिभागिता के बावजूद प्राधिकारी ने त्रुटिपूर्ण ढंग से चैन आफ प्रोड्यूसर (लिस्को) और निर्यातक (सेंचुरी) का क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन अलग-अलग निर्धारित करने से मना कर दिया। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी की संगत परम्परा के अनुसार संबद्ध देश में उत्पादक द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु का सभी निर्यातक निर्यात कर रहे हो, व्यक्तिगत मार्जिन प्रदान करने के लिए प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करना अपेक्षित होता है। चूंकि लिस्को द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु के चार निर्यातकों में से केवल एक प्राधिकारी के समक्ष था और प्रत्युत्तर दाता उत्पादक-निर्यातक संयोजन को व्यक्तिगत मार्जिन प्रदान नहीं किया जा सका।

167. व्यक्तिगत उपचार मुद्दे के अलावा सेंचुरी ने इसके समान मुद्दे भी उठाए हैं जिनका मैसर्स बाहरू मलेशिया की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरण का समाधान कर दिया गया है। इसलिए, उनको यहां दोहराया नहीं जा रहा है।

8.3 आयातकों की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण

168. आयातकों की ओर से किए गए अपने प्रस्तुतिकरण में मैसर्स लक्ष्मी कुमारन एवं श्रीधरन ने बाहरू मलेशिया के प्रस्तुतिकरणों के संबंध में ऐसे तर्क दिए हैं जिनका पहले ही समाधान किया जा चुका है और उन्हें संक्षिप्तता की दृष्टि से दोहराया नहीं जा रहा है।

169. इन मुद्दों के अलावा आयातकों ने यह तर्क दिया है कि प्रकटन विवरण में उपलब्ध कराई गई कीमत अधोरदन तालिका से यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि के दौरान कोरिया आरपी से कोई कीमत अधोरदन नहीं हुआ है। तथापि, केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोरिया को पाटनरोधी शुल्क के दायरे से अपवर्जित नहीं किया गया है, ऐसा लगता है कि प्राधिकारी ने कोरिया के लिए आयातों का उतराई मूल्य सीईपीए में उल्लिखित शर्तों के अनुसार रियायती दर पर विचार करते हुए घटा दिया है। यह तर्क दिया गया है कि शुल्क की रियायती दर भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन करने के लिए केंद्रीय सरकार की नीति का परिणाम है। यदि यह केंद्रीय सरकार की वचनबद्धता नहीं होती तो शुल्क की कोई रियायती दर नहीं होती। अतः, शुल्क की रियायती दर को संबद्ध वस्तु के पाटन का कारण नहीं माना जा सकता है और इसके प्रभाव को कोरिया आरपी से संबद्ध वस्तु के आयातों का उतराई मूल्य निर्धारित करते समय अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त के आलोक में प्राधिकारी को कोरिया आरपी आयात के विरुद्ध जांच समाप्त कर देनी चाहिए। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति एवं कारणात्मक संबंधों का निर्धारण करने के लिए कीमतम अधोरदन ही केवल एकमात्र कारक नहीं है। प्राधिकारी ने पहले ही यह नोट किया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने घरेलू बाजार में कीमत का भारी निग्रहण/अवमंदन किया है और इसलिए क्षति एवं कारणात्मक संबंधों का निर्धारण करने के लिए कीमत अधोरदन उपयुक्त संकेतक नहीं है। हर हाल में क्षति एवं कारणात्मक संबंधों की जांच संबद्ध देशों से भी आयातों के लिए संचयी रूप से की गई है और जहां तक क्षति एवं कारणात्मक संबंधों की मौजूदगी क्षति एवं कारणात्मक संबंध के कारकों का आकलन करने से स्पष्ट होती है एक देश से कीमत अधोरदन में कमी उस देश के विरुद्ध जांच को समाप्त कर देने का एक कारण नहीं हो सकता है। इसलिए इस संबंध में पक्षकार का तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है।

170. उपर्युक्त के अलावा मैसर्स एथीना ला एसोसिएट्स ने उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे आयातकों की ओर से, अपने प्रस्तुतिकरण में उन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष विगत में किए गए अपने प्रस्तुतिकरणों को ही दोहराया है और हितवद्ध पक्षकारों की प्राधिकारी द्वारा सौदावार आयात आंकड़ों तक पहुंच बनाने के मुद्दे को उठाया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किए गए आईबीआईएस आंकड़े स्वयं याचिका में ही हितवद्ध पक्षकारों को पहले ही प्रदान करा दिए गए हैं और इसलिए हितवद्ध पक्षकारों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। प्राधिकारी द्वारा संग्रहित डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों का प्रयोग केवल तुलनात्मक प्रयोजन से ही किया गया है और नियमावली में यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि उन आंकड़ों को अन्य हितवद्ध पक्षकारों के साथ शेयर किया जाए जिन्हें डीजीसीआईएंडएस से गोपनीय रूप से प्राप्त किया गया है।

ठ.4 लिस्को, चीन की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण

171. लिस्को ने, प्रकटन पश्चात किए गए प्रस्तुतिकरण में यह तर्क दिया है कि अधिकांश कच्चे माल की यूनिट कीमत, निकल वियरिंग पिग आयरन को छोड़कर, भारी अंतरों के बिना यूनिट कीमतें प्रतीत होती है। इसलिए प्राधिकारी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि प्रमुख कच्चे माल की कीमत में भारी अंतर तथा और इस मुद्दे के संबंध में अंतिम जांच परिणाम में अपने जांच परिणाम को परिवर्तित कर देना चाहिए। लिस्को ने पुनः तर्क दिया है कि उन्होंने भारत को अपनी संबद्ध वस्तु के कुल निर्यात में से 60.6 प्रतिशत निर्यात सेंचुरी स्टील पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर के माध्यम से किया है और सेंचुरी ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर भी दायर किया है। इसलिए प्राधिकारी को निर्यात कीमत का निर्धारण उपर्युक्त संपूर्ण श्रृंखला से संबंधित आंकड़ों के आधार पर करना चाहिए। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लिस्को द्वारा अपनी प्रश्नावली प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार सहबद्ध तथा असहबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रमुख कच्चे माल की यूनिट कीमत भारी अंतर दर्शाती है। इसलिए प्राधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित है।

172. जहां तक निर्यात कीमत के निर्धारण का संबंध है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार किसी संबद्ध देश में किसी उत्पादक द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु का निर्यात करने वाले सभी निर्यातकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे व्यक्तिगत मार्जिन प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करेंगे। चूंकि लिस्को द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु के चार निर्यातकों में से केवल एक निर्यातक जो व्यक्तिगत मार्जिन के लिए प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए थे को प्रत्युत्तरदाता उत्पादक – निर्यातक संयोजन प्रदान नहीं किया जा सका।

ठ.5 घरेलू उद्योग की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण

173. घरेलू उद्योग ने अपने प्रकटन पश्चात् विवरण प्रस्तुतिकरण में अधिकांश मुद्दों के संबंध में अपने आधार को दोहराया है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अन्य प्रस्तुतिकरणों का निम्नवत समाधान किया गया है।

174. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद पर कॉइल्स या प्लेट्स की लंबाई के रूप में प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए और जहां तक उस उत्पाद की चौड़ाई का संबंध है उसे भी अशर्त नहीं छोड़ना चाहिए। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि वे उन उपभोक्ताओं को जिन्हें 1650 एमएम तक की चौड़ाई के उत्पाद अपेक्षित होते हैं उन्हें 1650 एमएम से अधिक के उत्पाद का आयात करने उसको स्लिट करने 1650 एमएम से कम के उत्पादन को स्थानापन्न करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 1650 से अधिक की चौड़ाई के लिए पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से अविनियमित छूट प्रदान करने से घरेलू उद्योग को सतत क्षति होगी। इसलिए छूट केवल उन उपभोक्ताओं को दी जानी चाहिए जिन्हें वास्तव में अधिक चौड़ी चौड़ाई की सामग्री अपेक्षित होती है और जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के अंतर्गत 1650 से कम की चौड़ाई की किसी सामग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जहां तक उस उत्पाद की लंबाई का संबंध है इस विचाराधीन उत्पाद के प्रारंभिक विवरण में विसंगति पर संगत खंडों में पहले ही चर्चा कर ली गई है और अब इस विसंगति को दूर कर लिया गया है। जहां तक चौड़ाई पर प्रतिबंध को समाप्त करने और छूट के आधार पर अंतिम प्रयोग की अनुमति देने का संबंध है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन तर्कों को जांच के इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें विचाराधीन उत्पाद के दायरे में भारी परिवर्तन अंतर्गस्त है।

175. घरेलू उद्योग ने पुनः यह प्रस्तुत किया है कि चूंकि इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और उसकी बिक्री कई नामों से की जाती है इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया शुल्क तालिका में यह विनिर्दिष्ट करें कि इस विचाराधीन उत्पाद पर आयातकों द्वारा प्रयोग किए गए इसके वैकल्पिक नामों पर ध्यान दिए बिना शुल्क लगेगा। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि चूंकि इस विचाराधीन उत्पाद की कोई समर्पित सीमाशुल्क संहिता नहीं है, इसलिए प्राधिकारी शुल्क तालिका में यह विनिर्दिष्ट करें कि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है। प्राधिकारी ने इस पर विचार किया है और इस मुद्दे का इस जांच परिणाम में समुचित ढंग से निराकरण कर दिया गया है।

176. घरेलू उद्योग ने पुनः यह प्रस्तुत किया है कि गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करना उपयुक्त नहीं है इससे घरेलू उद्योग को अनावश्यक रूप से न्यून संरक्षण प्राप्त होता है। प्रयोग किए गए कच्चे माल को अनिवार्यतः सर्वोत्तम प्राप्त स्तर नहीं मानना चाहिए। वास्तविक कच्चे माल और उपयोगी वस्तुओं की खपत पर विचार किया जाना चाहिए। ओडिशा में किया गया निवेश गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए बेंचमार्क होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए कुछ उत्पादन स्तर को "युक्तियुक्त, उपयुक्त या आवश्यक" माना है, इसलिए भारित औसत गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए कुछ अन्य उत्पादन मात्रा को अपनाने के लिए कोई आधार नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गैर-क्षतिकारी की कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया है और उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

177. घरेलू उद्योग ने इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया है कि क्षति मार्जिन का परिकलन गैर-क्षतिकारी कीमत और किसी विशिष्ट देश से संबंधित आयात आंकड़ों में न्यूनतम सौदा कीमत के बीच अंतर के आधार पर करना चाहिए। प्राधिकारी की यह परम्परा रही है कि वह असहयोगकर्ता निर्यातक के मामले में न्यूनतम आयात कीमत पर विचार करते हैं। अतः, किसी ऐसी स्थिति में जहां सभी निर्यातक असहयोगकर्ता हो अथवा उन्होंने चुनिंदा रूप से केवल उस सीमा तक सहयोग दिया हो कि प्राधिकारी ने व्यक्तिगत पाटन मार्जिन और क्षतिमार्जिन देने को मना कर दिया हो, वहां भी व्यवहार भिन्न नहीं हो सकता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी विशिष्ट देश के सभी निर्यातकों को असहयोगकर्ता के रूप में घोषित किया गया है वहां क्षतिमार्जिन का निर्धारण करने के लिए सभी आयात संव्यवहारों के भारित औसत उतराई मूल्य की तुलना एनआईपी से की गई है और इसलिए क्षति मार्जिन की गणना उपयुक्त रूप से की गई है।

178. घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण यूएस डालर में निश्चित प्रमात्रा में ही किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस उत्पाद की प्रकृति पर विचार करते हुए इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि स्टील उत्पादों से संबंधित पिछले सभी मामलों में पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण निश्चित शुल्क के रूप में किया गया है, इसलिए इस मामले में भी शुल्क के उसी रूप में सिफारिश करना उपयुक्त होगा।

ड. निष्कर्ष

179. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और प्राधिकारी के रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं कि :

- (i) संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से निर्यातकर्ता देशों की घरेलू बाजार में उनके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर प्रवेश हुआ है;
- (ii) संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन पर्याप्त और न्यूनतम से अधिक है;
- (iii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और घरेलू उद्योग को यह क्षति संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन आयातों के मात्रा और कीमत प्रभाव दोनों के कारण हुई है।

ड. भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

180. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क का एचआर फ्लैट उत्पादों का प्रयोग करने वाले अनुप्रवाही उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और यह परिष्कृत उत्पादों की कीमतों को प्रभावित करेगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को कारित क्षति का उपशमन करना होता है जिससे कि भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा की ऐसी स्थिति स्थापित करना है जो देश के सामान्य हित में हो। पाटनरोधी उपाय का अधिरोपण करने से संबद्ध देश से होने वाले आयात पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा और इसलिए इससे अनुप्रवाही उद्योग तथा उपभोक्ताओं को इस संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ण. सिफारिशें

181. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई और निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के सभी पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी प्रदान कराने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटनरोधी नियमावली में दी गई शर्तों के अनुरूप पाटन, क्षति और घरेलू उद्योग की पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों की जांच प्रारंभ करके एवं आयोजित करके और संबद्ध देशों के विरुद्ध सकारात्मक पाटन मार्जिन स्थापित करके तथा यह निष्कर्ष निकाल के कि इन पाटन आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। प्राधिकारी का विचार है कि घरेलू उद्योग को कारित की जा रही क्षति से बचाने के लिए निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना अपेक्षित है।

182. इसलिए प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधोलिखित स्वरूप और ढंग में निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

183. प्राधिकारी द्वारा अपनाये गये न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका के कालम 9 में विनिर्दिष्ट राशि के अनुरूप पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किये जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप-शीर्षक या प्रशुल्क मद	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7219 और 7210	हॉट रोल्ड आस्टीनितिक स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पाद	एएसटीएम ग्रेड 304 (चौड़ाई 1650 एमएम तक और मोटाई 1.2 एमएम से अधिक)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	कोई	कोई	309	एमटी	यूएस डालर
2	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई अन्य देश	कोई	कोई	309	एमटी	यूएस डालर
3	-वही-	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई अन्य देश	चीन	कोई	कोई	309	एमटी	यूएस डालर
4	-वही-	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया	कोई	कोई	316	एमटी	यूएस डालर
5	-वही-	-वही-	-वही-	मलेशिया	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई अन्य देश	कोई	कोई	316	एमटी	यूएस डालर
6	-वही-	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई अन्य देश	मलेशिया	कोई	कोई	316	एमटी	यूएस डालर
7	-वही-	-वही-	-वही-	कोरिया आरपी	कोरिया आरपी	कोई	कोई	180	एमटी	यूएस डालर
8	-वही-	-वही-	-वही-	कोरिया आरपी	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई अन्य देश	कोई	कोई	180	एमटी	यूएस डालर
9	-वही-	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई अन्य देश	कोरिया आरपी	कोई	कोई	180	एमटी	यूएस डालर

184. केन्द्रीय सरकार के इन आदेशों, जो इस सिफारिश से सृजित होंगे, के विरुद्ध, अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क उत्पाद कर तथा सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की जा सकती है।

185. प्राधिकारी, इसके अंतर्गत यथा संस्तुत निर्णायक साधन की निरंतरता बनाए रखने, उसमें संशोधन करने या उसे समाप्त करने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा अधिनियम के संगत उपबंधों और इस संबंध में समय-समय पर जारी सार्वजनिक नोटिसों के अनुसार करेंगे। इस समीक्षा के लिए प्राधिकारी द्वारा किसी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक यह अनुरोध इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप किसी हितवद्ध पक्षकार द्वारा दायर नहीं किया जाता है।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2015

Final Findings

Sub: Anti-Dumping Investigation concerning import of Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel 304 series from the People's Republic of China, the Republic of Korea, and Malaysia.

F. NO. 14/30/2013-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the Rules) thereof:

1. Whereas M/s Jindal Stainless Limited, New Delhi, (herein after referred to as the applicant) had filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as this Authority), in accordance with the Act, and the Rules, alleging dumping of Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel of ASTM Grade 304 with all its variants, as per the detailed description hereunder (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from the People's Republic of China, the Republic of Korea and Malaysia (herein after also referred to as subject countries) and requested for initiation of an investigation for levy of anti dumping duties on the subject goods.

2. And Whereas, the Authority on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicant issued a public notice dated 11th March 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject good, originating in or exported from the subject countries, in accordance with the Rule 6(1) of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

A. Procedure

3. Procedure described below has been followed with regard to this investigation after issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigation by the Authority.

- (i) In terms of sub-Rule 5 of Rule 5, the Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the application from the domestic industry requesting for initiation of antidumping investigation. The Govt. of Korea was also informed through its Embassy in India about the receipt of the application in accordance with the provisions of Article 2.14 of the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between India and the Republic of Korea;
- (ii) The Embassies of the subject countries in New Delhi were also informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2);
- (iii) The Designated Authority sent copies of initiation notifications dated 11th March 2014 to the Embassies of the subject countries in India, known exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, and the domestic industry, as per the information available with it. Parties to this investigation were requested to file questionnaire responses and make their views known in writing within prescribed time limit. Copies of the letter, petition and questionnaire sent to the exporter, were also sent to the Embassies of subject countries along with a list of known exporters/ producers with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaire within the prescribed time;
- (iv) Copy of the non-confidential version of the petition filed by the domestic industry was made available to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra;
- (v) Exporters' Questionnaires were sent to the following known exporters from subject countries in accordance with the Rule 6(4) to elicit relevant information:

1. M/s. Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd., China
 2. M/s. Lianzhong Stainless Steel Corporation, China
 3. M/s. Baosteel Tower, China
 4. M/s. Jiuquan Iron and Steel (Group) Co. Ltd., China
 5. Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd., China
 6. POSCO, Korea
 7. Bahru Stainless, Malaysia
- (vi) The People's Republic of China being a Non Market Economy Country, the Authority informed the known exporters from China PR to furnish necessary information/ evidence, as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 of the Annexure-1 to the Rules to enable the Authority to consider whether market economy treatment should be granted to such cooperating exporters/producers who could demonstrate that they operate under market economy conditions;
- (vii) The following producers/exporters exporting the subject goods originating in or exported from the subject countries have filed questionnaire responses:
- (i) M/s Lianzhong Stainless Steel Corporation, China
 - (ii) M/s Bahru Stainless, Malaysia;
 - (iii) M/s Century Steel Pte. Ltd.; Singapore
- (viii) M/s POSCO, Korea; M/s Hyundai, Korea and M/s Hyou Sung, Korea have filed a combined injury submission opposing the claims of the domestic industry on various grounds;
- (ix) Questionnaires were sent to the following known importers and consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4):
1. Ratnamani Metals and Tubes Ltd., Gandhidham,
 2. Sangeeta Metal (INDIA), Mumbai
 3. Bhandari Foils & Tubes Ltd., Dewas (M.P)
 4. Ramani Steel House, Mumbai
 5. Prakash Steelage Ltd., Navi Mumbai Maharashtra
 6. Nishant Infinn Pvt. Ltd., Mumbai
 7. Rajendra Mechanical Industries Ltd East Mumbai
 8. A.C Steel Sgop, Mumbai
 9. Phoenix Foils Pvt. Ltd, Gujarat
 10. Quality Folis(India) Pvt. Ltd., Haryana
 11. Domet Trading Pvt. Ltd., Maharashtra
 12. Remi Edelstahl Tubulars Ltd., Mumbai
 13. Process Plant and Machinery Association of India, Mumbai
 14. Stainless Steel Exporters Welfare Association, Delhi
 15. All India Stainless Steel Industries Association of India, Mumbai
 16. The Tamil Nadu Stainless Steel Merchants and Manufacturers Association, Chennai.
- (x) Following importers/users of the subject goods have filed their responses:
1. Ratnamani Metals and Tubes Limited
 2. Bhandari Foils and Tubes Limited
 3. Hindustan Inox Limited
 4. JNB Steel Industries Private Limited
 5. Kansara Popatlal Tibhovandas Metals Private Limited
 6. Santosh Steel Industries
 7. Shalco Industries Private Limited
 8. Subhalaxmi Metals and Tubes Pvt. Ltd.
 9. SNB Enterprises Pvt. Ltd.
 10. Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd.
 11. Sunrise Stainless Pvt. Ltd.
 12. Varun Foils Ltd.
 13. Suncity Sheets Pvt. Ltd.
 14. Navgrah Fastners Pvt. Ltd.

- (xi) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigations. The petitioner has also provided the import data from IBIS. Both data sources have been examined and used to the extent they were found appropriate;
- (xii) The Authority made available non-confidential versions of the evidences presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- (xiii) Optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India, based on the information furnished by the petitioner on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), was worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry;
- (xiv) The confidentiality claims of various interested parties in respect of the data submitted by them have been examined. The information, which is by nature confidential or which has been provided on a confidential basis by the interested parties, along with non-confidential summary thereof, has been treated confidential. *** in this finding represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;
- (xv) Investigation was carried out for the period starting from April 2012- June 2013(POI). However, the injury investigation covers the period 2009-10, 2010-11, 2011-12 and POI;
- (xvi) The Authority held a public hearing on 09.12.2014 to hear the interested parties orally, which was attended to by representatives of interested parties. The interested parties were asked to file written submissions and rejoinders. The written submissions and rejoinders received from interested parties to the extent relevant have been considered in the findings;
- (xvii) On the spot verification of the data of the domestic industry as well as of the exporters, to the extent considered necessary, was carried out.
- (xviii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for the findings were disclosed to known interested parties on 25th February 2015 and comments received on the same have been considered in the Final Findings;
- (xix) The Authority has taken weighted average exchange rate for the POI (April 2012- June 2013) as Rs. 54.69/US \$.

B. Product under Consideration and Like Article

4. The product under consideration notified in the initiation notification is “Hot Rolled austenitic stainless steel flat products; whether or not plates, sheets or coils (hot rolled Annealed and pickled or Black) of rectangular shape; of grade either 304 or 304H or 304L or 304N or 304LN or EN 1.4311, EN 1.4301, EN1.4307 or X5CRNI1810 or X04Cr19Ni9, or equivalents thereof in any other standards such as UNS, DIN, JIS, BIS, EN, etc.; whether or not with number one or Black finish; whether or not of quality prime or non prime; whether or not of edge condition with mill edge or trim edge; of thickness in the range of 1.2mm to 10.5mm in Coils and 3mm to 105mm in Plates & Sheets; of all widths up to 1650mm; of all lengths up to 10,000 meters in Coils and 10 Meters in Plates.”

5. The subject goods are used for manufacture of process equipments, re-rolling, reactor vessels, material handling equipments, railways, pipes and tube, automatic components, rolled and formed sections, architecture, building and construction, industrial fabrications and power sector etc.

6. This product is classified under Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975 under Customs sub heading 7219 & 7210 of the first schedule. The classifications indicated herein are indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. The product description shall prevail in all circumstances.

7. The applicant has claimed that there is no significant difference between the products manufactured by them and the subject goods imported from the subject countries, which can have any impact on price, usage, quality etc. The applicant also claims that there is no material difference in the production process between the petitioner and exporters from the subject country. Therefore, the imported product under consideration and the goods manufactured by the domestic industry are like articles” within the meaning of the term as per the Rules.

B.1 Views of the Interested Parties

8. The interested parties, including M/s POSCO, Korea RP; M/s Hyundai Corporation, Korea RP; M/s Hyosung Corporation, Korea RP, M/s Acerinox, Bahru Stainless Malaysia, M/s Century Steel, Singapore, M/s LISCO, China and Importers in India, in their respective submissions regarding the scope of product under consideration and like articles, have *inter alia* argued as follows:

- That in respect of the scope of the product under consideration in this Investigation, the product exported from the Subject Countries and the product manufactured by the domestic industry should be either identical or at least alike in all respects for comparability. In this regard, where there is no identical or alike domestic product, the Investigation should exclude the relevant product line and also narrow down its scope.
- That as per the product dimensions shown in the recent catalogues of the Petitioner they produce 'Hot Rolled Coil and HRAP/Coil with thickness of minimum 2.8mm' at Hissar, and Hot Rolled Coil with thickness of minimum 2mm and HRAP Coil with thickness of minimum 1.4mm at Odisha plant. The Odisha plant is still under ramp up and incapable of production of such less thickness. Therefore, STS HR 304 with thickness of below 2.0mm should not be included within the scope of product under consideration.
- That due to the inability of the domestic producers to manufacture STS HR 304 with thickness of below 2.0mm and qualified for quality standards and specifications required by the Indian customers, it is inevitable for the downstream user industries to import the same.
- That Annealing and Pickling are the process involved in the Cold Rolling process wherein Hot Rolling does not involve Annealing and Pickling process. Hot Rolling and Cold Rolling are two distinct process and inclusion of Annealed and Pickled products into the PUC lead to overlapping of two distinct processes and products at large. Therefore, the Authority should exclude Annealed and Pickled products from the scope of PUC to remove the apparent grave infirmity in the PUC definition.
- That since PUC includes both prime and non prime products appropriate adjustments should be made in their prices for fair comparison for the purpose of dumping and injury margin calculations.
- That the petitioner claims that they have produced and supplied product of width upto 1270 mm from Hisar plant and also has developed facilities upto 1650 mm in Odisha plant, however, produced upto 1625 mm only at its Odisha plant. Thus, the widths should have been kept upto a level produced by the petitioner while defining the product, which is not more than 1625 mm in any case.
- That the petitioner is generally making 1000mm, 1250mm and 1500mm width of Coils in Mill Edge and if any customer wants 400mm, 405mm, 425mm, 485mm, 550mm, 585mm, 600mm, 620mm, 650mm, 720mm, 750mm, 780mm etc. [below 1000mm in general] then the petitioner gives him Slit Edge. Thus, the petitioner is not supplying subject goods of Mill Edge below 1000mm width. As against this, the producers in subject countries are providing all widths like 400mm, 405mm, 425mm, 485mm, 550mm, 585mm, 600mm, 620mm, 650mm, 720mm, 750mm, 780mm in Mill Edge. Thus, the petitioner's process to make that small widths is totally different to Chinese Manufacturers like Huadi, Dingxin, Ruitian, Jisco, Baoshan, Quanxing etc. and the PUC should not be defined in a way to include Mill Edge below 1000mm in the PUC as the same is not produced by the petitioner.
- That the petitioner claimed Coil Length maximum to be at 10,000 meter and included coils of lengths upto 10,000 meters in the PUC. This is illogical. A coil of 1650mm width x 2mm thickness and 10,000 meter should weigh around 262 Tones. However, no company in the world can make coil more than 40 tones. As per market information no material higher than 1000 Meter has ever come to India from any of the subject countries. Thus, inclusion of coils upto 10,000 meter looks dubious and need to be fixed as per the market reality and practices to ensure the realistic aspect of the definition of PUC.

9. Apart from these general arguments regarding the scope of product under consideration and like articles, M/s Posco, Korea, in its submission has further argued:

- That HR Stainless steel Coils and sheets exported from Korea are not like article to the product of the petitioner and therefore, should be excluded from the scope of the investigation. In support of their argument Posco has quoted the Appellate Body's observations in EC-Asbestos on the issue of determination of like articles as follows:
"The report of the Working Party on Border Tax Adjustments outlined an approach for analyzing "likeness" that has been followed and developed since by several panels and the Appellate Body. This approach has, in the main, consisted of employing four general criteria in analyzing "likeness": (i) the properties, nature, and quality of the products; (ii) the end-uses of the products; (iii) consumers' tastes and habits – more comprehensively termed consumers' perceptions and behavior – in respect of the products; and (iv) the tariff classification of the products...."
- That considering the four general criteria set out by the Appellate Body as above, the Authority should investigate the like product in terms of not only tariff classification but, more importantly, also quality, the end-uses, consumers' preferences. It has been argued that there is a great difference between goods produced by domestic industry and goods imported from Korea, in terms of product quality, its end-uses and consumers' preferences of

STS HR 304. Although the product concerned is categorized into the same standards, depending on its quality for end-uses and consumers' tastes, the target market is different. With differentiated customer group and market, POSCO and the Petitioner cannot be said to be in competitive relationship. It is submitted that the non-competitive relationship can also be interpreted as one of non-substitutable nature. Due to lack of competitiveness and substitution, the Authority should exclude the STS HR 304 originated in Korea from the Investigation.

- That contrary to the Petitioner's averments, there is significant difference in production process between the POSCO product and that of the Petitioner. As it is well known in the World Stainless Steel market, POSCO employs 'Strip Casting' method in its production process for some special products with thickness below 2.0mm, named 'Postrip', which process enables POSCO to manufacture different specification and size such as thinner coils and plates. This difference is even more glaring in view of the fact that the Petitioner does not produce STS HR 304 with width below 2.0mm.
- That POSCO's 'Strip Casting' reduces overall production process and skips several conventional processes. While the conventional production method, which the Petitioner has employed, first produces "Slabs" and then proceeds with hot rolling them, the Strip Casting method skips the production of "Slabs" and works all processes simultaneously, from continuous casting to hot rolling.
- That this reduction of the process does not mean a mere change in shortening of the production line. The introduction of the Strip Casting enables POSCO to manufacture 'Postrip', which satisfies its customer's more sophisticated needs and also improves the product quality, which is subsequently regarded as a different product in the World Stainless Steel market.
- That the Investigation should consider that POSCO has a significantly different production process globally known as the 'Strip Casting Method' in Steel industry, which enables it to produce STS HR 304 with more sophisticated customer's needs as well as better quality.

B.2 Views of the domestic industry

10. The domestic industry, in its various submissions, has *inter alia* argued:

- That the Director General (Safeguards) had earlier recommended safeguard duty on imports of this product vide Notification No. G S R D-22011/06/2012, wherein the Director General (Safeguards) had considered the following scope of the product under consideration after elaborate investigations.
"Hot Rolled Flat products of Stainless Steel -304 grade (upto a maximum width of 1625 mm) encompassing all austenitic grades having minimum Nickel (Ni) content of 6%, compulsorily containing chromium with or without the presence of other alloying elements like molybdenum, titanium etc."
- That the Designated Authority had earlier recommended anti dumping duty on imports of this product from European Union, South Africa, Taiwan and USA vide Notification No. 14/12/2010-DGAD, wherein the Designated Authority had considered the following scope of the product under consideration after elaborate investigations.
"Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel of width up to 1250 mm (width tolerance of +20 mm for Mill Edge and +5mm for Trimmed Edge) of ASTM Grade 304 with all its variants including products of equivalent specifications in other standards like UNS, IS, Chinese DIN, JIS, BIS, EN, etc."
- That most of the integrated producers globally produce HR products and CR products produced by rolling the HR products. Globally the producers can produce different types at the same plant/manufacturing facilities and can interchangeably produce different types. Producers first produce 'higher width' coils and then the same can be trimmed/slit (either by them or slitters or re-rollers) to 'small widths' of size required by the 'end consumers'. As opposed to coils, producers produce plates of size required by end consumers.
- That there are 3 categories of customers to whom HR steel producers sell their product:
 - i. End consumers: consumers of HR Plates, HR Coils, CR plates, sheets, strips. These are the eventual consumers of the product under consideration. These end consumers require specific product type for their end applications and generally buy the product in the desired dimensions.
 - ii. Re-rollers and slitters (including service centres): They buy HR Coils from domestic or foreign producers and re-roll under cold conditions into desired coils width (smaller) and thickness. End product is cold rolled coils of narrower width and thinner thickness. There are service centres who are involved in slitting of the HR products. They are capable of slitting both HR and CR coils to desired widths.
 - iii. Traders: These are not the consumers of the product under consideration. They buy the product under consideration and sell the same. Their entire objective is trading and making money.

- That the slitters and re-rollers buy the products of wider widths, slit it and sell in the desired smaller widths to the end consumers or re-rollers.
- That the scope of the product under consideration includes coils, sheets and plates. Sheets/plates and coils are merely two different forms of the product. The only difference between sheets and plates is in thickness. If thickness is below 5 mm, it is normally called sheet. If thickness is higher, it is called plate. Sheets/plates and coils have been imported from subject countries and supplied by the domestic industry.
- That the Designated Authority had earlier conducted investigations relating to this product, wherein both coil and plates/sheets were included within the scope of the product under consideration (the scope of the product under consideration in anti-dumping case was “Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel of width up to 1250 mm (width tolerance of +20 mm for Mill Edge and +5mm for Trimmed Edge) of ASTM Grade 304 with all its variants including products of equivalent specifications in other standards like UNS, IS, Chinese DIN, JIS, BIS, EN, etc.)”. No product is consumed in coil form. Every coil is first cut and then consumed.
- That there is no known difference in product produced by the petitioner and exported from the subject countries. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. Comparison of essential product properties in respect of domestic product and imported product would show that the goods produced by the domestic industry are identical to the imported goods in terms of essential product properties. There are a number of standards – domestic & international and all producers produce goods conforming to these standards. Thus, the consumers find the goods supplied by the domestic industry and foreign producers as identical, if the two conform to same standards.
- That there is no material difference in the production process employed by the foreign producers and that employed by the petitioner. However, every manufacturer fine-tunes its production process as per the necessities and available facilities.
- That the product description is the one that was proposed by the Directorate after filing of initial petition. Nevertheless, while product description may be lengthy or wide, the product scope is not wide and remains the same as was considered by the Designated Authority in the past anti-dumping as well as safeguard investigation;
- That the product produced by the petitioner and respondent are targeted towards the same application/end use and the consumers are using the goods interchangeably, thus rendering the products as like article. While determining the like article, the Authority is required to take into account all the products which fall under the description of the product as long as the same are technically and commercially substitutable. POSCO had raised similar issues in the investigation concerning imports of Cold Rolled Flat Products. The Authority had rejected these arguments;
- That the Designated Authority may consider rephrasing the description of the product under consideration as follows, which does not mean changing the scope of the product under consideration and would merely restrict the description and even would better clarify the same:
“Hot Rolled Flat Product of Stainless Steel of Grade 304 as per ASTM, including all variants and equivalent grades in other standards like EN, DIN, JIS, BIS etc, with widths not exceeding 1650mm, having minimum nickel content of 6%, compulsorily containing chromium, with or without the addition of other elements like titanium, copper etc., with a minimum thickness of 1.2 mm.”
- That the Petitioner has no objection to the description of the product under consideration being modified to as stated above. In any case, the petitioner submits that the scope of the product under consideration in previous case and present case is the same.
- That the new production facility set up in Odisha has developed facilities upto 1650 mm and the petitioner has already supplied material up to 1690 mm width in Cold Rolling. Relevant evidence showing sale of 1690 mm width (CR product) product has been submitted to the Authority.
- That contrary to POSCO’s arguments that the petitioner does not produce goods below 2 mm of thickness which is the product produced and exported by it the Petitioner has produced and supplied product with lower thickness. Relevant Evidence has been submitted to the Authority.
- That prime and non prime are merely two different types of the product under consideration. The anti-dumping investigation and the safeguard investigation conducted on the product under consideration did not distinguish product on the basis of prime and non prime products. The cost of production of prime and non prime goods is not different.

- That annealing and pickling is a process involved in both Hot Rolled and Cold Rolled Flat products. ASTM and EN standard clearly mentions annealed & pickled (de-scaled) Hot Rolled products.
- That suspension of production in Odisha is a temporary shutdown. A plant constructed with investments to the tune of Rs. 10,000 crores would not be allowed by any prudent business to be shut permanently. Hot Rolled products are still being produced from the Odisha plant. Suspension of production is in cold rolled category.

B.3 Examination of the Authority

11. The Authority has carefully examined the arguments of the interested parties and the domestic industry in respect of the scope of the product under consideration and the like article produced by the domestic industry. During the visit to the production facilities of the petitioner the production process and the product itself has been examined to the extent possible.

12. The petitioner is a major producer of Hot Rolled as well as Cold Rolled Stainless Steel producers in India with two plants, one at Hissar and newly set up Odisha Plant with combined installed Capacity of 15.80 lacs tonnes per Annum. Both the plants first produce hot rolled black plates/coils of desired width and thickness which are then annealed and pickled to give the product necessary softness and surface finish. Hot rolled products are sold either as black plates/coil which are further processed i.e., annealed and pickled by the buyer at its own end, or as No. 1 finished i.e. annealed and pickled product. A portion of the hot rolled plates/coils produced in the plants are further cold rolled, annealed and pickled and skin passed and thereafter sold as cold rolled products which have different end uses. Both the plants have their separate lines for hot and cold rolling. Therefore, it is seen that annealing and pickling is an integral part of both Hot Rolled products and Cold Rolled Products. Hence, arguments of some of the interested parties that the petitioner has wrongfully included annealed pickled products, which are part of cold rolling process, within the scope of the PUC, are devoid of any merit.

13. It was found during the verification visit that Odisha plant of JSL, both Hot Rolling and Cold Rolling lines were in operation. On enquiry it was found that the Cold Rolling unit was shut down from 16th November to 20th December 2014 due to certain pollution control issues with the State Govt. As per the CDR report submitted by the company before the relevant Authorities the plant should have completed its ramp up operation with 90% capacity utilization by September 2013. However, it was submitted that this capacity utilization has not been achieved due to lack of orders because of dumping from various countries while the plant is fully ready for full production. In any case, the plant was producing Hot Rolled products, therefore, the arguments of the interested parties that the domestic industry is unable to supply the material due to closure of Odisha plant is not found to be correct.

14. Examination of the production and capacities of the petitioner reveals that as per the technical literature of Odisha plant this plant has the capacities to produce plates and strips up to 1650mm width. As per ISO standards the Mill edge production has a tolerance of +20mm. The plant had sold HR coils upto 1625mm and 1.2 mm thickness during the POI. The same plant has also produced and sold CR coils upto 1690mm during the same period. It has been submitted that HR coil produced in the same plant is transferred captively for further cold rolling into CR coil. Therefore, the petitioner has argued that though they have not sold HR coils of width above 1625mm during the POI the very fact that CR coils of higher width upto 1690mm has been produced and sold by the petitioner indicates that they have produced HR of same width and transferred the same captively for cold rolling. It was clarified by the technical team of the petitioner during the verification that though the plant can produce coils of width upto 1650mm and 1.2mm thickness (+ the tolerance limits), their production schedule and actual production depends on the sizes and thickness demanded by the buyers. Therefore, they can always produce HR coils up to these dimensions if there is an order for the same.

15. As far as the arguments of the interested parties that the petitioner is not supplying subject goods of Mill Edge below 1000mm width it was clarified that the production of wider plates/coils and subsequently slitting them for narrower width as per customer requirement is a more cost effective way of production. In any case the user has to trim the Mill Edge plates/ coils before using the same. Rolling of narrower plates/ coils, in the same line, leads to a lot of wastage of the production facility and energy losses. It was found that the petitioner is supplying Hot Rolled Coils of different widths to the buyers after slitting. Since the Mill Edge plates are ultimately trimmed and slit to required dimensions the arguments of the interested parties that the PUC should not cover Mill Edge products below 1000 mm does not have any merit.

16. The interested parties have argued that non-prime materials should be excluded from the PUC. The Authority notes that in the production process both prime and non prime materials are produced universally and are sold as such. They are used as substitutable products by users in many areas of usage. The cost of production of prime and non prime goods is not different though the non-prime may be sold at a different price. All the previous investigations conducted, including the safeguard investigation, did not distinguish product on the basis of prime and non prime nature of the products. Therefore, the Authority does not find any merit in the arguments of the interested parties in this regard.

17. As far as the length of coils up to 10000 meters is concerned the matter has been examined and the arguments of the interested parties have been found to be logical. Apparently there is a mistake in the description and therefore, the Authority has removed this criterion from the scope of PUC.

18. The Authority notes that POSCO, in its submission, has argued that their production process and the grades of steel produced is different and therefore, not like article to the subject goods manufactured by the petitioner. POSCO has argued that the jurisprudence developed by certain WTO Panels *indicate employing four general criteria in analyzing "likeness": (i) the properties, nature, and quality of the products; (ii) the end-uses of the products; (iii) consumers' tastes and habits – more comprehensively termed consumers' perceptions and behavior – in respect of the products; and (iv) the tariff classification of the products....*" In this connection the Authority notes that Rule 2(d) defines "like article" as an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such an article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation. While determining the likeness of an article the Authority looks into the raw material used, production process, end use, and technical and commercial substitutability etc.

19. The Authority notes that POSCO has not put any evidence on record to prove how their product is different from the product manufactured by the domestic industry except the fact that POSCO uses strip casting method for producing narrower and thinner coils. POSCO claims that this method reduces overall production process skipping several conventional processes and produces better quality product. However, POSCO has not substantiated its claims with any production and cost data and questionnaire response. The Authority also notes that POSCO had made similar arguments for exclusion of its products on the grounds of difference in production process and quality in Anti Dumping investigation concerning import of Cold Rolled Coils and the Authority held *".....the Authority could appreciate that BAF only makes it an efficient process to get the quality end- product rather than a different end product demonstratively in terms of quality and technical terms..... Hence, the Authority treats grades 409 and 409 L produced with BAF process as technically and commercially substitutable with the same produced by domestic industry without using BAF technology."* In the instant case also POSCO has not substantiated its claim that its process results in a product which is not technically and commercially substitutable to the product manufacture by the domestic industry. Therefore, the arguments of POSCO have not been accepted.

20. The above examination of various arguments of the interested parties as well as the domestic industry; and the product and import data submitted by the applicant indicates that there is no difference between Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel 304 series produced by the Domestic Industry and imported from subject countries. In view of the similarity in manufacturing process and technical and commercial substitutability, the Authority holds that the subject good is required to be treated as 'like article' and one product for the purpose of defining the 'product under consideration' in this case.

21. The Authority notes that in a similar finding the Safeguard Authority had restricted the scope of PUC to 1625 mm width on the basis of actual production and supply by the petitioner during their investigation period. The Authority notes that the domestic industry has demonstrated its capability to produce and supply the stainless steel coils beyond 1625 mm and thickness up to 1.2 mm. In fact HR coils of higher width has been produced and captively transferred for production of CR which has been sold during the POI. Therefore, the Authority confirms the width and thickness limits of the product under consideration as indicated in the initiation notification.

22. The Authority further note that in its Final Finding dated 11th October, 2011 for the same product against other countries the Authority allowed width tolerance for trim edge and mill edge materials separately as per ISO standards. Therefore, the Authority considers it appropriate to indicate width tolerance in respect to the subject goods in the present investigation as per the same ISO standard. The width tolerance indicated in ISO standard for Hot Rolled plates/ sheets and strips is + 20mm (for mill edge) and + 5mm (for trim edge).

23. Considering all aspects of the product the Authority proposed confirmation of the description of the product under consideration with incorporation of the tolerance limits as follows:

"Hot Rolled austenitic stainless steel flat products; whether or not plates, sheets or coils (hot rolled Annealed and pickled or Black) of rectangular shape; of grade either 304 or 304H or 304L or 304N or 304LN or EN 1.4311, EN 1.4301, EN1.4307 or X5CRNI1810 or X04Cr19Ni9, or equivalents thereof in any other standards such as UNS, DIN, JIS, BIS, EN, etc.; whether or not with number one or Black finish; whether or not of quality prime or non-prime; whether or not of edge condition with mill edge or trim edge; of thickness in the range of 1.2mm to 10.5 mm in Coils and 3mm to 105 mm in Plates & Sheets; of all widths up to 1650 mm (width tolerance of + 20 mm for mill edge and + 5mm for trim edge)."

24. The interested parties have reiterated their respective stands on the product under consideration in their post disclosure submissions. The Authority notes that the issues raised by the interested parties have been adequately

addressed in the previous paragraphs and do not need further elaboration. Therefore, the Authority confirms the product under consideration as above.

C. Domestic Industry and Standing

25. The application has been filed by M/s Jindal Stainless Limited, New Delhi and the applicant is one of the major producers of the subject goods in India. The Authority notes that there are only two other producers of the subject goods in India i.e., M/s Steel Authority of India Limited and M/s Shah Alloys who also manufactures the subject goods in India.

26. Before initiation of the investigation the Authority called for further information from the above known domestic producers in this regard for determination of the standing of the applicant domestic industry. Efforts were also made to ascertain the production of the subject goods by other Indian producers. The Authority also examined the information available in the public domain in respect of capacities and production of other domestic producers of the subject goods in the domestic market. It has been brought to the notice of the Authority that none of the other Indian steel makers, except mentioned herein above, produced Hot Rolled Stainless Steel for commercial sale and therefore, do not qualify to be included as a part of the domestic industry.

27. Taking into account the reported/estimated capacities and production of other known producers of the subject goods the applicant commands a major proportion of the domestic production of the subject goods in the country. None of the interested parties have raised any issue regarding the standing of the applicant. Therefore, the Authority holds that the applicant commands a major proportion of the production of the subject goods in India and for the purpose of this investigation the applicant i.e. M/s Jindal Stainless Limited commands the standing in terms of Rule 5(3) and constitutes the domestic industry in terms of Rule 2(b).

D. De Minimis Limits

28. As per the import data received by the Authority from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and other secondary sources (IBIS), as well as the data furnished by the cooperating exporters from the subject countries, the imports of the subject goods from the subject countries are found to be above the de minimis level.

E. Interested Parties to the investigation

29. The Authority notes that one producer/exporter of the subject goods in China i.e. Lianzhong Stainless Steel Corporation and one producer/exporter from Malaysia i.e. Bahru Stainless have submitted their responses to the exporter's questionnaire. One trader/exporter of the goods manufactured in China located in Singapore i.e. M/s Century Steel Pte. Ltd. has also filled a questionnaire response. None of the producers/exporters from Korea has filled any questionnaire response. However, M/s POSCO, Korea; M/s Hyundai, Korea and M/s Hyou Sung, Korea have filed a combined injury submission opposing the claims of the domestic industry on various grounds.

30. The following importers/consumers have filed importers questionnaire response/injury submissions:

1. Ratnamani Metals and Tubes Limited
2. Bhandari Foils and Tubes Limited
3. Hindustan Inox Limited
4. JNB Steel Industries Private Limited
5. Kansara Popatlal Tibhovandas Metals Private Limited
6. Santosh Steel Industries
7. Shalco Industries Private Limited
8. Subhalaxmi Metals and Tubes Pvt. Ltd.
9. SNB Enterprises Pvt. Ltd.
10. Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd.
11. Sunrise Stainless Pvt. Ltd.
12. Varun Foils Ltd.
13. Suncity Sheets Pvt. Ltd.
14. Navgrah Fastners Pvt. Ltd.

31. The domestic industry has argued that POSCO Korea had earlier participated and submitted questionnaire response in the investigation concerning Cold Rolled Flat products. However, the company has refrained from submitting questionnaire response this time, stating that they are not dumping the goods. It has been submitted by the domestic industry that existence or otherwise of dumping is a fact, whose existence or otherwise can be determined by the Designated Authority only after analysing the facts. Without providing questionnaire response with relevant data, a party cannot just make statement that they are not dumping. In fact non-submission of response implies that there is significant dumping practiced by POSCO.

32. Domestic industry has further argued that while an interested party has a right to participate in the investigations and advance its argument, its first obligation is to provide relevant information prescribed by the Authority. The Authority has prescribed a questionnaire for providing relevant information. This prescription cannot be circumvented, even by presenting arguments. The information demanded by the Authority through the questionnaire is highly pertinent to the investigations and the exporter should have filed questionnaire response.

33. The Authority notes that POSCO Korea and other exporters have made certain arguments in respect of various aspects of the investigation without filing any questionnaire response for determination of dumping, if any, and extent thereof. Therefore, the Authority is not in a position to examine their claims with regard to no dumping from Korea. However, their submission with regard to the other aspects of the investigation have been taken on record and examined along with the arguments made by other interested parties and have been addressed in these findings to the extent they are relevant and backed by verifiable evidence.

F. Miscellaneous issues raised by the interested parties

F.1 Views of the other interested parties

34. The interested parties and the domestic industry have raised several issues with respect to the present investigation, including methodologies of dumping determination and injury claims of the domestic industry. While the issues regarding the dumping and injury determination have been dealt in the appropriate places in this finding, the general issues raised by the parties to the investigation have been examined hereunder. For the sake of brevity the submissions of the parties and issues raised therein have been summarized as follows:

- That the investigation was initiated with 9 months gap between the end of the period of data collection and the initiation. Such a huge gap of 9 months cannot qualify as “*ending close to the date of initiation*” in terms of the WTO mandated investigating practices. The Authority in the present case is in violation of the above requirement set by the WTO. Therefore, the present initiation is bad in law and should be immediately terminated on this ground alone.
- That the Applicant has simply stated that it could not find any price details with respect to the prices in a market economy third country or the constructed normal value in a market economy third country. This is a clear case of non-fulfillment of the mandatory requirements of a complete application. Without any submissions on the price or constructed normal value in a market economy third country, the application is clearly incomplete.
- That the applicant has not been able to adduce a single bit of evidence regarding the prices of the subject good prevailing in a market economy third country; Prices of the subject good from such third country to other countries, including India; Raw material cost for subject goods, which was allegedly taken 'on the basis of the international price of the major raw materials; Adjustments with regard to export price (ocean freight, inland transportation cost, VAT loss, sales commission, bank charges, port handling & charges and marine insurance). Under these circumstances the Authority could not have satisfied itself as to the “accuracy and adequacy” of the evidence presented.
- That if constructed normal value is fully accepted based on the experience of the Applicant, the requirement to provide normal value with evidence will become redundant because whenever there is price undercutting/underselling, the normal value will show the assumed dumping behavior of the exporter even though there may not be any dumping with reference to actual normal value.
- The interested parties in their submissions have argued that the consumption norms of the participating exporter must be considered in the present investigation for determination of normal value.
- That M/s Jindal Stainless Steel is also exporting HR SS Coils and CR SS Coils above 304 series and their prices are comparable with export prices of suppliers from China, Korea and Malaysia. Therefore, there is no ground for Anti dumping duty.

- That the purpose of applicant is to gain monopoly status and damage the domestic industry of finished goods where HR SS coil/ CR SS coil series 304 are used as input.
- That the prices charged by the applicant in domestic market and export market are already higher and for protection of higher prices in domestic market applicant is seeking Anti Dumping Duty.
- That the applicant industry is exporting mainly CR SS Coils of 304 series and difference in price of CR SS Coils and HR Coils is approx. 200 USD per MT and as such the export price in international market will be 200 USD less than CR SS Coil of 304 series. Therefore, the price of HR coils may be ascertained by reverse charge method.
- That if anti dumping duty is imposed, the product in the Indian market will be more costly and ultimate users will be affected. Anti Dumping duty on the product will seriously impact the domestic user industry and their finished products such as process equipments, re-rolling, reactor vessel, material handling equipments, railways, pipes and tubes, automatic components, rolled and formed sections, architectural and building and construction industry, fabrication and power sector etc.
- That international suppliers of China PR, Korea and Malaysia are not competitors of Jindal Stainless Limited because international suppliers' manufacture HR coils of width up to 900mm whereas applicant industry manufactures HR coils exceeding 1000mm. The technology and manufacturing process used by these countries are also different.
- That the foreign manufacturers have lesser cost of manufacturing due to efficiency in their operation and scale of production. They are also giving better quality product of stainless steel at lesser price and are not dumping the product in India.
- That majority of production is done by Applicant i.e. 90% and rest 10% is done by M/s Salem Steel. Applicant is not supplying goods to those who are not solely purchasing from them and they are also exploiting the small buyers by dictating their terms. If Anti dumping duty is imposed then Applicant will have complete monopoly in the market.
- That applicant already have over valued plant and the same cannot be competitive compared to the foreign manufacturer of such goods and anti dumping is not a remedy.
- That applicant is already at advantage than the foreign suppliers as they get major raw material like iron ore, chrome within the country whereas foreign suppliers has to import these raw materials.
- That applicant domestic industry's funding pattern should be examined to ascertain whether they are solely used for manufacturing purpose or used in their subsidiary as interest free loan, etc.
- That Hot Rolled products produced by JSL have hot rolling marks on both the sides which are not seen on overseas vendor. The pipe manufacturers have to buy extra widths to remove those defects.
- That the applicant is not in a position to manufacture specific width in specific thickness for small quantity. Coils supplied by JSL, a minimum of 3 meters in the front end and rear end will have major quality issues, which increases the wastage.
- That the delivery by JSL is not on time and transportation charges are very expensive because they delivered through Road which costs Rs. 4000 per MT.
- That the non-confidential version of the petition is wholly deficient and not sufficient to provide reasonable summary of information treated confidential inter alia in the petition in complete violation of AD rules pertaining to confidentiality.
- That the domestic industry has claimed unwarranted and highly excessive confidentiality on costing information and meaningful summary has also not been provided.
- That the domestic industry has resorted to constructing the Normal Value for the purpose of determining dumping margin and it would be absolutely unfair if the importers/users are not allowed to comment upon the information relied upon to construct normal value which has a direct bearing on them.
- That the Authority should disclose the complete transaction-wise import data to all interested parties through the public folder.

F.2 Views of the Domestic Industry

35. The domestic industry, in its submissions, has refuted the arguments of the interested parties. The submissions of the domestic industry, in this respect, have been summarized as follows:

- That the petition was filed with most recent period. In any case, no prejudice has been caused by consideration of the present period of investigation. On the contrary, performance of the domestic industry has further deteriorated in the period after the present period of investigation, as is well established by the statement enclosed with the rejoinder submission. It would be seen that the imports have increased significantly after the period of investigation and the losses suffered by the domestic industry have significantly increased in the post period of investigation.
- That China's massive capacity expansion and unfair cost advantages have led to a situation where it is involved in global dumping. There is a plethora of cases against China involving steel. The industry has to, therefore, match prices in order to sustain in the global market. While petitioner does not have a mechanism to restrict other countries from dumping globally, the petitioner has the right and legitimate expectation from its country's Government to provide remedy against dumping in the home land;
- That evidence with regard to the adjustments to the extent possible has been given, such as evidence of ocean freight and VAT. For other adjustments, conservative figures have been considered. The exporter participating in the investigation would certainly be able to provide such information as they are privy of it.
- That as regards the argument that the petitioner has not provided credible information on actual and potential effects of dumped imports the domestic industry has argued that potential word means 'possible' or 'probable' and that it has been substantiated that dumping has caused current decline in performance of the domestic industry in various parameters. This fact itself is a ground for potential further decline in the performance of the domestic industry.
- That the Authority has been consistently examining actual performance of the domestic industry over the injury period. It is only in a situation where actual performance over the injury period does not show injury to the domestic industry that the authority is required to examine potential situation with regard to various economic parameters.
- That confidentiality, where warranted, has been claimed and the Authority after verifying the same has granted the same. Petitioner has provided index information wherever warranted. No specific instances have been pointed out where the petitioner could have provided actual information and the petitioner has withheld the same. It has been argued by the DI that the importers have filed questionnaire response wherein the details of volume parameters such as imports and inventories have not been disclosed. While import volumes and inventories have been claimed as business sensitive for these importers they consider that even cost of production, selling price and profit/loss is not confidential for the petitioner.
- That there is no legal and factual basis in the arguments of the interested parties for placing the transaction-wise import data collected by the Authority in the public folder. The Authority requires petitioners to provide information with regard to volume and value of imports and source of information. The Authority does not require the petitioners to provide transaction by transaction data. To such an extent, it should be concluded that the transaction by transaction information provided by the petitioner is beyond the requirements prescribed by the authority.
- That as regards rights of interested parties, their right is limited to comment on the claim of the domestic industry with regard to volume, value and price of imports. The interested parties have liberty to defend their interests on the basis of this information. The interested parties cannot demand the information with regard to transaction wise data on this account.
- That the transaction wise data is required by the Designated Authority only to satisfy itself with regard to adequacy and accuracy of information/evidence contained in the petition. However, such requirement is for the Designated Authority and does not generate a right on the interested parties to demand the relevant evidence.
- That the Designated Authority is required to satisfy itself with regard to adequacy and accuracy of information provided by the interested parties; and for this purpose, the Designated Authority seeks elaborate information from the exporters and verifies the same. However, the domestic industry is not provided access to such information.

- That if the argument of the exporter was to be accepted, it implies that the invoice by invoice details of exports and domestic sales made by the exporter must also be made available to the domestic industry in order to allow them to check the correctness of their data.
- That without prejudice, transaction wise details of imports have been made available by the petitioner in the present case. Thus, while legally the petitioner is not required to provide this information, on facts, the petitioner has in fact provided this information and therefore the entire argument is without any basis.
- That the prices from market economy third country to India could not be adopted for the reason that these prices from third countries to India are affected by Chinese dumping and thus inappropriate. Under the circumstances, normal value is required to be determined considering price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin.
- That price actually paid in India could not have been considered for the reason that the same were below cost of production. Thus, the only option with the Authority was to consider cost of production in India, duly adjusted, to reflect international raw material prices and optimum conversion costs, selling, general & administrative expenses and reasonable profit. The Chinese producers, or importers or any other interested party has made no claim nor advanced any evidence either with regard to price or constructed value in a market economy third country.
- That UN Comtrade data could not be adopted for submission as evidence of Normal Value for reason that the customs classification is not dedicated to product under consideration. Product under consideration is classified under customs sub-heading 7219 and 7220. UN Comtrade gives information for custom classification at 6 digit level. This classification code does not even describe the series of stainless Steel Products. It is likely that UN Comtrade would include products other than product under consideration. Such being the case, customs data of the other countries could not be adopted. Further, import price from third countries into India could not be adopted for the reason that the same are either at dumped prices or are influenced by present dumping.

F.3 Examination by the Authority

36. Various miscellaneous issues raised by the interested parties have been examined and addressed as follows:

- As regards the gap between the period of investigation and the date of initiation is concerned, the Authority notes that there is no legally binding obligation on the Authority to adopt any specific time limit for adoption of the POI though the Authority is fully guided by the best endeavor guidance and tries to adhere to the most recent period for investigation purpose. In the factual matrix of the case the investigation has been initiated with a period of data collection which is applicable for both domestic industry as well as the exporters. The domestic industry has submitted that the injury has intensified after the POI due to higher volume of imports in the post POI period. Therefore, the interests of the other interested parties have not been affected because of the gap between the period of data collection and date of initiation.
- As regards the adequacy and accuracy of information submitted by the petitioner in the application with respect to evidence of normal values and export prices the Authority notes that on the basis of an objective examination of the prime facie evidence submitted by the petitioner the investigation was initiated. The petitioner has explained the circumstances under which direct evidence of the normal values in the countries of exports could not be produced and after an objective examination of the same alternative methods of assessment of normal value has been accepted at the initiation stage. The adjustments to the export prices were effected after examination of information placed before the Authority by the petitioner. Therefore, the Authority holds that the investigation was in no way vitiated because of the fact that the normal values and export prices were assessed at the initiation stage by using alternative methods as no direct evidence of prices prevailing in the subject countries were available.
- As regards the arguments of the interested parties that the petitioner has not established *potential decline* anywhere in the petition and the allegations with regard to injury should be dismissed for inconsistency with Article 3.4 the Authority notes that the domestic industry, in its petition before the Authority, had made out a *prima facie* case of actual decline in certain parameters related to physical and financial performance of the domestic industry due to volume and price effect of the dumped imports. Therefore, at that stage there was no need to seek information on the potential or possible impact of the dumped imports.

- As regards the price behavior of the domestic industry in the export market and domestic market as raised by certain interested parties, the Authority notes the submission of the domestic industry that their price behavior in the external markets is impacted by overwhelming presence of dumped imports in several market from the subject countries which is borne out of the fact that several trade remedy actions have been taken by many WTO members on steel products. The Authority also notes that the performance of the petitioner on account of its export prices in external market has no bearing in this case as the injury suffered by the petitioner on account of its domestic operation only has been examined separately and injury, if any, on account of exports has not been attributed to the injury suffered in domestic operation of the petitioner. Therefore, the arguments of the interested parties in this regard have not been found to be tenable.
- As regards the arguments of the interested parties to provide them transaction-wise import data considered by the Authority in this investigation, the Authority notes that the Rules do not require the Authority to place the information collected from other sources, other than the information provided by the interested parties on non-confidential basis, in the public folder. The information/data collected by the Authority from other agencies have been analysed in the best possible manner and used in the findings to the extent they are relevant. Therefore, the requests of the interested parties cannot be acceded to.
- As regards the arguments of the interested parties regarding the anti-competitive and monopolistic behavior of the petitioner; quality and delivery issues; and public interest issues, are concerned, the Authority notes that the purpose of the antidumping investigations are aimed at identifying and removing the effects of dumped imports to create a level playing field for the domestic manufacturers against unfair price behavior of foreign producers and not to restrict imports or create a monopolistic situation. The domestic industry has the right under the law to seek such remedial measure. The importers and users are free to import the goods as per their requirement at un-dumped prices.
- As far as the issues raised by the interested parties regarding the confidentiality claims are concerned, the Authority notes that to the extent possible and practicable the confidentiality claims of various parties submitting the information have been examined and confidentiality claims admitted on the basis of nature of information provided by the parties. The Authority notes that import data and volume statistics, etc. have been placed in the public folder and no confidentiality has been admitted for such information which are not business proprietary information or sensitive for the domestic industry. However, keeping in view that estimation of the normal value for the Chinese exporters has been done on the basis of the operating information of the domestic industry and breakup of various elements of such an estimated value is business sensitive information for the domestic industry, detailed breakup was not provided in the public file. As far as the submissions of the exporters are concerned, the information provided by the exporters, to the extent they are not business sensitive to the party providing the same, have been placed in the public folders. In view of the above the objections of all parties with respect to confidentiality claims of the opposing parties have been disposed off.

G. Methodology and Determination of Dumping Margin

37. The Authority notes that the following producers/exporters of the subject goods from the subject countries have filed questionnaire response:

- (i) M/s Bahru Stainless, Malaysia; and
- (ii) M/s Lianzhong Stainless Steel Corporation, China; and
- (iii) M/s Century Steel Pte. Ltd.; Singapore (Exporter)

38. No questionnaire response has been received from any producer/exporter from Korea RP. Certain interested parties have argued that the consumption norms of the participating exporter must be considered in the present investigation for determination of normal value. In this connection the Authority notes that the Normal values in the countries of export has been determined depending upon the level of participation of the exporters in the investigation and the data submitted by them. To the extent credible information on the consumption norms etc. have been placed before the Authority the same has been used to the extent they are supported by verifiable evidence. Accordingly, the claims of alleged dumping have been examined and the margins of dumping from each of the subject countries have been determined as follows:

G.1 Malaysia

39. As per the import data analysed by the Authority 1584 MTs of the subject goods were imported from Malaysia during the POI. Only one exporter from Malaysia, i.e., M/s Bahru Stainless Steel, has filed a questionnaire response. The

questionnaire response was examined and supplementary information was sought from the exporter and the exporter filed certain supplementary information in response to the same. The response and the data submitted by the exporter have been examined by the Authority.

40. M/s Bahru Stainless has submitted that it is a private limited company incorporated and registered in Malaysia on the 27th March 2008 with over ***% shareholding by M/s ACERINOX, S.A. Spain and M/s Nisshin Steel Co., Ltd. Bahru also has a related company in Malaysia i.e., M/s ACERINOX SC Malaysia SDN BHD (“ACERINOX SC”), which had exported small volumes of the product concerned to India during the POI (**** MT).

41. M/s Bahru Stainless, in its submissions, has also submitted that ACERINOX SC acquired ACERINOX Malaysia SDN BHD (“ACERINOX MALAYSIA”) in April 2013. ACERINOX MALAYSIA had also exported small volumes of the product concerned to India during the POI (**** MT). After acquiring Acerinox Malaysia SDN BHD, Acerinox SC Malaysia SDN BHD had stopped exporting the subject product to India from September 2013.

42. It has been further submitted that Acerinox SC; Malaysia SDN BHD and Acerinox Malaysia SDN BHD procured ‘Hot-Rolled N1 Coil’, which is a finished product from Spain, South Africa and USA and performed simple cutting operation on the aforesaid material to achieve desired lengths. Such cut length products were then supplied to customers in India. Products exported by Acerinox SC Malaysia SDN BHD and Acerinox Malaysia SDN BHD retained their origin as Spain, South Africa and USA, from where Hot-Rolled N1 Coil was procured and are already subject to anti-dumping duty vide Notification No. 104/2011-Customs dated 25th November, 2011. Therefore, these two Companies, i.e., M/s Acerinox SC Malaysia SDN BHD and M/s Acerinox Malaysia SDN, related to Bahru Stainless, have not submitted the details of their exports to India in this investigation.

i) M/s Bahru Stainless, Malaysia

43. M/s Bahru Stainless has filed a detailed questionnaire response and has submitted that their main activity is production of Cold Rolled Stainless Steel flat products. However, they have also exported to India Hot Rolled flat products of stainless steel (N1 products) which are covered within the scope of the product under investigation. But the hot rolled flat products of stainless steel exported by them to India are not of Malaysian ‘country of origin’. It has been submitted that Bahru Stainless procures Black Coils from various suppliers outside Malaysia and performs annealing and pickling activities on such Black Coils. After performing annealing and pickling activities, the coils are cut to required sizes and thereafter supplied to the customers in India. The HS Code for Black Coils procured by Bahru Stainless and the HS Code for N 1 products exported by Bahru Stainless to India is same and there is no change in the tariff heading (at 4 digit level) or subheading (at six digit level). Accordingly, the country of origin of such hot rolled flat products of stainless steel exported by Bahru Stainless to India is not Malaysia but the country from where Black Coils are procured. During the POI, Bahru Stainless sourced Black Coils from several related and unrelated companies, in South Africa; Spain; Japan, Korea, China, Singapore and Hong Kong for supplying the product under consideration to India.

44. Though the manufacturing and export operations of Bahru are significantly different from that of Acerinox SC Malaysia SDN BHD and Acerinox Malaysia SDN BHD as outlined above, it has been argued by Bahru that there is hardly any value addition in the aforementioned processes, and value addition, if any, does not qualify as providing status of origin from Malaysia under the ASEAN-India FTA Rules of Origin notified under Notification No. 189/2009 - Customs (N.T.) dated 31.12. 2009. The ASEAN-India FTA Rules of Origin lay down two requirements which have to be met for achieving origin status from a member FTA country to seek and get exemption from Customs Duty. Firstly, Rule 5(1)(i) requires an entity in a member FTA country, such as Malaysia, to make at least a 35% value addition to the end product as a ratio of its FOB price to be considered as originating in that FTA country. Secondly, Rule 5(1)(ii) requires that a product shall be deemed to be originating from Malaysia if the non-originating materials undergo at least a change in tariff sub-heading (CTSH) level i.e. at six-digit level of the Harmonized System.

45. Further, it has been argued that cutting operation does not qualify Malaysian origin to a product under the ASEAN-India Rules of Origin, as cutting operation is expressly excluded under Rule 7(1)(b) and this is the reason that the Bahru does not provided a Certificate of Origin showing Malaysia as origin to an importer in India for claiming any concessional benefits under ASEAN-India FTA.

46. Bahru has argued that as there is no production of the subject products in Malaysia, the present investigation against Malaysia should be terminated in line with India’s consistent practice and practice in other jurisdictions.

47. Bahru has further argued that Bahru and its related companies are the only exporters of the subject goods from Malaysia that have exported small volumes of the product concerned to India during the POI. Further, there are no other exporters of the subject goods from Malaysia. Bahru initially filed only Appendix-2 of the questionnaire response related

to export sales to India. However, subsequently, in response to deficiency letter they submitted other appendices, including domestic sales details.

48. Bahru further argued that total import volume of the subject products from Malaysia during the POI is only 1232.02 MT as compared to 1584 MT projected in the petition. Therefore, the data presented in the petition concerning the import volume of the subject product from Malaysia in the POI is factually incorrect. It has also been argued that imports of the subject products from Malaysia comprise only 0.75% in domestic demand (including captive). Even assuming that this figure is correct, the Malaysian imports comprise less than 1% in demand, which is too insignificant to cause any injury to the domestic industry.

Views of the Domestic Industry

49. The domestic industry has contested the claims of the exporter and has argued that M/s Bahru Stainless Sdn Bhd is already attracting ADD if the goods are produced by its sister concern, Columbus Stainless (PTY) Ltd, South Africa. In fact the combination of Columbus Stainless (PTY) Ltd, South Africa (producer) and Acerinox Malaysia Sdn Bhd (parent company) also attracts ADD. It is evident from the annual report of Bahru as well as various independently published reports that black coils are being procured from its sister concern, i.e., Columbus Stainless (PTY) Ltd, South Africa. By admitting that they are merely importing black coils and are simply carrying out Annealing Pickling operation in Malaysia, the exporter is clearly presenting two different positions before two different authorities i.e., (a) before Customs Authority wherein the goods have been declared as originating in Malaysia; and (b) before Designated Authority wherein it has been claimed that the exporter is not a producer, but only an exporter of goods produced in some other country. While the Customs Authorities need to take appropriate action with regard to applicability of anti dumping duty and origin of goods, the current application before the Designated Authority is in respect of exports of goods from Malaysia and is thus clearly maintainable, as the imports statistics shows imports from Malaysia.

50. It has been argued by the domestic industry that Anti dumping duty is imposed on imports into India from a country. The law is not restricted to '*producers*' from such subject country, but is also extended to '*exporters*' from such country. Anti-Dumping Duty is based on the combination of producers and exporters. Even assuming that there is no actual production in Malaysia, even then the exports of subject goods from countries having exports above the level of de minimus would attract anti dumping duties. The issue is well decided by the Designated Authority in the past investigations relating to, such as, DVD-R, CFL, CDR, to name a few.

Examination of the Authority and determination of Normal Value

51. The Authority notes that the responding exporter from Malaysia has claimed that the black coils of HR are imported by them from several manufacturers in several countries, some of them being their related/group concerns and further processed before being exported to India. This has not been contested by the domestic industry also. The only issue being contested is whether the annealing and pickling, and slitting operation being carried out by them in Malaysia qualifies the status of originating goods from Malaysia as per Indo-ASEAN FTA. Bahru has claimed that the annealing and Pickling, and slitting operation carried out by them does not confer the goods originating status as per the FTA as it does not give the value addition prescribed and there is no change in the tariff heading (at 4 digit level) or subheading (at six digit level). Therefore, Bahru claims that the country of origin of such hot rolled flat products of stainless steel exported by Bahru Stainless to India is not Malaysia but the country from where Black Coils are procured, and therefore, the investigation against Malaysia should be dropped.

52. Domestic industry has argued that Bahru has in fact claimed the goods are of Malaysian origin before the customs Authority as the import data received by the Authority from DGCI&S would show the goods as of Malaysian Origin and the importer might have claimed preferential duty under FTA on the basis of such Rules of Origin Certificate issued by the exporter in Malaysia.

53. Bahru has submitted that Bahru does not provide a Certificate of Origin showing Malaysia as origin to an importer in India for claiming any concessional benefits under ASEAN-India FTA. But the fact remains that the import data submitted by DGCI&S shows the goods are of Malaysian origin which means that the importers have cleared the goods as Malaysian origin against certificates of origin issued by the concerned authorities in Malaysia.

54. The Authority also notes that the domestic industry has taken up the alleged mis-declaration of the origin of the goods exported from Malaysia and collection of antidumping duty imposed on goods of South Africa, EU and USA origin with the appropriate Authorities in the Department of Revenue.

55. While whether the goods have been wrongly declared as of Malaysian origin and cleared under Indo-ASEAN FTA preferential duty arrangement is a matter of separate investigation by the concerned agencies/authorities, there is no denying the fact that the goods exported from Malaysia are not of Malaysian origin as per the rules of origin under the FTA.

56. The Arguments of Bahru that since the goods are not of Malaysian origin, the investigation against Malaysia should be dropped is not tenable in view of the fact that the goods are being exported from Malaysia. The black coils have been procured by the responding exporter from several manufacturers in different countries and these coils have undergone further minor processing in Malaysia before exporting to India and other countries. Therefore, the Authority holds that Bahru cannot be treated as a producer of the subject goods and individual treatment cannot be granted to them for determination of their dumping margin.

57. The Authority also notes that apart from the responding exporter M/s Bahru Stainless Steel their related Company M/s ACERINOX SC Malaysia SDN BHD (“ACERINOX SC”), which had exported **** MT during the POI. ACERINOX MALAYSIA had also exported **** MT to India during the POI. As per the submissions of Bahru these two companies have stopped exports to India. None of these parties have submitted any information about their exports. Therefore, all exporters in Malaysia have been treated as non-cooperative and the dumping margin for all exporters from Malaysia has been determined based on the facts available.

58. In view of the position explained above in the absence of any other reasonable method of determination of Normal Value in Malaysia the Authority has constructed the Normal value in Malaysia. For the purpose of construction of Normal Value in Malaysia the international price of major raw materials, to the extent they were available and most efficient conversion cost of the domestic industry has been considered. A reasonable margin of profit has been added to arrive at the weighted average constructed normal value of the subject goods in Malaysia at ex-works level. Accordingly, weighted average ex-works Normal value for the product under consideration in Malaysia has been determined as US\$ ****/MT.

Export Price

59. As per the import data 1584 MTs of the subject goods were imported from Malaysia during the POI at an average CIF price of Rs137384/- (US\$2512/-) per MT. After adjusting the CIF price for all post sales expenses including inland and ocean freight and insurances and, bank charges and credit costs etc. on the basis of facts available taking into account information available in cooperating exporter’s response, the net export price at ex-works level works out as US\$**** per MT.

Dumping Margin: Malaysia

60. The ex-works normal value has been compared with the ex-works export price to arrive at the dumping margin as follows:

CIF	Adjustments	EP	CNV	DM	DM %
US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	
2,512.05	****	****	****	****	10-20%

G.2 China PR

61. The Authority notes that as per the import data analysed China has exported 30,589 MTs of the subject goods to India during the POI. However, only one Chinese producing Company i.e., M/s Lianzhong Stainless Steel Corp. (“LISCO”) has filed a questionnaire response along with Market Economy Treatment Questionnaire Response. During the POI LISCO has exported **** MT of the subject goods to India out of which **** MTs have been exported through M/s Century Steel Pte. Ltd., Singapore (Century). Century has also filed a separate questionnaire response as an exporter of goods manufactured by LISCO, China.

i) M/s Lianzhong Stainless Steel Corporation, China PR

Examination of Market Economy claims of LISCO

62. The Authority notes that M/s Lianzhong Stainless Steel Corporation, one of the producers and exporters of the subject goods from China PR has submitted its questionnaire responses and market economy questionnaire responses and has rebutted the non-market economy presumption. On the basis of preliminary examination of the questionnaire response and the MET claims of this exporter a letter was issued to them asking for certain additional information/clarification vide letter dated 14th August 2014. The exporter, *vide* letters dated 8th September and 18th September 2014, filed certain clarification/additional information.

63. LISCO, has submitted that it is a producer and exporter engaged in the production and exports of the product under consideration solely from China. LISCO has also submitted that in a previous antidumping duty investigation of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel from China PR, Japan, Korea, European Union, South Africa, Taiwan (Chinese Taipei), Thailand and USA (No.14/06/2008-DGAD, dated 24th November 2009), LISCO was granted market economy status by the Authority.

64. As per the questionnaire response LISCO was a wholly foreign-owned enterprise established in December 2001 by its Taiwan parent company, Yieh United Steel Corporation ("YUSCO"). YUSCO owned ***% of LISCO's shares through a holding company incorporated in the British Virgin Islands, and another holding company incorporated in Samoa. YUSCO owned ***% of both the holding Companies. At the inception of establishment of LISCO, the first holding Company was the sole shareholder of LISCO. On July 8, 2002, it transferred its ***% of shares holding at LISCO to the second holding Company. After this transfer of shares, the first holding Co. owned *** % of LISCO and the second holding Co. owned ***% of LISCO, respectively. This transfer of shares between the holding companies did not change LISCO's legal form as a wholly foreign-owned enterprise. Both LISCO and its parent YUSCO are members of "E United Group" in Taiwan. E United Group is not a legal entity but a group of companies with cross-ownership and/or with common control by Mr. I. S. Lin, the chairman of YUSCO. Other than the steel industry, E United Group is also involved in businesses such as education, health care, and real estate development, etc.

65. It was submitted that LISCO was controlled by its board of directors as a wholly foreign-owned company and was free to repatriate capital and profits based on the resolution of its board of directors, as stipulated in LISCO's Articles of Association. LISCO did not have any relationship with any level of the PRC government, including the ministries or offices of any level of the government.

66. Responding to domestic industry's submission that LISCO is in the process of being acquired by a State owned enterprise LISCO had further submitted that LISCO's legal structure as a wholly-owned subsidiary of its Taiwan parent, Yieh United Steel Corporation, has never been changed since the period of investigation of the underlying investigation while it is true that LISCO this year has been in discussions with several potential business partners (including companies in Taiwan, Korea, Japan, China and several other countries) in acquiring a certain portion of LISCO's shares. But nothing was concrete at that point.

Views of the domestic industry

67. The domestic industry, in its submissions, has argued that China is a non-market economy and has been treated as such by European Union and United States as well this Authority in the past three years. Even China agreed in the accession treaty that WTO Members could use an NME antidumping methodology till December 11, 2016. Domestic industry has further argued:

- That AD Rules have prescribed certain conditions that have to be satisfied in order to establish the claim of market economy treatment. It is to be noted that each and every condition must be fulfilled by an intending exporter in order to claim market economy treatment.
- That except where the responding Chinese exporters confirm to each of these standards, the Designated Authority is required to determine normal value in accordance with Para 7 of Annexure-I to the AD Rules.
- That based on various pronouncements relating to examination of market economy status by India and other investigating authorities, certain jurisprudence has clearly emerged and Market economy status cannot be granted unless the responding exporters satisfy/establish certain conditions, which inter alia include:
 - That there is no major state ownership/control;
 - That the prices of major inputs substantially reflect market values prevailing in the international market;
 - That their books are audited in line with international accounting standards
- That market economy status cannot be granted to a responding exporter in China unless Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules. It is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected.
- That there are various news articles that show that Ansteel Group is going to acquire a 60% stake in LISCO. Ansteel Group, a large-sized steel production base in China, is a State-owned enterprise and has the reputation as the "Cradle of the Chinese Steel Industry" and the "Eldest Son of the Republic's Steel Industry". It has been argued that with 60% stake being held by a State owned company, it cannot be contended that the government interference would not be there and this proposed change in the legal status of the exporter will have a direct bearing on the case.

- That raw material forms 87% of total cost of production of the product under consideration and therefore it is of utmost importance whether prices of inputs reasonably reflect the market values. The exporter has provided no evidence to establish that prices of inputs consumed by the exporter reasonably reflect the market values. The exporter has in fact admitted that one of the raw material i.e., steel scrap, has been procured from two of its affiliated companies. The Company has purchased raw material from other local domestic supplier as well which are not operating under market economy conditions.
- That LISCO is admittedly governed by the Pricing law of China which is formulated to promote the socialist market economy. Article 6 of the law to provide for framing of own pricing policy. Exception is given under Article 18, which states that “the government shall issue government set or guided prices for few merchandises that are of great importance to development of the national economy steel industry is undeniably merchandise that is of great importance to national economy, and by virtue of the above Article, the prices of steel shall be controlled by the Government of China.
- That the Government of China has issued a “Catalogue of Major Industries, Products, and Technologies Encouraged for Development in China” (Encouraged Industries Catalogue). The said catalogue identifies “Steel and Iron”, “low-alloy steel and micro-alloy steel”, “Stainless steel smelting”, “Hot- and cold-rolling stainless steel sheet” “Processing and treatment of scrap steel” as encouraged industries.
- That the Catalogue of Encouraged Foreign Investment Industries considers “ Manufacturing of nickel-saving stainless steel products”, “Manufacturing of the equipment of coal-fired power plant and de-nitrification technology for sintering machine in steel industry” as encouraged industries.
- That the Govt. of China has promulgated the Policies for Development of Iron and Steel industry which has various provisions to facilitate steel industries.

Examination by the Authority and Determination of Normal Value (LISCO)

68. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China provide(s) information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3) in Paragraph 8 and prove to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People’s Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-

- (a) the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
- (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

69. The Authority notes that LISCO was granted market economy treatment in an earlier investigation in 2009 concerning certain cold rolled steel products. LISCO, in its questionnaire response submissions contended that there has not been any significant change in the status of the Company in terms of management or business structure since then though there are discussions with several potential business partners (including companies in Taiwan, Korea, Japan, China and several other countries) in acquiring a certain portion of LISCO’s shares, nothing was concrete at that point.

70. On spot verification of the information submitted by the Company was carried out on 29-30, January, 2015 in China. During the verification the company informed that ****% of the shares of LISCO has been acquired by M/s Ansteel Group Corporation, a State owned Company, in China PR, on 24th December, 2014 and accordingly, the name of the Company has been changed to M/s Ansteel Lianzhong Stainless Steel Corporation as a limited liability Sino-foreign joint venture with a registered capital of RMB ****. With this acquisition the shareholding of the Company stands as follows: Public Zone Co. Ltd, registered in British Virgin Islands ****%; Ansteel Group Coprp, China ****%; and Valley Field Ltd, Samoa ****%. It was also noted that with this acquisition there is a change in the composition in the

board. The board now consists of seven members with four members representing Ansteel, two representing Public Zone Co. and one member representing Valley Field Ltd. It was mentioned by the Company that Ansteel is a major Carbon steel producer in China and is diversifying into stainless steel business with this acquisition.

71. The Company also informed that they will soon file the required documents with the Authority informing about this development and change in the status as well as the name of the Company and the earlier submissions made by LISCO should be subsumed as the submission on behalf of the new entity i.e., M/s Ansteel Lianzhong Stainless Steel Corporation.

72. In the light of the above the production process and cost of production of the subject goods manufactured by the Company during the POI were also examined. Examination of the data submitted by the exporter indicates that it procured most of the major raw materials locally from their affiliated Companies as well as unaffiliated companies. Major portion of the raw materials have been procured from unaffiliated suppliers in China. There is a significant difference between the prices of major raw materials procured from the unaffiliated suppliers in China when compared to the prices at which the goods have been sourced outside China as well as its affiliated suppliers. No information is available on the market economy status of the major raw material suppliers in China and the difference in price of various raw materials procured by the exporter from different sources indicates that the cost and prices of the raw materials in China procured by the exporter for production of the subject goods do not reflect the true market value of the goods. The Authority notes that Raw materials constitute a very major portion (82%) of the cost of sales as per the information submitted by the Company. Therefore, cost of production of the subject goods produced by this producer/exporter is not reliable and cannot be accepted.

73. In view of the above the normal value for China is required to be determined as per the procedure described in Para 7 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules. Para 7 of Annexure I read as follows:

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Account shall also be taken within time limits, where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

74. As per the above provisions normal value in China is required to be determined based on domestic selling prices in a market economy third country, or the constructed value in a market economy third country, or the export prices from such a third country to any other country, including India. However, if the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted to include reasonable profit margin.

75. In the absence of any reliable price and cost details for the subject goods in any market economy third country the Designated Authority has constructed the normal value in China on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin. Accordingly, the Normal Values for the subject goods exported by all exporters in China has been determined as US\$*** /MT.

Export Price: M/s. Ansteel LISCO, China through M/s Century Steel Pte Singapore

76. LISCO has reported export of **** MT of the subject goods to India during the POI. The goods have been exported to India through 4 unaffiliated exporters in Hong Kong, Taiwan and Singapore. Out of the total quantity exported during the POI, **** MTs have been exported through M/s Century Steel Pte Ltd., Singapore, who has filed a separate questionnaire response. None of the other exporters of the remaining quantity exported by LISCO to India during the POI has filed any questionnaire response. Therefore, the Authority notes that total value chain of the exports of goods to India is not complete with respect to the goods exported by this producer and it would not be possible to determine the export price of this exporter without completion of the entire value chain. Accordingly, the Authority holds

that individual treatment cannot be granted to LISCO for determination of a separate dumping margin for the goods exported by it during the POI.

77. No other producer/exporter from China has filed any questionnaire response. As per the import data imports from China during the POI was 30,589 MT at an average CIF price of Rs. 138236/- (US \$2527.62/-) per MT. The CIF Price has been adjusted for all ex-works expenses such as inland and ocean freight and insurance, bank charges and credit costs etc. and VAT differential of 4% on the basis of facts available taking into account the information available from the cooperative exporter's data. Accordingly, net ex-works export price for all exporters in China works out to US \$**** per MT.

Dumping Margin: China

78. The ex-works normal values and export prices, so determined at ex-works level, have been compared to determine the dumping margin for all exporters from China as follows:

CIF	Adjustments	EP	CNV	DM	DM %
US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	
2527.62	****	****	****	****	10-20%

G. 3 Korea RP

79. None of the exporters from Korea RP has filed any questionnaire response. As per the import data available with the Authority 3813 MTs of the subject goods have been imported from Korea RP during the POI. POSCO, one of the major manufacturers in Korea, in its limited submission before the Authority has argued that its products are significantly different and therefore, should be excluded from the investigation. However, these arguments have been found to be unsubstantiated.

80. Neither POSCO nor any other producer or exporter from Korea has provided any information of their normal values or export prices. Therefore, the Authority has determined the normal value and export price for all exporters from Korea on the basis of facts available as follows:

Normal Value in Korea RP

81. In the absence of any cooperation from any producer/exporter in Korea RP and any other credible information which could provide the basis for determination of normal value in Korea RP based on actual cost and prices in the domestic market of the exporting country, or exports to third countries, the Authority has constructed the Normal Value in Korea RP. For the purpose of construction of Normal Value in Korea RP the international price of major raw materials, to the extent they were available and most efficient conversion cost of the domestic industry has been considered. A reasonable margin of profit has been added to arrive at the weighted average constructed normal value of the subject goods in Korea RP at ex-works level. Accordingly, weighted average ex-works Normal value for the product under consideration in Korea RP has been determined as US\$ ****/MT.

Export Price: Korea RP

82. Export Price for all exporters in Korea RP has been determined on the basis of import prices reflected in transaction wise data for the POI from IBIS. Average CIF price reflected in the import data has been adjusted for inland and ocean freights and insurance, handling and other selling expenses based on facts available to arrive at ex-works export price. Accordingly, ex-works weighted average export price for all exporters in Korea RP has been determined as US\$****/MT.

Dumping Margin: Korea RP

83. For the purpose of determination of dumping margin the weighted average ex-works normal value and weighted average net ex-works export prices so determined have been compared at the same level of trade and dumping margin has been determined for all exporters from Korea RP as follows:

CIF	Adjustments	EP	CNV	DM	DM %
US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	
2,656.73	****	****	****	****	5-15 %

84. The Authority notes that the dumping margins so determined for the subject countries are above de minimis and significant.

H. Determination of Injury and Causal Links

85. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure –II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

86. The Authority notes that the application for imposition of antidumping duty has been filed by M/s Jindal Stainless Limited, who commands a major proportion of total production of the subject goods in India. In terms of Rule 2(b) of the Rules the petitioner has been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation. Therefore, for the purpose of this determination the cost and injury information of the petitioner, constituting the domestic industry as defined in Rule 2(b), has been examined.

H.1 Views of Exporter, importers and other Interested Parties regarding the injury claims of domestic industry

87. The Authority notes that though the Korean exporters have not filed the Response to the Exporters’ Questionnaire, they have filed certain injury submissions before the Authority. Other interested parties have also made substantial submissions with regard to the injury and causal link claims of the domestic industry. The submissions of exporters, importers and other interested parties to this investigation, in respect of the injury and causal link claims of the domestic industry, have been summarized as follows:

- That the Korean exporters have not exported the PUC to India at dumped prices, as alleged, or at all and they are only filing the Submissions on Injury as they convincingly believe that no injury, leave alone material injury, is being caused to the Petitioner;
- That the Petitioner is habitual in approaching the Government of India and seeking protection claiming injury, as and when it expands its production capacity, be it for cold rolled or for hot rolled stainless steel products. This is evident from the various investigations, including the instant Investigation, where the Petitioner has filed petitions in blatant abuse of the Trade Remedy measures to its advantage by filing incorrect data;
- That the petitioner has given false and misleading information regarding its capacity expansion and capacity utilization in past investigations. In the present investigation also the petitioner has shown that it has enhanced its capacity but the petitioner is silent on the issue whether its commercial production has stabilized or not. The petitioner may be asked to provide complete break-up of how installed capacity for the PUC has been worked out in a situation when there is no dedicated plant capacity for the same;
- That the petitioner has exaggerated the increased imports of STS HR 304 and deliberately invented material injury, which is not only factually incorrect but non-existent. On the contrary, the Petitioner has enhanced the capacity by almost 100% in the last one year and is struggling to make the same fully operational due to ramp up problems;
- That the Authority should properly consider reasons for the decline in capacity utilization of the Petitioner and also losses on account of other factors and it will find a causal link between other factors and injury;
- That the petitioner’s Hisar plant, which is fully established, is operating at 90% utilization whereas the Odisha plant which started production in 2011 is operating at 15% capacity utilization. The lower capacity utilization at Odisha Plant is due to the fact that Stainless steel production facility at Odisha plant is under ramp up and was yet to stabilize. The alleged losses to the Petitioner are attributable to its unstabilised production and not to the purported increase in imports as admitted by them in its various unaudited reports and press releases.
- That there has been no increase of total import from the base year in relative terms to demand, including captive consumption. Also, under the condition of a steady high increase in demand, comparison of total imports between the preceding year and the POI in both absolute terms and relative terms should be considered, which comprehensively indicates a decrease in total imports.
- That the increased quantity of 540MT originating in Korea is too minimal to negatively affect the total Indian STS HR 304 market with demand size of 168,510MT measured during the POI;
- That while the total demand has increased by 24,331 MT, the volume of STS HR 304 imported from Korea has increased only by 540MT, which increase cannot be termed as significant.

- That considering the total imports of 3,052MT from Korea and the total demand of 168,510MT in the Indian market during the POI, it is doubtful how 1.8% volume of the total demand could possibly affect the whole Indian market so badly such as to cause 'material injury'.
- That the Investigation should seriously deliberate on nature of increased market share of imported goods from Subject Countries, re-distribution of market share among STS HR 304 imports led by imposition of dumping duty on all imports exported from European Union, South Africa, Taiwan and USA. For this reason, the Authority should not treat the increase in market share of imports from the Subject Countries as either a cause or a sign of injury to domestic industry;
- That as a benefit emanating from CEPA, the Korean exporters are eligible to have preferential duty rate on the products exported to India and vice versa, if their product qualifies to its rules of origin. In this regard, many Korean and Indian producers benefited from CEPA, including POSCO. In other words, POSCO has attained the benefits concerning reduction in customs duty rate and increased its imports volume by 540MT since the effective year 2010;
- That the increased volume in imported STS HR 304 from Korea should be understood as a positive effect of the CEPA and not a cause to injury to Indian domestic industry;
- That the Authority should consider the significant drop of Nickel price, during the period of injury investigation, almost to a half of the early 2011, as a critical factor to lead to a fall of selling price of domestic industry and landed price of imports;
- That the imported STS HR 304 from Korea has not had a serious influence on price undercutting in Indian domestic industry. Further, neither price suppression nor depression resulting from the import of STS HR 304 from Korea is evident;
- That even the sales and production of the Petitioner have been increasing. Consequently, the argument of the Petitioner that domestic industry has suffered in terms of sales and production should be denied for analysis of injury in the Investigation;
- That the Investigation should carefully analyze the core reasons for material injury to domestic industry. Concerning the decline of capacity utilization, the imports from Korea could not be a cause. Rather, mistake in market forecasting to make managerial decision on establishing new production mill is the primary factor for the Petitioner's declining capacity utilization;
- That the estimation of 17.30% loss of market share due to dumping presented by the Petitioner is miscalculated upon wrong condition. The Petition assumes the automatic transfer of absent market share from anti-dumping duty attracting countries without consideration of other factors, which more directly and largely affects customer's purchase decision and subsequently market share;
- That has admitted by the Petitioner in its various financial statements, one of the causes for its increased cost of production is the depreciation of India Rupee to US Dollar;
- That another possible cause for the rise in cost of production is an increase in labour cost. Other possible causes are items of manufacturing overheads such as depreciation and amortisation expenses, and power and fuel.
- That POSCO has not increased its STS HR 304 production capacity during the POI. Although there was an increase of production capacity in POSCO's family corporation, Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd. (hereinafter "ZPSS") in China, the ZPSS has not been exporting its STS HR 304 products to India during the period of injury investigation. Thus, there is no possibility of threats of injury as a result of imports from Korea;
- That the Petitioner has failed to present prima facie evidence of causal link in the Petition, in the absence of which the only factors that have caused injury are self inflicted attributable to their mismanagement and are of no relevance to imports from Korea.
- That imposition of anti-dumping duty on imports of STS HR 304 will have a detrimental effect on the STS HR consuming industry leaving it with the situation of purchasing the raw material with higher price than the rest of world. Due to higher purchase price, the total manufacturing cost of the STS HR 304 consuming entities in India will inevitably go up.
- That Jindal have Hot Rolling Machine at Hisar with capacity of 750,000 Tonnes Per Annum in which they are making 1000mm and 1250mm width of coils, whereas as in countries like China, factories are making mostly narrow width coils from 400mm to 700mm with a an estimated capacity of about 10,00,000 tonnes per annum rendering effective cost advantages. Under such circumstances cost of production of Jindal cannot be compared with that of Chinese producers;
- That Jindal should be considered as an inefficient producer and injury, if any, is on account of their inefficiency and product mix and not because of any dumping from subject countries;

- That the application on record do not demonstrate any material injury to the domestic industry on account of any alleged dumping from subject countries thus the present investigation is liable to be terminated without any measures;
- Return to be adopted must be reasonable and not hypothetical. Calculation of return by adopting 22% uniformly on both the components of capital employed is totally incorrect;
- That the volume of imports from subject countries has significantly declined during POI as compared to 2010-11 & 2011-12. However, during the same period the volume of sales of domestic industry in domestic market has significantly increased. This clearly shows that there is no adverse effect on the sales volume of the domestic industry in the domestic market because of imports from subject countries;
- That in a situation where imports from subject countries have declined and sales of the petitioner increased in the same period defuse the entire claim of injury by the petitioner. Such inverse relation between imports and sales by the petitioner alone should be construed as sufficient to terminate the present investigations forthwith;
- That the domestic industry has resorted to huge capacity expansions in 2011-12 and during the POI. It is obvious that such robust capacity expansion could not be commercialized immediately. Further, it also shows that the capacity expansion have been made without adequate consideration excess capacity available with the petitioner and also the market situation. Therefore, it is submitted that this exploding capacity addition is one of the principal causes of injury to the domestic industry.
- That the capacity utilization of the domestic industry has shown declining trend during the POI. However, production shows significant increasing trends. Evidently, the reason for adverse performance in respect of capacity utilization is increase in its plant capacity and nothing else;
- That the sales volume of the domestic industry in domestic market during base year was 46,356 MT which went up to 63,916 MT during the POI. Further, volume of export market of the domestic industry also has significantly increased during the POI. Therefore, there is no injury to the domestic industry due to alleged dumped imports;
- Not disclosing actual level of inventory is suspicious. The sales figures of the Applicant indicate that it is able to sell almost 100% of its production during the period of injury up to the POI. Therefore, claim of rising inventories does not reconcile with rising sales figures
- That the cost of production of petitioner is high in POI because of high wages cost, interest cost, high capacity and investment, low utilization resulting into higher cost and financial losses, as evident in the injury information filed by the domestic industry;
- That if the cost of petitioner is high as compared to exporters, any cognizance of such higher cost of production caused by inefficiencies would tantamount to passing of burden on importers by way of anti-dumping duty mechanism which in turn seriously affect the interest of user industry which is labour intensive. Hence, levy of AD Duty would increase the price of raw materials for many user industries which would result in higher cost of end product to the customer.
- AD Rules requires DGAD to consider the best capacity utilization over the past three years and POI, while arriving at the NIP. Thus, DGAD should take the best capacity utilization during the injury period, that is, 92% and not 59% capacity utilization during the period of investigation, for the purposes of determining NIP.
- The Applicant is actually suffering losses due to its low priced exports rather than imports from subject countries

H.2 Views of the domestic industry

88. The domestic industry, in its submissions, has argued as under:

- That the allegations of the interested parties that the petitioner is a habitual protection seeker are baseless and it suggests that the duties so far have been imposed merely on the basis of application filed by the petitioner, without verifying the facts and without establishing that dumping of the product under consideration has caused injury. Only after detailed analysis of dumping, injury and causal link between dumping and injury is established duties are recommended by the Authority.
- That the Imports of the product under consideration have increased significantly and are undercutting and suppressing the prices of the domestic industry leading to significant losses. Performance of the Domestic Industry has steeply deteriorated in terms of profits, return on investments, cash flow, and has reached negative levels. The domestic industry has suffered significant financial losses, cash losses and suffered negative return on investment. Thus the petitioner is suffering material injury.
- That POSCO has not filed exporter questionnaire response and the claim of no dumping cannot be accepted without verifying data of the company and the argument is liable to be rejected.

- That initiation of safeguard investigation and recommendations of interim duties led to some partial correction in imports coupled with the fact of enhancement of capacities led to some reduction in imports. However, imports have further increased, as soon as safeguard duty was over. Further, if imports of the product under consideration over the entire injury period are considered, it would be seen that the imports have increased in absolute terms.
- That de minimis rule of imports pertains to percentage of imports from respective countries in relation to total imports. The law itself recognizes any country with more than 3% of share in total imports as having the potential to injure the domestic industry. Imports in relation to demand are immaterial to automatically drop a country from investigation. As explained in the petition, significant dumping and injury margin exists from imports of subject goods from Korea. The prices of imports from Korea are much below the level of costs of the domestic industry.
- That the Annual Report of 2012-13 of the petitioner clearly mentions that the ramp up of the Finishing Facility of its Odisha plant is in progress. It is a common knowledge in the stainless steel industries, that finishing is the process which follows cold rolling and it has got nothing to do with Hot Rolling and Annealing and pickling;
- That Petitioner has expanded capacity considering the growth in demand and expecting a fair opportunity in the domestic market to produce and sell goods given the fact of imposition of anti dumping duty on imports from other countries. Capacity is sufficient with the petitioner, thus, imports are in fact not necessary into the Indian market. However, the petitioner has not been able to utilize its capacities in view of dumped increased imports;
- That the decline in selling price in the POI as compared to the previous year is much more than the decline in cost of production of the domestic industry;
- That China was earlier a net importer of Stainless Steel product and has now become a net exporter. China was a significant market for Korean exporters. However, now China has turned into net biggest exporter of Stainless Steel and therefore, the market for Korea has gone. Accordingly these Korean exports are now diverted to India and elsewhere. This fact, coupled with excess capacity in Korea, clearly indicates threat of injury on account of dumping;
- That the Authority is required to determine injury to the domestic industry cumulatively from all dumped sources. Thus, individual examination of price undercutting, suppression or depression as claimed by the exporters is inappropriate, and could even be misleading.
- That the injury margin in case of Korea is also significantly positive. Thus, in any case, it would not be appropriate to selectively impose duty on dumped imports from China and Malaysia and exempt dumped and injurious imports from Korea. In fact, any such approach would be contrary to the legal provisions concerning imposition of anti dumping duty on non-discriminatory basis. Volume of imports from Korea is not negligible. The same is significant and beyond the legal limits;
- That while arguing that the imposition of antidumping duty shall not be in public interest, none of the interested parties has provided any quantified claim in this regard;
- That there are significant contradictions in the arguments of Korean exporters. On the one hand it has been argued that the exports from Korea were negligible and at the same time it has been argued that imports from Korea have increased due to the benefits of CEPA and preferential customs duty.
- That grant of concession under CPEA cannot become a certificate for dumping. Contrary to the argument of the exporter, with the preferential customs duty, the exporter should have in fact sold the product at prices above normal value. Exporter should not have exported at dumped prices.
- That the issue of devaluation of exchange rate and the impact of the same on domestic industry is well addressed and has been considered entirely irrelevant. The depreciation of Indian rupee on facts should have actually mitigated injury and should not have amplified the same. If US Dollar has improved, the rupee price has increased and the injury margin should have declined. However, on facts, the loss suffered by the domestic industry has increased.
- That while the material cost might be impacted by exchange rate, the same also equally impacts the price of the product. Thus, in any case, there is no selective impact of exchange rate either on raw material or on finished product.
- That the requirements of narrower coils can easily be met by slitting wider coils at an extremely nominal cost and the petitioner has extensive facilities for the same. Petitioner has also supplied narrower widths. Further, it is a known fact that a wider mill can produce a far higher output per unit time thereby resulting in lower fixed cost per MT besides other operating efficiencies. It makes a lot more sense to produce a wider coil and then slit the same than producing a coil in narrow width. This is the standard route followed by most mills worldwide.
- That the argument that production cost of domestic industry is ten times higher than the production cost of the subject countries is totally baseless.

- That the data would show that return on investment of Hissar plant was reasonable. As far as return on investment of Orissa plant is concerned, the same was initially impacted because of new operations; while the same was subsequently impacted by dumping in India. Thus, if the return on investment earned by the Authority may consider return on investment of the domestic industry in 2006-07 this represents return before dumping of the product in the country. Return on investment earned by the domestic industry during the period when the domestic industry was suffering because of dumping in any case would be inappropriate.
- That the increase in production and sales of the domestic industry is a result of enhancement of capacities. However, despite commencement of production at new production facilities and imposition of anti dumping duty earlier, petitioner was unable to increase its sales to the extent of additional market that the petitioner was expecting as a result of imposition of anti dumping duty.
- That the normated cost of Odisha also shows injury and the performance of Hissar plant on standalone basis has also deteriorated. This clearly establishes that the claimed deterioration in performance of the domestic industry is not because of commercialization of production at Odisha plant.
- That expansion of capacity has led to increase in sales and production. Further petitioner has increased its sales at the cost of prices. This has led to increase in sales. With imposition of anti dumping duty on other sources, the petitioner had expected to gain the market earlier occupied by the countries earlier resorting to dumping. However, market vacated by one set of dumped sources, with imposition of anti dumping duty, has been largely occupied by other set of dumped sources. This is a clear situation of dumping shifting from one source to other source and domestic industry continuing to suffer injury.
- That increase in wages cannot be seen in isolation. Expansion of capacity has led to increase in wages. It would be seen that increase in wage is far lower than the decline in profits.
- That the causal link is established by followings:
 - (i) There is significant difference between the prices offered by the Domestic Industry and Foreign Producers. Thus, inability of the domestic industry to raise the prices whenever costs are rising is a result of dumping of the product in the Country.
 - (ii) Even when the domestic industry has been offering sub-optimal prices and lowering its prices, it is losing sales opportunity. Thus, present sales volumes of the domestic industry are a direct consequence of dumped imports from the subject countries.
 - (iii) Price undercutting resulted in sub-optimal prices. As a direct consequence, the profits of the Domestic Industry declined to negative levels.
 - (iv) Reduction in profits directly resulted in deterioration in return on capital employed and cash flow. Thus, deterioration in profits, return on capital employed and cash flow is directly due to dumped imports.
 - (v) Price undercutting has led to deterioration in performance of the domestic industry in respect of profits, return on investment and cash flows.
- That the injury suffered by the DI cannot be attributed to manufacturing overheads like depreciation and amortisation expenses and power and fuel. This can be clearly established by separate examination of the two plants. Performance of Hissar plant clearly establishes that the deterioration in performance is because of dumping and not because of increase in manufacturing overhead because of commercialization of production in the new plant.

H.3 Examination of the issues by the Authority

89. The Authority notes the arguments of the other interested parties and various issues raised therein with regard to the claims of injury and causal link and the counter arguments domestic industry on the issues raised by the interested parties. While the issues pertaining to the examination of various injury and causal link parameters have been examined in the relevant paragraphs in this finding hereunder, some of the general issues raised have been addressed here as follows:

90. As regards the protection seeking behavior of the petitioner raised by the interested parties is concerned the Authority notes that as long as there is existence of unfair trade practice by the exporters from different countries at different points of time and the domestic industry suffers because of such dumped imports, the domestic industry has the right to seek remedial measure within the framework of the WTO Agreements and domestic laws. Such remedial measures are put in place after a detailed and objective evaluation of various information placed before the concerned

authorities. In the instant case also the Authority has examined the various claims and counter claims objectively within the framework of the Rules. Therefore, the arguments of the interested parties in this respect are not tenable.

91. As regards the argument that imports from certain countries are too low to have any significant impact on the domestic industry is concerned, the Authority notes that the volume of imports from all the subject countries are above de minimis levels specified in the Rules and the Agreement and the margin of dumping from each such country is also significant. Therefore, a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic product. Accordingly, the injury to the domestic industry has been assessed cumulatively and therefore, the arguments of the Korean exporters in this regard are not accepted.

92. As regards the performance of the domestic industry in terms of capacity addition and capacity utilization, stabilization of the new plant and its impact on its cost and prices, and other economic parameters are concerned, the Authority notes that these issues have been addressed to the extent they are found relevant and supported by substantial evidence under relevant headings hereunder.

H.4 Examination of Injury and Casual Link:

Gnbn m

Cumulative Assessment of Injury

94. Annexure II (iii) of the Anti Dumping Rules provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -

- a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country/ territory is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and;
- b) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

95. In the present case, the margins of dumping from each of the subject countries have been found to be more than the de minimis limits prescribed; the volume of dumped imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed; and the exports from the subject countries directly compete with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market. Therefore, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of imports.

96. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments have been considered in accordance with Annexure II of the Rules . All economic parameters affecting the Domestic Industry as indicated above have been examined as under: -

(A) Volume Effects of Dumped Imports: Import volumes and market shares

(a) Import volumes and share of subject countries:

97. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The Authority has examined the volume of imports of the subject goods from the subject countries and other countries based on the transaction-wise import data provided by DGCI&S and IBIS data submitted by the domestic industry. While the DGCI&S data for the period from 2009-10 to 2011-12 shows marginally higher import volumes compared to IBIS data, it showed significantly lower import volumes in the POI. Therefore, the data from DG, Systems for the POI was also called for corroboration. The DG Systems data shows a higher volume compared to DGCI&S and closer to IBIS. Therefore, the IBIS data, being more consistent, has been adopted for the injury analysis. The import volumes of the subject goods and share of the dumped imports during the injury investigation period as per IBIS data are as follows:

Sn	Particulars	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI	POI Annualised
1	Imports Volume						
(i)	Subject Countries	MT	8,490	31,797	38,744	35,985	28,788
	Trend		100	375	456	424	339
a	China	MT	5,117	26,293	34,905	30,589	24,471
b	Malaysia	MT	860	1,300	1,345	1,584	1,267
c	Korea RP	MT	2,512	4,204	2,494	3,813	3,050
(ii)	ADD Attracting countries	MT	22,779	10,012	6,585	6,309	5,047
	Trend		100	44	29	28	22
(iii)	Other Countries	MT	1,065	1,182	2,551	1,832	1,466
	Total	MT	32,334	42,991	47,881	44,126	35,301
	Trend		100	133	148	136	109
2	Share in Import						
(i)	Subject Countries	%	26.26	73.96	80.92	81.55	81.55
	Trend		100	282	308	311	311
a	China	%	15.83	61.16	72.90	69.32	69.32
b	Malaysia	%	2.66	3.02	2.81	3.59	3.59
c	Korea RP	%	7.77	9.78	5.21	8.64	8.64
(ii)	ADD Attracting countries	%	70.45	23.29	13.75	14.30	14.30
	Trend		100	33	20	20	20
(iii)	Other Countries	%	3.29	2.75	5.33	4.15	4.15
	Trend		100	83	162	126	126
	Total	%	100	100	100	100	100

98. The data indicates that total imports substantially increased by about 50% till 2011-12 compared to the base year of 2009-10. However, the imports from the subject countries increased by about 350% during the same period. But the total imports as well as imports from the subject countries declined marginally during POI. The Authority notes that China specific Safeguard duty was imposed on 4th January 2013 due to surge in imports from that country and the duty was in force on this product for a substantial part of the POI, i.e. till 22nd July 2013. This safeguard duty seems to have arrested the surge in imports during the POI leading to decline in imports during this period.

99. The imports from China alone constituted around 70% of the total imports during the POI and the previous year. The quarterly import data for the POI given below indicates that while there were substantial imports from China during the first two quarters of the POI, the imports started tapered off beginning the third quarter and volumes dropped substantially in last two quarters when the China specific safeguard duty was in force.

Particulars	Volume in MT				
	POI Q1	POI Q2	POI Q3	POI Q4	POI Q5
Subject Countries	11,980	10,942	7,829	3,674	1,560
China	11,066	9,134	6,936	2,232	1,221

100. Since the import data of the POI is partly affected by the Safeguard duty the Authority has also looked at the post safeguard duty scenario to examine the trend in imports after the duties ceased to exist after July 2013. The DGCI&S import data of 5 quarters after the POI has been examined to analyse the trend of imports after cessation of safeguard duty. The trend in imports is as follows:

Sn	Particulars	UOM	POI April'12-June'13	POI Annualised	Post POI July'13-Sept'14	Post POI Annualised
1	Imports Volume					
(i)	Subject Countries	MT	35,985	28,788	46,518	37,215
a	China	MT	30,589	24,471	43,895	35,116
b	Malaysia	MT	1,584	1,267	1,183	946
c	Korea RP	MT	3,813	3,050	1,440	1,152
(ii)	ADD Attracting countries	MT	6,309	5,047	11,400	9,120
(iii)	Other Countries	MT	1,832	1,466	1,920	1,536
	Total	MT	44,126	35,301	59,839	47,871

101. The above data indicates that there has been significant increase in the imports after the cessation of safeguard duties. Annualized increase in imports from the subject countries is about 29 basis points higher as compared to the POI.

b) **Actual and potential effect on production and capacity utilization:**

102. The volume of domestic production and actual and potential effects of dumped imports on the domestic operation of the domestic industry have been examined in terms of total production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry.

103. The domestic industry's installed melting capacity is combined for both hot rolled and cold rolled products and stands at 16.00 lacs MT which includes both Hissar and Odisha plants. After hot rolling, a part of the product is transferred captively for cold rolling. Therefore, overall melting capacity of the petitioner is not dedicated and therefore, not relevant for this injury investigation. However, for the purpose of examining the performance of the domestic industry with respect to the product under consideration the capacity has been derived in terms of its melting capacity apportioned to the product under consideration on the basis of number of heats used for the product under consideration.

104. The Authority also notes the arguments of the interested parties that the petitioner Company added the Odisha unit in 2011-12 and was in ramp up process during the POI. Therefore, the capacity utilization and other parameters during the POI would not be actual reflection of the injury suffered by the petitioner. Keeping this in view for the purpose of examination of the capacity and capacity utilization only that portion of the capacity of Odisha unit that was available for production during the ramp up operation as per the project report of the Company has been considered. Accordingly, the capacity, production and sales of the petitioner domestic industry during the injury investigation period have been examined as follows:

Particulars	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI	POI Annualized
Capacity of DI (PUC)	MT	1,08,869	1,16,654	2,11,359	4,75,014	3,80,011
Indexed		100	107	194	436	349
Production of DI	MT	1,00,265	98,448	1,29,900	3,00,577	2,40,462
Indexed		100	98	130	300	240
Capacity Utilization of DI	%	92%	84%	61%	63%	63%
Indexed		100	92	67	69	69
Domestic Sales of DI	MT	46,356	37,655	43,121	79,895	63,916
Indexed		100	81	93	172	138
Captive Consumption of DI	MT	56,713	53,846	60,555	1,69,362	1,35,489
Indexed		100	95	107	299	239
Sales of other domestic producers	MT	8,777	5,645	5,450	4,125	3,300
Total Demand excluding captive	MT	87,467	86,291	96,452	1,28,146	1,02,517
Indexed		100	99	110	147	117
Total Demand including captive	MT	1,44,179	1,40,137	1,57,006	2,97,508	2,38,006
Indexed		100	97	109	206	165

105. The new plant in Odisha was added in 2011-12 and started production that year with addition of about 1 lakh tone capacity. The capacity has been further ramped up in the POI taking the total capacity to about 250% compared to the base year. However, the production has increased only by about 140% during the same period. Therefore, the capacity utilization has declined to 63% from 92% in the base year when only Hissar plant was in operation. Since a major capacity addition has taken place during the injury period and not fully ramped up capacity and capacity utilization are not relevant as significant injury parameters in this case.

106. As far as the demand is concerned, there is a healthy growth of commercial demand as well as captive demand for cold rolling. During the POI (on annualized basis) the domestic sales of the DI has increased by about 38% compared to the base year. However, this increase is apparently because of the protection available under China specific safeguard duty in force during a major part of the POI as well as production augmentation from the new unit in Odisha. However, when analysed with reference to the capacity available and ability of the industry to produce and supply, the domestic sales appears to be low compared to its potential.

c) Actual and potential effect on market share:

107. Effects of the dumped imports on the domestic sales and market shares have been examined as follows:

Market Share in domestic demand-(Without Captive consumption)					
Particulars	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Subject countries	%	9.71	36.85	40.17	28.08
Indexed		100.00	379.64	413.85	289.32
Countries attracting ADD	%	26.04	11.60	6.83	4.92
Indexed		100.00	44.55	26.22	18.90
Other Countries	%	1.22	1.37	2.65	1.43
Indexed		100.00	112.50	217.34	117.45
Domestic Industry	%	53.00	43.64	44.71	62.35
Indexed		100.00	82.34	84.36	117.64
Other Indian Producers	%	10.03	6.54	5.65	3.22
Indexed		100.00	65.20	56.31	32.08
* POI: April '12 – Jun '13					

108. The data indicates that while the demand of the subject goods in the domestic market has increased by about 17% in the POI compared to the base year, the market share of the dumped imports from the subject countries in domestic demand has increased from about 10% in the base year to about 28% in the POI in spite of the fact that China specific safeguard duty was in force for a part period of the POI. The market share of the countries attracting antidumping duty dropped from 26% in the base year to about 5% in the POI. The share of the domestic industry in the total demand declined by about 8% upto 2011-12 and thereafter improved by about 9% over the base year apparently as an impact of the safeguard duty and antidumping duty on the subject goods from certain countries. The other Indian producers have lost significant market share in the injury period. It therefore, appears that the market share vacated by the countries attracting duty has been cornered by the dumped imports from the subject countries and this has prevented the domestic industry to improve its sales volume in the domestic market to the extent they have capacities to produce and sell.

109. The trends of imports have also been examined in relative terms with reference to consumption and production as is shown in the table below:

Particulars	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI	POI Annualized
Imports- Subject countries	MT	8,490	31,797	38,744	35,985	28,788
Imports in relation to consumption	MT	10%	37%	40%	28%	28%
Imports in relation to production	MT	8%	31%	29%	12%	12%

110. The above data indicates that imports from subject countries as a percentage of consumption and production have increased from 10% to 28% and 8 % to 12% respectively from the base year to POI indicating that dumped imports from the subject countries have shown significant increase in relation to production and consumption in India.

B) Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

111. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

i) Trend of import prices

112. Weighted average CIF import price of the subject goods from the subject countries has been analysed based on the IBIS import data as under:

	CIF Imports Prices	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
(i)	Subject Countries	Rs/MT	1,08,002	1,40,100	1,46,866	1,38,946
	Trend		100	130	136	129
a	China	Rs/MT	1,11,881	1,40,190	1,45,905	1,38,236
	Trend		100	125	130	124
b	Malaysia	Rs/MT	1,03,709	1,39,247	1,55,128	1,37,384
	Trend		100	134	150	132
c	Korea RP	Rs/MT	1,01,568	1,39,798	1,55,870	1,45,297
	Trend		100	138	153	143
(ii)	ADD Attracting countries	Rs/MT	98,425	1,35,673	1,48,418	1,66,418
	Trend		100	138	151	169
(iii)	Other Countries	Rs/MT	97,055	1,15,718	1,43,539	1,27,042
	Trend		100	119	148	131
	Total	Rs/MT	1,00,895	1,38,399	1,46,902	1,42,380
	Trend		100	137	146	141

113. The above data indicates that the CIF import price of the subject goods from the subject countries as well as countries attracting duty increased by about 30% to 53% upto 2011-12 and thereafter there has been a significant decline in the prices from the subject countries in the POI whereas the price from the countries attracting duty increased by about 18 basis points during the POI compared to the previous year. The decline in weighted average CIF price during the POI is in spite of the China Specific Safeguard duty being in force.

ii) Price undercutting effects

114. In determining the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been rebated. Since the dumped imports from the subject countries are simultaneously injuring the domestic industry the cumulated price undercutting effect of dumped imports from all sources have been examined as follows:

Total Subject Countries	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Weighted average Landed price of imports	Rs./MT	1,14,699	1,48,788	1,55,974	1,47,517
Indexed		100	130	136	129
Net Selling Price	Rs./MT	****	****	****	****
Indexed		100	127	130	122

Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****
Indexed		100	83	15	9
Price Undercutting (%)	%	****	****	****	****
Range		5-10	0-5	0-5	0-5

115. The above data indicates that the landed prices of the dumped imports have increased over the injury investigation period till 2011-12 and then declined. However, the landed prices have been significantly below the selling prices of the domestic industry throughout the injury investigation period. Weighted average price undercutting has been significant both in absolute and in percentage term. The Authority notes that the price undercutting during 2011-12 and POI has significantly declined compared to the base year apparently because the domestic industry was responding to the dumped prices with lower selling prices in the domestic market to retain its market. Therefore, the price undercutting needs to be seen along with the price suppression effects of the dumped imports.

116. The interested parties have argued that price undercutting of certain countries are negative and therefore, do not cause injury to the domestic industry. Therefore, the Authority has also looked at the price undercutting of the dumped imports from each of the subject countries separately as follows:

China					
Particulars	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Landed price of imports	Rs./MT	1,18,820	1,48,884	1,54,953	1,46,808
Indexed		100	125	130	124
Net Selling Price	Rs./MT	****	****	****	****
Indexed		100	127	130	122
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****
Indexed		100	241	94	60
Price Undercutting (%)	%	****	****	****	****
Range		0-5	0-5	0-5	0-5
Malaysia					
Particulars	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Landed price of imports	Rs./MT	1,10,141	1,47,882	1,64,748	1,45,904
Indexed		100	134	150	132
Net Selling Price	Rs./MT	****	****	****	****
Indexed		100	127	130	122
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	(****)	****
Indexed		100	57	-72	20
Price Undercutting (%)	%	****	****	(****)	****
Range		5-10	0-5	0-(-5)	0-5

Korea					POI	
Particulars	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	Total Imports	Imports with concessional duty
Landed price of imports	Rs./MT	1,07,867	1,48,467	1,65,537	1,53,874	1,47,962
Indexed		100	138	153	143	137
Net Selling Price	Rs./MT	****	****	****	****	****
Indexed		100	127	130	122	122
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	(****)	(****)	****
Indexed		100	42	(66)	(44)	1

Price Undercutting (%)	%	****	****	(****)	(****)	****
Range		10-15	0-5	0-(-5)	0-(-5)	0-5

117. The desegregated data as above indicates that the price undercutting of the imports from Korea is marginally negative during the previous year and the POI. It is also noted that with concessional duty under CEPA the dumped imports are marginally undercutting the prices of the domestic industry during the POI. However, the Authority notes that the price undercutting analysis may not provide a clear understanding of the price effect on the domestic industry unless the price suppression/depression effects are also examined in a situation where the domestic industry is forced to suppress its prices to increase its sales and market share because of the new capacity created.

iii) Price underselling effects

118. For the purpose of price underselling determination the weighted average landed prices of imports from subject countries have been compared with the Non-injurious selling price of the domestic industry determined for the POI.

Particulars	UOM	China	Malaysia	Korea RP	
				Total Imports	Imports with concessional duty
Non-Injurious Price	Rs/MT	****	****	****	****
Landed Price	Rs/MT	1,46,808	1,45,904	1,53,874	1,47,962
Price Underselling	Rs/MT	****	****	****	****
Price Underselling	%	****	****	****	****
Price Underselling (Range)		10-20	10-20	5-15	5-15

119. The above data shows that the imports from the subject countries are entering the Indian market at significantly below the non-injurious price of the domestic market indicating significant price underselling effect on the domestic prices.

iv) Price suppression and depression effects of the dumped imports:

120. To examine the price suppression effect of the dumped imports on the domestic prices the trend of net sale realization of the domestic industry has been compared with the cost of production of the domestic industry and the landed price of the dumped imports as follows:

Particulars	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of production	Rs./MT	****	****	****	****
Indexed		100	137	142	143
Selling Price	Rs./MT	****	****	****	****
Indexed		100	127	130	122
Landed price of imports Subject countries	Rs./MT	1,14,699	1,48,788	1,55,974	1,47,517
Trend		100	130	136	129

121. The data indicates that the cost of production of the domestic industry has increased significantly in 2010-11 due to increase in the factor costs, such as prices of major raw materials i.e., stainless steel scrap and nickel which is also corroborated by significant jump in import prices that year. Thereafter the increase in cost is moderate. However, the domestic selling price of the domestic industry has not increased in the same proportion as that of the costs of production of the domestic industry. In fact the selling prices declined significantly in the POI compared to the previous year while the cost marginally increased during the same period. The decline in the selling price of the domestic industry in the POI corroborates with the decline in landed prices of dumped imports from the subject countries. This indicates that the dumped imports are preventing the domestic industry to realize remunerative prices thereby significantly suppressing prices of the domestic industry.

H.5 Examination of other injury factors

122. After examining some of the injury factors i.e. actual and potential decline in sales and market share; actual and potential increase in volume of imports etc. in the previous section, the Authority has examined the other mandatory injury parameters as follows:

a) Profits/Loss and Return on investments

123. On the basis of the detailed examination of the cost of production and other associated costs as well as selling prices carried out by the Authority, profits earned by the domestic industry from the sales of the subject goods in the domestic market has been worked out as follows: -

Particulars	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI	POI Annualized
Cost of production	Rs./MT	****	****	****	****	****
Indexed		100	137	142	143	143
Selling price	Rs./MT	****	****	****	****	****
Indexed		100	127	130	122	122
Profit/loss	Rs./MT	****	(****)	(****)	(****)	(****)
Indexed		100	-141	-206	-437	-437
Cash Profit	Rs.Lacs	****	(****)	(****)	(****)	(****)
Indexed		100	-52	-103	-347	-347
PBIT	Rs.Lacs	****	(****)	(****)	(****)	(****)
Indexed		100	-62	-103	-248	-248
ROCE	%	****	(****)	(****)	(****)	(****)
Indexed		100	-69	-70	-113	-113

124. The above data shows that the cost of production increased significantly in 2010-11 by about 37% and thereafter has increased only marginally during the rest of the injury investigation period. The selling price also increased in 2010-11 by about 27% but was not enough to recover the full cost leading to losses. Even after imposition of Antidumping duty on EU, USA, South Africa and Taiwan in 2011-12 the losses have increased as the dumped imports from the subject countries have started entering the Indian market. The losses have increased in the POI due to significant fall in the selling prices because of drop in import prices from the subject countries. From positive profit margin per unit in the base year, profitability of the domestic industry has declined continuously over the injury investigation period and resulted in net loss on the domestic sales in the POI. The return on the domestic investments of the domestic industry has declined significantly during the POI as compared to the base year and during the POI the domestic industry had a significantly negative return from the subject goods.

125. The interested parties have argued that the loss to the company could be due to the ramp up operation of the Odisha plant, which is yet to stabilize with full production and therefore, the injury should be examined with respect to the Hissar Plant of the petitioner which was operating at over 90% capacity. The Authority notes that the injury is determined for the domestic industry as a whole. Therefore, a disaggregated analysis with respect to individual units is not required.

b) Employment and Wages

126. Number of employees and wages paid indicates that employment has increased because of the increase in capacity and production due to operationalisation of the new plant in Odisha.

Particulars	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI	POI Annualized
Cost of production	Rs./MT	****	****	****	****	****
Indexed		100	137	142	143	143
Selling price	Rs./MT	****	****	****	****	****
Indexed		100	127	130	122	122

Profit/loss	Rs./MT	****	(****)	(****)	(****)	(****)
Indexed		100	-141	-206	-437	-437
Cash Profit	Rs.Lacs	****	(****)	(****)	(****)	(****)
Indexed		100	-52	-103	-347	-347
PBIT	Rs.Lacs	****	(****)	(****)	(****)	(****)
Indexed		100	-62	-103	-248	-248
ROCE	%	****	(****)	(****)	(****)	(****)
Indexed		100	-69	-70	-113	-113

127. While the production and domestic sales of the product under consideration has increased by about 140% and 38% respectively in POI compared to the base year, the employment and wages have increased by about 50% and 80% respectively. Therefore, increase in employment and wages are in tandem with the production and sales.

c) Inventories

128. Inventory holding of the domestic industry in terms of average stock shows an increase of 170 basis points compared to the base year and 90 basis points compared to the previous year. The inventory as a percentage of sales also shows a significant increase of about 96 basis points compared to the base year and indicating inventory built up in the POI.

Particulars	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI	POI Annualised
Opening Stock	MT	****	****	****	****	****
Closing Stock	MT	****	****	****	****	****
Average Stock	MT	****	****	****	****	****
Indexed		100	53	180	270	270
Average stock as percentage of domestic sales	%	11	7	21	17	21
Trend		100	65	194	157	196

d) Cash Profit

129. Cash profits of the domestic industry over the injury period have been as under: -

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI-Annualized
Profit Before Tax	Rs Lacs	****	(****)	(****)	(****)
Indexed		100	(115)	(191)	(603)
Interest	Rs Lacs	****	****	****	****
Indexed		100	24	43	340
Depreciation	Rs Lacs	****	****	****	****
Indexed		100	99	108	265
PBDIT	Rs Lacs	****	(****)	(****)	(****)
Indexed		100	(30)	(60)	(141)
PBDIT	Rs/MT	****	(****)	(****)	(****)
Indexed		100	(37)	(65)	(103)
Cash Profit	Rs Lacs	****	(****)	(****)	(****)
Indexed		100	-52	-103	-347

130. The data above indicates that the interests and depreciation of the petitioner has increased significantly during the POI as the Odisha unit was capitalized in March 2012. Therefore, there is a significant increase in the cash loss in the POI. However, the trend of interests, depreciation and cash profits of the previous years' which were not affected by the capitalization of Odisha plant clearly shows significant cash loss in domestic operations largely due to low prices in the domestic market.

(e) Productivity

131. The productivity of the domestic industry has been examined with reference to production per day and per employee as follows:

Particulars	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Productivity per day	MT/days	132	108	123	183
Trend		100	81	93	138
Productivity per employee	MT/No.	251	249	189	231
Trend		100	99	75	92

132. The data shows that daily productivity of the domestic industry has improved. However, per employee productivity has declined compared to the base year while it shows improvement from the previous year. It is noted that Odisha plant has come into operation during the last two years of the injury investigation period and therefore, per employee productivity would not correctly reflect the performance of the industry as a whole.

(f) Growth

133. Performance of the domestic industry shows that capacity, production, and sales of the domestic industry show positive growth in view of commencement of production at new plant in Odisha since 2011-12 and the efforts made by the domestic industry to sell in the domestic market as well as export markets at the cost of financial losses. Parameters such as profit, cash flow, and return on investments shows negative growth.

Growth in %	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Production in MT		-1.81%	31.95%	85.11%
Capacity Utilization-PUC in %		-7.70%	-22.93%	1.82%
Domestic Sales in MT		-18.77	14.52	48.23
Profit Rs/MT		-241%	-46%	-113%
Cash Profit Rs Lacs		-152%	-100%	-236%
Return on Capital Employed in %		-17.77%	-0.03%	-4.54%

(g) Ability to raise fresh Investment

134. The Authority notes that there is a healthy growth in domestic demand for the subject goods and the domestic industry has made fresh capital investments for expansion during the investigation period apparently keeping in view healthy growth in demand for the product in the domestic market as well as export market.

(h) Magnitude of Dumping

135. The dumping margins of the dumped imports determined for the subject countries are above de minimis level.

(i) Factors affecting prices

136. Examination of trends in the volume of dumped imports and prices of the dumped imports from the subject countries, and the domestic prices indicate that the dumped imports through volume and price effects have affected the prices of the domestic industry through price suppression and depression effects in the domestic market.

H.6 Overall assessment

137. The above analysis of the factors indicate that the domestic industry has added capacity and increased production as well as sales compared to the base year and previous years. There has been an increase in the market share of the domestic industry during the POI as a result of the imposition of China specific safeguard duty during this period. However, in spite of improvement in certain physical parameters such as volume and production and sales, the domestic industry suffered injury on account of decline in net sales realization during the POI resulting in decline in profitability and return on investments as well as cash profits.

138. Volumes of dumped import from the subject countries increased significantly during the injury investigation period with a significant drop in the POI due to the China specific safeguard duty in place. However, the post POI import data indicates surge in imports after cessation of the China specific safeguard duty. Therefore, there is a clear indication that the trends in import volumes prior to the POI is likely to continue or intensify.

139. The prices of the dumped imports which increased upto 2011-12 show a significant drop in the POI suppressing the prices of the domestic industry in the domestic market. Price suppression during the injury investigation period has resulted in significant financial losses to the domestic industry. The injury suffered by the domestic industry is material and significant.

I. Causal link and other factors

140. Having examined the existence of material injury and volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting, price underselling and price suppression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti Dumping have been examined to see whether any other factor, other than the dumped imports, could have contributed to injury to the domestic industry. Accordingly, the following parameters have been examined:

(i) Volume and prices of imports from other sources

141. Import data examined shows that the subject goods are also being imported from other countries not under this investigation. The Authority notes that the anti dumping duties are currently in force against import of subject goods from European Union, South Africa, Taiwan and USA. The volume of imports from these countries as well as their share in imports has substantially declined after imposition of anti dumping duties. The volume of imports from the subject countries accounts for over 81% of total imports during the POI. Imports from other countries individually are insignificant and taken together accounts for about 4% of total imports. Therefore, the imports from other countries do not significantly affect the domestic industry.

(ii) Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

142. None of the interested parties have raised any argument regarding contraction in demand or any change in pattern of consumption leading to injury to the domestic industry. Examination of demand and pattern of consumption for the subject goods in the domestic market shows a growth of about 17% over the injury period and domestic demand with captive consumption shows an increase of about 65%. Therefore, possible contraction in demand cannot be attributed to the injury to the domestic industry.

(iii) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

143. The goods are freely importable and the import data shows that significant volume of subject goods are being imported to the country. There is no other major player in the Indian domestic market and therefore internal competition, apart from that is expected in a healthy market economy situation, could not have been a cause of injury to the domestic industry.

(iv) Development in technology: -

144. Production of hot rolled stainless steel plates and strips through electrical arc furnace route is an established method of production of stainless steel. The Authority notes that JSL has put up a new plant in Odisha with state of the art technology for the production of subject goods. Some of the interested parties have argued that certain specific manufacturing process adopted by them give them certain cost advantage. But these arguments/claims have not been substantiated with any evidence. Further, verification of production process of the participating producers in the subject countries does not demonstrate any substantial technological advantage to them or any new technological developments. Therefore, the Authority notes that development of technology could not be a cause of injury to the domestic industry.

(v) Export performance of the domestic industry: -

145. The interested parties have argued that the petitioner itself exports the Product under consideration at a price lower than that charged at Indian Domestic Market and that could be a cause of injury to the domestic industry. It is noted that the petitioner has provided separate information for their domestic and export performance. The export performance of the petitioner domestic industry has been examined as follows:

	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI	POI Annualized
Export Sale	MT	2,709	5,476	9,806	51,075	40,860
Trend		100	202	362	1,885	1,508
Export Price	Rs.MT	****	****	****	****	****
Trend		100	120	121	113	113

146. The Authority notes that the export sale of the domestic industry has increased, however the prices have declined in the POI. As noted in this finding elsewhere, the domestic industry has argued that they are not able to realize profits in export market due to global dumping by many countries including the countries under investigation in this case. In any case, for the purpose of injury analysis, only the domestic sales and parameters concerning the domestic

operations of the petitioner have been considered and injury, if any, caused due to the export performance of the domestic industry, has not been attributed to the dumped imports.

(vi) Productivity of the Domestic Industry

147. Productivity of the domestic industry has improved in terms of total output. Therefore, this cannot be attributed to the injury to the domestic industry.

J. Other factors and arguments of the interested parties

148. The interested parties have argued that the injury suffered by the domestic industry is due to its new plant in Odisha which is under ramp up operation and such injury should not be attributed to the dumped imports from the subject countries. This issue has been examined in detail and the Authority notes that even after normating the additional cost on account of lower capacity available during the ramp up operation of the Odisha plant, the petitioner is found to be suffering material injury. Stand alone analysis of Hissar plant's performance also indicates existence of material injury on account of significant price suppression. Therefore, the arguments of the interested parties that the injury is entirely due to Odisha plant are not found to be correct.

149. The interested parties have also argued that the production and sales of the domestic industry has increased significantly therefore, the petitioner does not suffer any material injury. The Authority notes that while the petitioner enhanced its capacity significantly in anticipation of higher demands leading to increase in production and sales, the industry is unable to recover full cost due to presence of dumped imports.

150. With regard to the contention of the interested parties that enhancement of capacity leading to high cost of production overheads is the cause of injury to the domestic industry, the Authority notes that performance of both the plants of the petitioners has been examined on standalone basis. Hissar Plant which operates at about 90% capacity also suffers loss. Odisha plant, after normation, to eliminate the effect of ramp up operation also shows losses because the prices are suppressed. Therefore, the contention of the interested parties is not correct.

151. With regard to the contention of the Korea Exporters that the export prices from Korea does not have price undercutting or suppression/depression effects the Authority notes that the injury to the domestic industry is required to be carried out on cumulative basis taking into account all dumped imports. However, on standalone basis also the prices of the subject goods exported from Korea is much below the cost of production and the non injurious price of the domestic industry leading to significant price underselling and price suppression as well as positive injury margin.

152. The above non-attribution analysis shows that no other known factors, other than the dumped imports, appear to have affected the domestic industry.

J.1 Factors establishing causal link

153. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated due to dumped imports from the subject countries. Therefore, the causal link between dumped imports and the injury caused to the domestic industry is established on the following grounds:

- a. The volume of dumped import from the subject countries has increased significantly over the injury investigation period with decline in POI as a result of imposition of China specific safeguard duty. The imports have shown further increase in post POI after the cessation of China specific safeguard duty. Import price has remained below the level of cost and has resulted in significant price suppression. Increase in import from subject countries have taken away the market share vacated by the countries attracting ADD.
- b. The landed price declined significantly in the POI resulting in significant decline in the selling price of the domestic industry leading to intensified losses.
- c. Increase in import volumes and reduction in the selling prices by the domestic industry adversely affected the profits, cash flow and return on investments of the petitioner domestic industry.

154. Therefore, the Authority concludes that the domestic industry suffers material injury and the injury has been caused by the volume and price effects of dumped imports from the subject countries.

K. Magnitude of Injury and injury margin

155. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority margin of injuries with respect to the importation of the subject goods from the subject countries have also been determined. For determination of injury margin the Authority has determined the Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry as per the procedures laid down in Annexure III of the Anti Dumping Rules. The interested parties have argued that for the purpose of determination of NIP the Authority should not grant a return higher than what is achieved by the DI during injury. The Authority notes that as per consistent practice the procedures laid down by Annexure III of the Anti Dumping Rules have been followed while determining Non Injurious Price.

156. The non-injurious price for the domestic industry determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margins of the subject goods exported

from the subject countries to India. The weighted average landed price of the exporters from the subject countries and their injury margins have been worked out as follows:

Country	Producer/Exporter	NIP	Landed Value	Injury Margin	IM	IM Ranges
		Rs/MT	Rs/MT	Rs/MT	%	%
China	All Exporters	****	****	****	****	5-15
Malaysia	All Exporters	****	****	****	****	5-15
Korea	All exporters	****	****	****	****	0-10

L. Post Disclosure Submissions of all interested parties:

157. The Authority issued a disclosure statement on 25th February 2015 disclosing essential facts of the case and inviting the comments of all interested parties. The comments of the interested parties have been examined as follows:

L.1 Submissions on behalf of M/s Bahru, Malaysia

158. Lakhmi Kumaran and Sridharan, on behalf of Bahru, Malaysia in their post disclosure submissions have reiterated their stand in their previous submissions on various issues in this investigation. The Authority notes that all those issues have already been addressed in the findings and therefore, not being repeated again for the sake of brevity. However, few additional issues raised by the exporter have been addressed hereunder as follows:

159. In its submissions the above exporter has argued that the Authority has resorted to in cherry-picking data in this investigation and the Authority appears to be unsure as to which data source to rely upon to continue this investigation against Malaysia as it has examined DGCI&S Data, IBIS data as well as DG Systems data in the disclosure statement. It has been further argued that neither the Designated Authority nor Applicant has clarified the basis of arriving at the import volume of 1584 MT from Malaysia during the POI. It has been argued that total import volume of the subject goods from Malaysia is only 1232.02 MT as compared to 1584 MT claimed in the application and the Applicant has inflated Malaysian import volume by including scrap in the import volume as well as those imports, which are already subject to anti-dumping duty. The import volume from Malaysia is much lower and below the *de-minimis* level of 3%. In this regard the Authority notes that it was clearly indicated in the disclosure that IBIS import data has been used for this investigation after comparing the same with DGCI&S data. DG Systems data has also been examined to validate the data used. Therefore, there is no confusion about the data source used as has been alleged. As far as the import volume from Malaysia is concerned, it was clearly brought out in the disclosure statement that the questionnaire response of Bahru clearly states that Bahru and its related companies alone had exported about 1360 MTs during the POI which is above 3% of total import volumes taking into account this volume from Malaysia, notwithstanding the facts that there could be other exporters from Malaysia. It is also noted that Bahru and its related Companies were exporting the subject goods prior to POI and ceased to export some time during the POI. Therefore, there could be exports from Malaysia by these exporters prior to the POI which could have landed in India during the POI leading to reporting of marginally higher import volume during POI due to the time lag in export from Malaysia and import into India. Therefore, the Authority holds that the import data relied upon in this finding and volume determination in respect of Malaysia are correct and the volume imported from Malaysia is above *de minimis*.

160. The exporter has again reiterated its argument that the Authority should have provided the transaction wise import data relied upon in the investigation to all interested parties and therefore, the present investigation is in violation of the principles of natural justice. In this connection the Authority notes that transaction wise import data obtained by the Designated Authority from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) is confidential in nature and does not belong to the category of information/evidence provided by an interested party. Therefore, the request for providing transaction wise import data obtained by the Designated Authority from DGCI&S for the purpose of the anti dumping investigation is inadmissible under the Anti Dumping Rules. Notwithstanding this it may be noted that the disclosure statement clearly mentions that IBIS import data has been used in the determinations and the transaction wise import data from IBIS submitted by the domestic industry has already been placed in the public folder by the domestic industry. The public folder has been accessed by this Law firm on several occasions on behalf of all their clients and they already have access to the import data used in this investigation. Therefore, the arguments of the exporter in this regard are not tenable.

161. Bahru has further reiterated its stand on the country of origin of the subject goods and argued that it does not provide any certificate of origin showing Malaysia as origin of the subject goods to any importer in India. In fact, a certificate of origin is only required when a preferential customs duty benefit is to be claimed under a free trade agreement, such as the India-ASEAN FTA. Bahru has already clarified that its exports do not qualify for such benefit under the India-ASEAN FTA. Therefore, the Designated Authority's conclusion that importers in India are clearing

subject goods showing Malaysian origin against certificates issued by Malaysian authorities is incorrect. In this regard the Authority notes that this issue has been dealt in the disclosure at length. It was also indicated that while whether the goods have been wrongly declared as of Malaysian origin and cleared under Indo-ASEAN FTA preferential duty arrangement is a matter of separate investigation by the concerned agencies/authorities, there is no denying the fact that the goods exported from Malaysia are not of Malaysian origin as per the rules of origin under the FTA. The Authority has not arrived at any conclusion on the issue of mis-declaration of the goods as alleged by the domestic industry as it is a matter of separate investigation by another Authority. Therefore, the arguments of the exporter in this regard are not tenable.

162. Bahru has further argued that they have been wrongly treated as non-cooperative though they have filed complete questionnaire response. In this regard the exporter has referred to Article 2.5 of ADA and Section 9A (c) of the Customs Tariff Act, 1975. The Authority notes that as per their own submission Bahru is not the manufacturer of the product and the manufacturers have not filed any questionnaire response. As per the policy of the Designated Authority individual treatment cannot be given unless both the producer and exporter are before the Authority. Therefore, the questionnaire response of Bahru has not been accepted for grant of individual treatment.

163. Bahru has further argued that if the Designated Authority still constructs normal value, parameters considered to construct normal value should be disclosed as there is no basis to keep these parameters confidential. Therefore, the Authority should disclose the international price of major raw materials and the reasonable margin of profit considered by it in constructing the normal value. In this regard the Authority notes that around 70% of the raw material cost is accounted for by Nickel and Stainless Steel Scraps. The international price of Nickel has been taken as the import price to the respective countries as reported in the World Trade Atlas for the period of investigation. The international price of SS Scrap has been taken from the Metal Bulletin (International Magazine) for the respective countries for the purpose of construction of Normal Values. A profit margin of 5% has been considered on cost of production minus interest cost to arrive at the Constructed Normal Values.

164. Bahru has argued the Designated Authority is incorrect in including these products types, which are not in commercial competition in the domestic market. Merely because Applicant is capable of producing these product types is not sufficient. In *Magnet Users Association v. Designated Authority* [(2003) 157 ELT 150 (Tri-Del)], the Hon'ble Tribunal has made it clear that in an anti-dumping investigation, grades of subject goods, which are not produced by the domestic industry have to be excluded from the product scope. In this regard it was clearly brought out in the disclosure that the domestic industry has in fact produced and sold Cold Rolled coils of higher width which is rolled out of the hot rolled coils thereby demonstrating that they have produced HR coils. Therefore, the arguments of Bahru in this regard are devoid of any merit.

165. With respect to injury and causal link determination the exporter has reiterated most of its arguments made earlier and the issues have already been addressed in the respective sections in the findings. The exporter has argued that the Authority should not have relied upon the Post POI data in the injury analysis. In this regard the Authority notes that the disclosure statement itself indicated that the POI import volumes were affected by the China specific Safeguard duty for over 6 month period during the POI and therefore, it was necessary to examine the trends thereafter to see whether the imports have increased substantially after cessation of the duty. Therefore, the objections of the exporter in this regard are not tenable.

L.2 Submissions on behalf of M/s Century Steel, Singapore

166. Lakhmi Kumaran and Sridharan, on behalf of Century Steel, Singapore, in their post disclosure submissions, have argued that despite the full participation, the Authority has incorrectly and illegally denied separate margin of dumping and margin of injury to the chain of producer (LISCO) and exporter (Century). In this regard the Authority notes that as per the consistent practice of the Authority all the exporters exporting the subject goods manufactured by a producer in the subject country are required to file the questionnaire response for grant of individual margin. Since only one out of the four exporters of the subject goods manufactured by LISCO was before the Authority individual margins could not be granted to the responding producer-exporter combination.

167. Apart from this individual treatment issue Century has also raised identical issues which have already been addressed with regards to the submissions made on behalf of M/s Bahru, Malaysia as above. Therefore, they are not being repeated again for the sake of brevity.

L.3 Submissions on behalf of the Importers

168. In their submissions on behalf of the importers represented by them M/s Lakshmi Kumaran and Sridharan have repeated most of the arguments as already addressed with regards to the submissions of Bahru, Malaysia and they are not being repeated for the sake of brevity.

169. Apart from these issues Importers have argued that it is clear from the price undercutting table provided in the Disclosure Statement that there is no price undercutting from Korea RP during POI. However, just to ensure that Korea is not excluded from the purview of anti-dumping duty, it seems the Authority has reduced the landed value of imports for Korea by considering concessional rate of duty in terms of CEPA. It has been argued that concessional rate of duties are a result of policy of the Central Government to promote bilateral trade between India and Korea. Had it not for the commitment of Central Government, there would not be any concessional rate of duty. Thus, the concessional rate of duties cannot be held to be a reason for dumping of subject goods and its effect should be excluded while determining the landed value of imports of subject goods from Korea RP. In view of the same, the Authority should terminate the investigation against imports from Korea RP. In this regard the Authority notes that price undercutting is not the only parameter for determination of injury and causal link. The Authority has already noted that the dumped imports from the subject countries have significantly suppressed/depressed the prices in the domestic market and therefore, price undercutting is not the appropriate indicator for determination of injury and causal links. In any case the injury and causal link has been examined cumulatively for all imports from the subject countries and lack of price undercutting from one country cannot be a reason to drop the investigation against that country as long as overall assessment of injury and causal link factors indicate existence of injury and causal link. Therefore, the arguments of the party in this regard have not been accepted.

170. In addition to the above M/s Athena Law Associates, in its submissions on behalf of the importers represented by them, while reiterating its submissions previously made before the Designated Authority have also raised the issue of providing the interested parties access to the transaction-wise import data used by the Authority. The Authority notes that IBIS data used by the Authority has already been provided to the interested parties in the petition itself and therefore, the interests of the interested parties have not been compromised in any manner. DGCIS data collected by the Authority has only been used for comparison purpose and the Rules do not require the Authority to share this data, obtained confidentially from DGCIS, to other interested parties.

L.4 Submissions on behalf of LISCO, China

171. LISCO, in its post disclosure submissions, has argued that the unit prices of most of the raw materials appear to have unit prices without significant variations, except for nickel-bearing pig iron. Therefore, the Authority should not have reached the conclusion that there was significant difference between the prices of major raw materials and should change its findings on this issue in the Final Findings. LISCO has further argued that they had exported 60.6% of their total exports of the subject goods to India through Century Steel Pte Ltd., Singapore and Century has also filed the questionnaire response. Therefore, the Authority should determine the export price based on the data pertaining to the above completed chain. In this regard the Authority notes that as per the information submitted by LISCO in its questionnaire response the unit price of major raw materials sourced from related and unrelated parties shows significant difference. Therefore, the conclusion reached by the Authority is in order.

172. As far as determination of export price is concerned, the Authority notes that as per the consistent practice of the Authority all the exporters exporting the subject goods manufactured by a producer in the subject country are required to file the questionnaire response for grant of individual margin. Since only one out of the four exporters of the subject goods manufactured by LISCO was before the Authority individual margins could not be granted to the responding producer-exporter combination.

L.5 Submissions on behalf of the Domestic Industry

173. The domestic industry, in its post disclosure submissions, has reiterated its stand on most of the issues. Other submissions made by the domestic industry have been addressed hereunder as follows:

174. The domestic industry has argued that the product under consideration should not have any restrictions in the form of length of coils or plates and as regards restrictions on width of the product the same should not be left unconditional. The domestic industry has argued that the consumers who require product of width upto 1650mm should not be allowed to import the product above 1650 mm, slit the same and substitute for their requirement of the product below 1650 mm. Any unregulated exemption from payment of ADD for widths above 1650 mm would lead to continued injury to the domestic industry. Therefore exemption should be given only to those consumers who in fact require material in wider width and who cannot use any material with width below 1650 under Section 25 of the Custom Act, 1962. As regards the length of the products is concerned, the anomaly in the initial description of the product under consideration has already been discussed in the relevant section and the anomaly has been removed. As far as the removal of restriction on the width and allowing end-use based exemption for is concerned, the Authority notes that such arguments cannot be accepted at this stage of the investigation as it involves significant change in the scope of the product under consideration.

175. The domestic industry has further submitted that since the product under consideration is produced and sold by various names, the Designated Authority may kindly specify in duty table that the product under consideration should attract duty regardless of alternate names used by the importers. Further, the domestic industry has submitted that since the product under consideration does not have dedicated customs code, the authority may kindly specify in duty table that the customs classification is indicative only. The Authority has taken note of this and the issue has been appropriately addressed in the finding.

176. The domestic industry has further submitted that the determination of NIP is inappropriate leading to unduly low protection to the domestic industry. The raw materials utilization should not necessarily be considered at the best achieved levels. Actual raw material and utilities consumption must be considered. The investment at Odisha should form the benchmark for determination of NIP. Further, if the Authority considers some production level as "reasonable, appropriate or necessary" for NIP determination, there is no basis for adopting some other production volume for determining weighted average NIP. The Authority notes that NIP has been determined as per the procedure laid down in Annexure III of the Anti Dumping Rules and no change in approach is required.

177. The domestic industry has further submitted that the Injury Margin should be calculated based on difference between NIP and lowest transaction price in the import data pertaining to that particular country. The practice of the Authority is to consider lowest import price in case of non-cooperating exporters. Thus, in a situation where all the exporters are non-cooperating or have selectively cooperated to such an extent that the Authority has denied individual dumping margin and injury margin, the treatment cannot be different. The Authority notes that since all the exporters from a particular country have been declared non-cooperative the NIP is compared with the weighted average landed value of all import transactions for determination of injury margin and therefore, the injury margin has been calculated appropriately.

178. The domestic industry has submitted that Anti dumping duty should be imposed only as fixed quantum in US Dollars. The Authority notes that considering the nature of the product and the fact that antidumping duties in all previous cases in steel products have been imposed in terms of fixed duties, it would be appropriate to recommend same form of duty in this case also.

M. Conclusions

179. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority, as recorded in this finding, the authority concludes that:

- i) The subject goods have entered the Indian market from the subject countries at prices less than their normal values in the domestic market of the exporting countries;
- ii) The dumping margins of the subject goods imported from the subject countries are substantial and above *de minimis*;
- iii) The domestic industry has suffered material injury and the injury has been caused to the domestic industry, both by volume and price effect of dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

N. Indian industry's interest & other issues

180. The interested parties have argued that the antidumping duties would adversely affect the downstream industry using HR flat products and impact the prices of the finished goods. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the subject goods to the downstream industry and the consumers.

O. Recommendations

181. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on various aspects of dumping, injury and causal links. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal links between dumping and injury to the domestic industry, in terms of the Rules laid down, and having established positive dumping margin against the subject countries, and having concluded that the domestic industry suffers material injury due to such dumped imports, the Authority is of the opinion that imposition of definitive measure is required to prevent injury being caused to the domestic industry.

182. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods, from the subject countries, in the form and manner described hereunder.

183. Having regard to the lesser duty rules the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive antidumping duty equal to the amount indicated in Col 9 of the duty table annexed herewith is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.

Duty Table

Sl.No	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Specification	Countries of origin	Countries of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measure	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7219 & 7210	Hot Rolled austenitic stainless steel flat products	ASTM Grade 304 (width Upto 1650mm and Thickness above 1.2 mm)	China PR	China PR	Any	Any	309	MT	US\$
2	-Do-	-Do-	-Do-	China PR	Any, other than the subject countries	Any	Any	309	MT	US\$
3	-Do-	-Do-	-Do-	Any, other than the subject countries	China	Any	Any	309	MT	US\$
4	-Do-	-Do-	-Do-	Malaysia	Malaysia	Any	Any	316	MT	US\$
5	-Do-	-Do-	-Do-	Malaysia	Any, other than the subject countries	Any	Any	316	MT	US\$
6	-Do-	-Do-	-Do-	Any, other than the subject countries	Malaysia	Any	Any	316	MT	US\$
7	-Do-	-Do-	-Do-	Korea RP	Korea RP	Any	Any	180	MT	US\$
8	-Do-	-Do-	-Do-	Korea RP	Any, other than the subject countries	Any	Any	180	MT	US\$
9	-Do-	-Do-	-Do-	Any, other than the subject countries	Korea RP	Any	Any	180	MT	US\$

184. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

185. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

J. K. DADOO, Designated Authority